कश्मीर घाटी में दुल्हन बाजार

काशी विश्वनाथ मंदिर आस्था का गलियारा

ओमिक्रॉन से निबटने की तैयारी

इंडिया टुडे

22 दिसंबर, 2021 50 रुपए

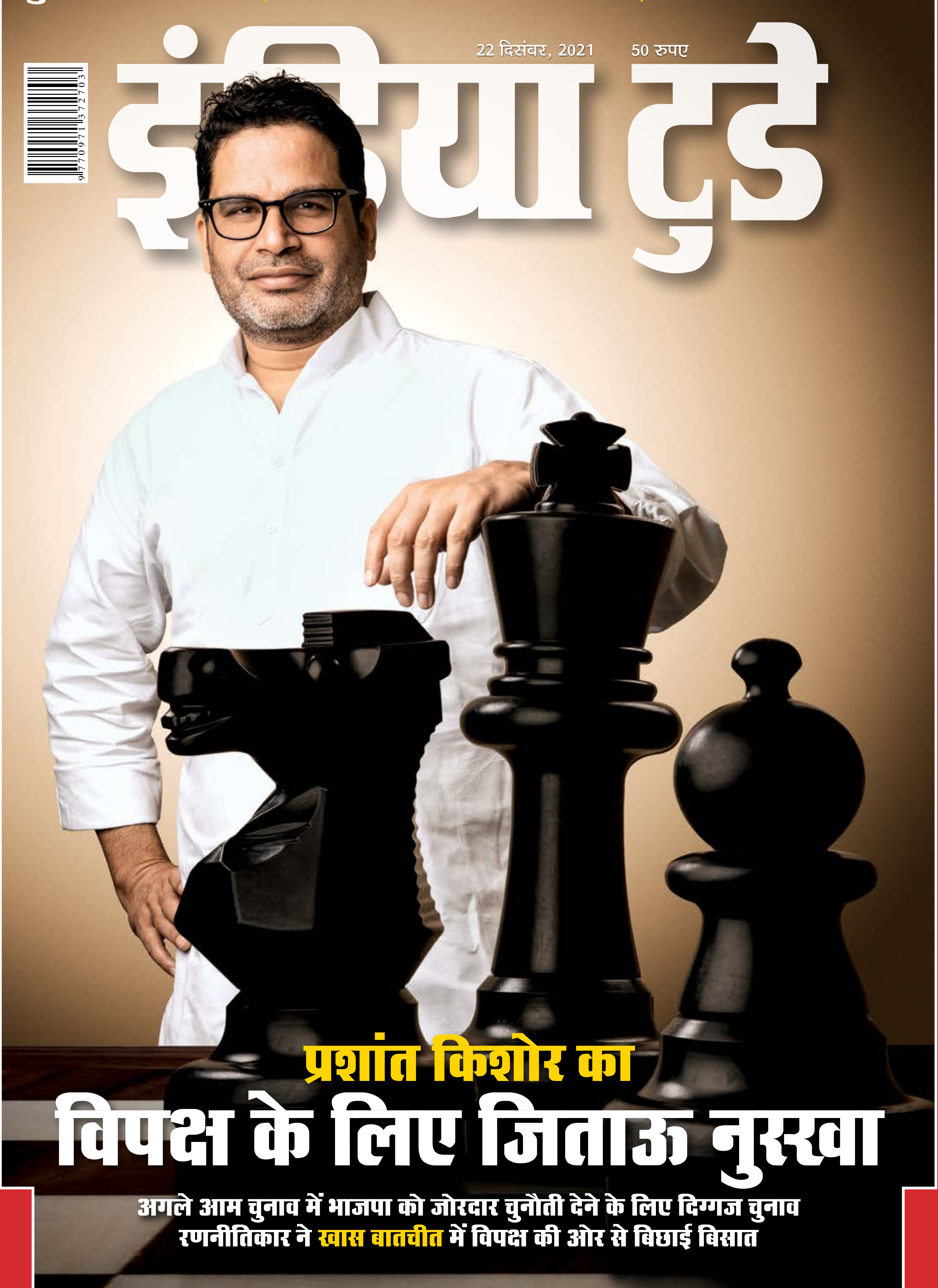

प्रशांत किशोर का
विपक्ष के लिए जिताऊ नुस्खा

अगले आम चुनाव में भाजपा को जोरदार चुनौती देने के लिए दिग्गज चुनाव रणनीतिकार ने **खास बातचीत** में विपक्ष की ओर से बिछाई बिसात

www.indiatodayhindi.in

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 62 (आवरण सहित)

OC

VISIT…

LANZAROTE
Caliente.com

हर दिन को दो
अपना 100%

100% शाकाहारी,
ऑर्गेनिक* ओमेगा, Bio-fermented* विटामिन
एवं प्राकृतिक* मिनरल के साथ प्रतिदिन संतुलित पोषण पायें

पतंजलि®
Nutrela™
NUTRITION

PRESERVATIVE FREE | SCIENTIFICALLY FORMULATED
NO ADDED COLOUR
Nutrela
DAILY ACTIVE
Nutrela
ORGANIC OMEGA
3, 6, 7 & 9
Nutrela
DAILY ENERGY
HERBAL | HOLISTIC | HEALTH

*Ingredients

Bio-fermented मल्टीविटामिन
शाकाहारी ओर्गेनिक ओमेगा
B-complex प्राकृतिक विकल्प

India's Most Certified
& Authentic Nutrition

ORGANIC INGREDIENTS | NATURAL 100% NATURAL | DAILY RDA 100% DAILY RDA | VEGETARIAN 100% VEGETARIAN | GMO FREE | GLUTEN FREE | PRESERVATIVE FREE | NO ADDED COLOUR | PLASTICIZER FREE | BIOFERMENTED INGREDIENTS

Ruchi
Ruchi Soya Industries Limited

Online Store: Amazon, Orderme app, www.nutrelanutrition.com
Retail Store: आपके नज़दीकी सभी पतंजलि चिकित्सालय, पतंजलि स्टोर और सभी प्रमुख स्टोर पर उपलब्ध।
www.nutrelanutrition.com; wecare@nutrelanutrition.com; Phone - 18601800180

प्रधान संपादक की कलम से

हमारी 19 मई, 2014 की आवरण कथा 'छा गए मोदी' में एक चश्माधारी, क्लीन-शेव्ड युवा जींस और टी-शर्ट में नरेंद्र मोदी के साथ कदमताल करता दिखाई दिया था. प्रशांत किशोर तब मोदी के प्रमुख कैंपेन मैनेजर थे. वे टेक्नोलॉजी में सिद्धहस्त करीब 1,000 वॉलंटियर की छोटी-सी सेना की अगुआई कर रहे थे, जिसने 3डी रैलियों, कॉलर ट्यून, 'चाय पे चर्चा' के जरिए अभूतपूर्व चुनावी हल्ला बोल दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की शैली सरीखे जनमत संग्रह को इस कदर हवा दी कि उसने उम्मीदवार मोदी को उछालकर सत्ता में स्थापित कर दिया. तब किशोर ने हमसे कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक अभियान ''मोदी लहर को कई मील आगे ले गया''. नेपथ्य के रणनीतिकार के लिए यह सही ही था कि उनकी तस्वीर हमारी कथा के आखिरी पेज पर नमूदार हुई.

मोदी सरकार ने सत्ता में एक दशक का तीन-चौथाई निशान पार कर लिया है. एक उल्लेखनीय बदलाव यह आया है कि किशोर अब उन लोगों को सलाह दे रहे हैं जो मोदी सरकार के निष्ठुर शत्रु हैं. भाजपा से उनके रिश्ते टूटने के कारण पूरी तरह साफ नहीं हैं पर उनकी आज की राजनीति को प्रभावित करते लग रहे हैं. मायावी गुरिल्ला योद्धा की तरह वे हर उस राज्य में प्रकट हो गए जहां भाजपा ने पैठ बनाने की कोशिश की, लेकिन हमेशा विपक्ष के पाले में थे, चाहे पंजाब रहा हो, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना. उन्होंने कांग्रेस, वाइएसआर कांग्रेस, आप, द्रमुक और जद (यू) (जब वह भाजपा के साथ गठबंधन में नहीं थी) के लिए कैंपेन की योजनाएं बनाई हैं. 2017 का उत्तर प्रदेश चुनाव, जिसमें उन्होने कांग्रेस और सपा को सलाह दी थी, बिरला झटका था. 2021 का पश्चिम बंगाल चुनाव, जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी की टीएमसी के लिए रणनीति बनाई, उनकी सबसे बड़ी फतह थी. पिछले साल 21 दिसंबर को, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा के एक दिन बाद, उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा दहाई का आंकड़ा पार करने के लिए हाथ-पैर मार रही होगी. पांच महीने के थकाऊ चुनाव अभियान के बाद उनकी भविष्यवाणी हैरतअंगेज ढंग से सही साबित हुई. लेकिन यह इस हफ्ते 44 वर्षीय किशोर के हमारे आवरण पर होने का अकेला कारण नहीं है. भारतीय राजनीति ने मंच पर और उसके नीचे रंगबिरंगी सियासी शख्सियतों का पूरा काफिला देखा है. इनमें गॉडमैन, दरबारी विदूषक, बाहुबली, पत्नियां, विधवाएं, राजकुमार और नाम भर के महाराजा हैं. किशोर की तरह कभी कोई नहीं हुआ. एक दशक से भी कम वक्त में ऊंचे स्ट्राइक रेट के साथ वे विभिन्न राजनैतिक दलों और नेताओं के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं. आज भी उनके पास एक योजना है.

फाल्गुनी नायर: सौंदर्य की नायिका
भारत कैसे कर रहा है समुद्र मंथन की तैयारी
कितना गंभीर है ओमिक्रॉन का खतरा
इंडिया टुडे
भाजपा
चुनौती 2022

15 दिसंबर, 2021 का आवरण

पिछले हफ्ते हमारी आवरण कथा 'भाजपा: चुनौती 2022' आपको अगले साल के चुनावों के लिए कमर कस रही भाजपा की विशालकाय प्रचार मशीनरी के भीतर ले गई थी. सत्ता में साढ़े सात साल बाद भी मोदी सरकार गंभीर सत्ता विरोधी भावना से दोचार नहीं है. असल में, पॉपुलर नैरेटिव पर उसका कब्जा है. अगस्त में हमारे ताजातरीन देश का मिजाज सर्वे से पता चला कि अगर आज चुनाव हों तो भाजपा जीतेगी, जो महामारी के बहुत-से झटकों और तहस-नहस करती आर्थिक गिरावट को देखते हुए यह बहुत बड़ी सफलता है. उधर विपक्ष अब भी बंटा हुआ है और भाजपा के खिलाफ वैकल्पिक नैरेटिव पेश नहीं कर पा रहा है. यहीं किशोर का प्रवेश होता है. वे 2024 में भाजपा को प्रभावी ढंग से चुनौती दे सकने वाले राजनैतिक संगठनों को साथ लाने में मदद कर रहे हैं. यह महत्वाकांक्षी पहल, जो किशोर की अब तक की सबसे बड़ी पहल है, अब से दो साल बाद राजनैतिक रणक्षेत्र की दशा-दिशा तय कर सकती है.

हमारी आवरण कथा 'प्रशांत किशोर का विपक्ष के लिए जिताऊ नुस्खा' के लिए ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर (पब्लिशिंग) राज चेंगप्पा ने राजनैतिक रणनीतिकार से दो घंटे से ज्यादा बात की. किशोर कुशाग्र राजनैतिक पर्यवेक्षक की तरह उभरकर आए, जो लफ्फाजी पर नहीं जाते, अपने विरोधियों की शक्तियों को कम करने नहीं आंकते या न ही अपने पक्ष के फायदों को बढ़ा-चढ़ाकर आंकते हैं. उन्होंने विपक्ष की एक सबसे अहम समस्या पर उंगली रखी—खराब ढंग से काम कर रही कांग्रेस जो राजनैतिक स्थान को लहूलुहान कर रही है पर स्पष्ट संकेत समझने से इनकार करती है. किशोर आंकड़ों के आधार पर 1984 में मिले लोकसभा में आखिरी बहुमत के बाद से ग्रैंड ओल्ड पार्टी के लगातार पतन का विश्लेषण करते हैं. तब 40 फीसद वोट हिस्सेदारी से अब यह महज 19 फीसद पर सिकुड़ गई है. इससे भी अहम यह कि 2012 से उसने जो 50 चुनाव लड़े, उनमें से 90 फीसद हारी है. 2014 के लोकसभा चुनाव में उसने भाजपा के खिलाफ लड़ी हर 100 सीटों में से महज छह जीतीं. 2019 में उसका स्ट्राइक रेट घटकर मात्र 4 पर आ गया.

किशोर कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने जन अपील बढ़ाने के लिए अपनी मूल हिंदुत्व की रणनीति में चरम राष्ट्रवाद और जनकल्याणवाद और जोड़ लिया है. उन्हें एहसास हो गया है कि धार्मिक ध्रुवीकरण उन्हें यहां तक ही ले जा सकता है. किशोर मानते हैं कि धार्मिक मुद्दों पर 50-55 फीसद से ज्यादा ध्रुवीकृत कर पाना असंभव है. भाजपा को वोट देने वाले हरेक हिंदू पर एक दूसरा हिंदू होगा जो उसे वोट नहीं देगा.

किशोर को शक है कि विपक्षी दलों का जमावड़ा भर कामयाबी का पक्का नुस्खा हो सकता है. भाजपा को चुनौती देने के लिए वे चार चीजें बेहद जरूरी मानते हैं—चेहरा, नैरेटिव, एकजुट विपक्ष और चुनाव मशीनरी जिसमें भाजपा के संदेशों और व्यूहरचनाओं को जवाब देने के लिए त्वरित प्रत्युत्तर व्यवस्था भी शामिल है. 2022 के विधानसभा चुनावों को वे 2024 के आम चुनाव के सेमीफाइनल की तरह नहीं देखते. कामयाब नेताओं में वे तीन गुणों की पहचान करते हैं—बुद्धिमता, चरित्र और, सबसे ऊपर, साहस.

राजनैतिक नेताओं के ब्रांड विकसित कर चुके रणनीतिकार के लिहाज से यह जरा असामान्य बात है कि किशोर संयुक्त विपक्ष के नेता की खोज को 'गैरजरूरी कवायद' करार देते हैं. वे कहते हैं कि 1970 के दशक में इंदिरा गांधी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के उभार या पांच साल बाद राजीव गांधी की भारी जीत के बाद वी.पी. सिंह के उभार की भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता था. नेता होना भी जरूरी नहीं है क्योंकि बीते कुछ सालों के तीन सबसे अहम आंदोलनों—नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस, जमीन अधिग्रहण कानून और तीन कृषि कानूनों के खिलाफ—का कोई बड़ा नेता नहीं था.

किशोर खुद को खाकसार मानते लगते हैं और राजनैतिक रणनीतिकारों को 'महिमामंडित वाक्पटु श्रोता' कहते हैं, ''हम जो सुनते हैं उसका अर्थ निकाल सकते हैं और उसे सुसंगत रणनीति में बदल सकते हैं'' लेकिन काम पर भी उनका उतना ही ध्यान है. वे हमें बताते हैं, ''मेरी इच्छा यह है कि हम एक ऐसा राजनैतिक तानाबाना जुड़ता देख सकें जो असरदार हो, जो उस 60 फीसद जगह को मजबूत करता हो जो गद्दीनशीन निजाम के साथ नहीं है.''

चेंगप्पा के मुताबिक, प्रशांत किशोर का कोई खास एजेंडा हो सकता है, पर वे राजनैतिक तबके को तटस्थ ढंग से देख सकते हैं. वे कहते हैं, ''जो बात आपको प्रभावित करती है, वह स्पष्टता और वह डेटा है जो वह अपने तर्क और रणनीति को सबूत के तौर पर पेश करते हैं. स्वस्थ विपक्ष जीवंत लोकतंत्र की पूर्वशर्त है. यही किशोर और विपक्ष की प्रासंगिकता की दिशा में यात्रा को देखना कहीं ज्यादा अहम बना देती है.''

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे
www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादकः अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सनः कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टरः राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसरः मनोज शर्मा
एडिटरः सौरभ द्विवेदी
सीनियर एडिटरः मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटरः शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटरः मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरोः पुष्यमित्र (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटरः नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टरः चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टरः असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटरः बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंटः यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चरः प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चरः सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफः अभिनव पुगला

एसोसिएट पब्लिशरः विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेडः सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजरः जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजरः मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरू)
डिप्टी जनरल मैनेजरः इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसरः विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजरः दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजरः विपिन बग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजरः राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजरः एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजरः पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

वर्षः 36; अंकः 4; 16-22 दिसंबर, 2021; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोनः 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजेंः** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवाः** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोनः दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्सः (0120) 4078080. ई-मेलः wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालयः** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालयः** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोनः 022-66063355 फैक्सः 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालयः** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोनः 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरू-560 025 फोनः 2212448, 226233, टेलेक्सः 0845-2217 INTO IN. फैक्सः 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालयः एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादकः राज चेंगप्पा**

भीतर

सुर्खियां
स्मृति शेषः
योद्धा जनरल
पेज 5

भारत-रूसः द्विपक्षीय करार,
बहुपक्षीय समीकरण
पेज 7

फुरसत
पुस्तक अंशः संशोधन
प्रस्ताव वापस
पेज 58

सवाल-जवाब/नमिता गोखलेः
करुणा बड़ी कारसाज है
पेज 60

बंदीप सिंह

आवरण कथा

14 भाजपा को चुनौती का प्लान

चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने एक एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में 2024 के आम चुनाव में भाजपा को चुनौती देने की खातिर विपक्ष के लिए तैयार गेमप्लान की बातें साझा कीं.

ओमिक्रॉन

30 असर का इंतजार

ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है लेकिन अब तक इससे गंभीर लक्षण या मौत जैसी बात सामने नहीं आई है.

नगालैंड

40 शांति पर ग्रहण

14 नगा लोगों के मारे जाने की घटना ने अशांत नगालैंड में सुरक्षाबल और केंद्र सरकार को रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है.

कश्मीर के कुंआरे

52 घाटी का दुल्हन बाजार

जीवनसाथी तलाश रहे घाटी के अधेड़ों के लिए दलाल ला रहे हैं दूर-दराज की दुल्हनें.

काशी विश्वनाथ मंदिर

46 आस्था का गलियारा

नए काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर को भाजपा ऐसे समय पर खोलना चाहती है ताकि इसका चुनावी फायदा मिले.

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
7303086006 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करेंः wecare@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण फोटोः **बंदीप सिंह**
(शतरंज के मोहरे, साभारः वसंत विहार क्लब, दिल्ली)

पाठकों के लिए सूचनाः कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

सुर्खियां

भारत-रूस संबंध: द्विपक्षीय करार, अनेकपक्षीय समीकरण
पेज 7

पंजाब सबको साधते आगे बढ़ते चन्नी
पेज 8

बिहार: भ्रष्टाचार पर जोरदार वार
पेज 10

असम: भीड़ का कानून
पेज 12

स्मृति शेष

जनरल बिपिन रावत
1958-2021

जांबाज जनरल

संदीप उन्नीथन

बिपिन रावत
BIPIN RAWAT

बंदीप सिंह

जनरल बिपिन रावत 63 साल के थे जिनका 8 दिसंबर को हेलिकॉप्टर हादसे में निधन हो गया, वे भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) और सबसे लंबे समय तक सेवारत रहे जनरल थे. इस साल 31 दिसंबर को वे जनरल के रूप में सेवा के अभूतपूर्व पांच साल पूरे कर लेते—तीन साल तक भारत के 26वें सेनाध्यक्ष के रूप में और दो साल देश के पहले सीडीएस के रूप. पिछले दिसंबर में उन्होंने उन्होंने जनरल के.एस. थिमैया का चार साल जनरल के रूप में कार्यरत रहने का रिकॉर्ड तोड़ा तो उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं था. सेनाध्यक्षों की समिति के स्थायी अध्यक्ष; सैन्य मामलों के विभाग के सचिव और तीनों सेनाओं की ऑपरेशन कमानों जैसे अंडमान व निकोबार कमान और स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमान के प्रमुख होने की अपेक्षाओं के बोझ का मतलब था कि इस तरह की व्यक्तिगत उपलब्धियां उनके लिए किसी हद तक तुच्छ थीं. जनरल रावत के लक्ष्य बड़े थे. रहते तो वे अगले साल तक तीनों सेनाओं की मौजूदा 17 एकल-सेवा कमानों को मिलाकर गठित की जाने वाली भारत की पहली फोर-थिएटर कमान के गठन की निगरानी करते. उन्हें तीनों सेवाओं के लिए साजो-सामान खरीद प्रक्रिया को व्यवस्थित कर प्राथमिकताओं को नए सिरे से तय करने के लिए एकीकृत क्षमता विकास योजना भी शुरू करनी थी.

लोग रावत से प्यार करें या नफरत पर उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था. विभाजन रेखा के अलग-अलग पक्षों से देखे जाने के आधार पर उन्हें या तो दूरदर्शी सुधारक देखा जाता था या परंपरा तोड़ने वाले के रूप में. कारण यह था कि रावत चरम उत्साह के साथ सैन्य सुधारों के प्रयास करते थे और इस क्रम में अक्सर अन्य दो सेवाओं के बारे में उग्र टिप्पणियां करते थे जिससे सैन्य अधिकारियों को परेशानी होती थी. वे सुनार की कोमल चोटों की आदी व्यवस्था में हथौड़ा चलाने वाले लुहार थे. 1962 के भारत-चीन युद्ध की आपदा के बाद से, भारत के राजनैतिक वर्ग ने सशस्त्र बलों को उनके हाल पर छोड़ दिया. पर जनरल रावत का कार्यकाल ऐसी सरकार के दौरान रहा जो रक्षा सुधार की आवश्यकताओं के बारे में पूरी तरह से जागरूक थी. दिसंबर 2019 में भारत के पहले सीडीएस के रूप में उनकी नियुक्ति यूं ही नहीं हुई—नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में सशस्त्र बलों के लंबे समय से लंबित सुधारों की शुरुआत की. उन्हें जनरल रावत में वांछित बदलाव करने वाला व्यक्ति मिल भी गया था.

उनकी आकस्मिक मृत्यु से अधूरे कार्यों की एक लंबी सूची बन गई है. ऐसी आकस्मिक स्थिति 1994 में जनरल बिपिन जोशी की अचानक मृत्यु के बाद पहली बार सामने आई है. यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि उनकी जगह कौन लेगा, लेकिन अगर सरकार वरिष्ठतम सेवा प्रमुख की नियुक्ति की परंपरा का पालन करती है, तो वह वर्तमान सेना प्रमुख जनरल मनोज नरवणे की ओर रुख कर सकती है. सीडीएस के रूप में नियुक्त होने वाले नए व्यक्ति के लिए सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ाना असंभव तो नहीं लेकिन कठिन कार्य होगा, क्योंकि बहुत से सुधारों को पहले सीडीएस के साथ ही जोड़ कर देखा जा रहा था. पूर्व सेना प्रमुख जनरल वी.पी. मलिक जनरल रावत को एक “दृढ़, स्पष्टवादी और सीधे” व्यक्ति के रूप में याद करते हैं. वे कहते हैं, “बिपिन के पास असंदिग्ध सैनिक गुण, सैन्य ज्ञान और सीडीएस पद के लिए आवश्यक अनुभव था.”

जनरल रावत का जन्म एक सैन्य परिवार में हुआ था. उनके पिता, लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत, 1988 में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे. रावत को 1978 में उनके पिता की रेजिमेंट, 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं रेजिमेंट में ही कमिशन मिला था. सेवा में रहते हुए, वे दो बार बाल-बाल बचे थे. 1993 में एक युवा मेजर के रूप में वे जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से गोलीबारी में घायल हुए थे. वर्षों बाद 2015 में जब वे नगालैंड स्थित 3 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे तब एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में उन्हें मामूली चोटें आई थीं. फील्ड कमांडर के रूप में उनकी आक्रामकता ने उन्हें सेवाकाल में जल्दी ही अलग पहचान दिला दी थी.

जनरल बिपिन रावत ने सेना प्रमुख के पद पर आक्रामकता और बतौर पहले सीडीएस सुधारवादी भावना का सूत्रपात किया

2008 में कांगो में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना दल का नेतृत्व करने वाले ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ बल प्रयोग का आदेश दिया था. नगालैंड में जब वे कोर कमांडर थे, तो उनके ही अधीन एक कमांडो यूनिट ने म्यांमार में घुस कर एनएससीएन (के) शिविरों पर छापेमारी की थी. यह छापामारी नगा विद्रोहियों की ओर से भारतीय सेना के 18 सैनिकों की हत्या के प्रतिशोध में की गई थी. शायद इसी आक्रामकता ने उन्हें तब मदद की जब 2016 में सरकार ने उन्हें भारत के 26वें सेना प्रमुख के रूप में तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर वरीयता देते हुए चुना था. सेना प्रमुख के रूप में रावत ने ज्यादा सैनिकों वाली भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या घटाने और अर्थहीन संगठनों को समाप्त कर संसाधन बचाने जैसे सुधारों के बारे में बोलना शुरू किया. उनकी योजनाएं इस तथ्य पर आधारित थीं कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना अपने बजट का 80 प्रतिशत से अधिक वेतन, ईंधन, गोला-बारूद और आपूर्तियां खरीदने पर खर्च कर रही थी और नए उपकरण खरीदने के लिए उसके पास बहुत कम पैसा बचता है. उन्होंने ‘एकीकृत युद्धक समूह’ नामक नई युद्धक संरचनाओं की तैनाती की प्रक्रिया भी शुरू की.

रावत अपने फील्ड कमांडरों पर अल्प सूचना पर युद्ध लड़ने की तैयारियों का दबाव रखते थे. 2001 में पाकिस्तान के साथ 10 महीने के ऑपरेशन पराक्रम गतिरोध के बाद सेना की ‘कोल्ड स्टार्ट’ युद्ध रणनीति विकसित हुई थी जिसमें वांछित है कि सेना कुछ घंटों के नोटिस पर युद्ध करने की स्थिति में रहे. संभवत: ये ही कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का प्रिय बनाते थे. डोभाल भी पौड़ी गढ़वाल जिले के सैन्य परिवार से हैं. जनरल रावत के सेना प्रमुख तथा सीडीएस रहते दक्षिण-पश्चिमी, पूर्वी और मध्य कमानों के जीओसी-इन-सी के रूप में तैनात रहे लेफ्टिनेंट जनरल अभय कृष्ण (सेवानिवृत्त) उन्हें दूरदर्शी मानते हैं.

सीडीएस के रूप में जनरल रावत ने वायु सेना के महंगे लड़ाकू विमानों के आयात पर सवाल उठाए और विचार किया कि क्या विशाल विमानवाहक खरीदने की तुलना में नौसेना के बजट को बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है. जनरल के तौर पर बिताए पांच वर्षों ने उन्होंने कई दुश्मन बना लिए थे. सैन्य दिग्गजों की बिरादरी के कुछ वर्ग उन्हें नापसंद करते थे और सैन्य पेंशन बिल में कटौती पर उनके बयानों के प्रति शत्रु भाव रखते थे. जनरल रावत इससे बेफिक्र रहते थे. एक बार मजाक में उन्होंने कहा था कि “दोस्त आसानी से बन जाते हैं, लेकिन दुश्मन हमें सतर्क रखते हैं.” उनका मानना था कि उनके प्रति घृणा का अधिकांश भाग ऐसी व्यवस्था की ओर से आता है जो जड़ता से प्यार करती है. उनका असामयिक निधन यथास्थितिवादियों की जीत का संकेत हो सकता है. ■

त्वरित शिखर सम्मेलन
6 दिसंबर को हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ

रोनू मेहता/गेट्टी इमेजेज

भारत-रूस संबंध

द्विपक्षीय करार, बहुपक्षीय समीकरण

संदीप उन्नीथन

नई दिल्ली में 6 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले तो दोनों की देहभाषाएं गर्माहट भरी और मुस्कान अनौपचारिक थीं. यह दोनों नेताओं के बीच पिछले दो साल में पहली निजी मुलाकात थी. अक्तूबर, 2018 को पुतिन के पिछले दौरे के दौरान, सार्स कोव-2 वायरस का नामकरण भी नहीं हुआ था और वह चीन में चमगादड़ों की गुफा में ही घूम रहा था, तब भारत के सामने विवादित सीमा पर तैनात हो रहे सैन्य ट्रकों से ज्यादा अहम कुछ नहीं था और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी दूसरी पारी को लेकर आश्वस्त थे.

पिछले दो वर्षों की घटनाओं ने भारत-रूस संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है. क्रीमिया पर कब्जे की घटना के बाद 2015 में अमेरिका ने रूस पर दबाव बढ़ा दिया, जिससे रूस की चीन से नजदीकी बढ़ गई. यह साझेदार नई दिल्ली के लिए रणनीतिक मामलों को जटिल बनाती है, क्योंकि चीन से भारत के संबंध वर्तमान में चार दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर हैं. दोनों पक्षों ने अभी तक उन हजारों सैनिकों, टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को वापस नहीं बुलाया है, जिन्हें वे पिछले साल मई में पूर्वी लद्दाख में एलएसी (वास्तविक नियंत्रण रेखा) पर ले गए थे. भारत और रूस शक्तिशाली राष्ट्रों के इस जटिल चतुर्भुज में अपने संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं. नई दिल्ली मॉस्को और वॉशिंगटन दोनों को रणनीतिक साझेदारों के रूप में देखता है—वे अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों के दो सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता भी हैं. 2017 के बाद से, अमेरिका की सीएएटीएसए (काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस ऐक्ट) नीति के तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का जोखिम होने के बावजूद रूस से भारत के हथियारों के आयात जारी रहा—भारत ने 2018 में अमेरिकी विरोध के बावजूद पांच एस-400 लंबी दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली खरीदी. हालांकि, इसकी वजह से अब तक प्रतिबंध लगाए नहीं गए हैं. इस बारे में कारोबारी मामले भी भूमिका निभा रहे हैं—अमेरिका को उम्मीद है कि भारत उससे हेलिकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल और टोही विमान खरीदेगा, जिसकी अनुमानित कीमत 10 अरब डॉलर (करीब 75,500 करोड़ रुपए) है.

राष्ट्रपति पुतिन ने दिल्ली में बिताए समय की तुलना में मॉस्को से नई दिल्ली की हवाई यात्रा में अधिक समय बिताया. यह शिखर सम्मेलन उनकी सबसे छोटी यात्राओं में से एक, पांच घंटे से भी कम समय तक चला. लेकिन दो साल में केवल उनकी दूसरी विदेश यात्रा के हासिल का महीनों तक अध्ययन किया जाएगा, खासकर जब से दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 'टू प्लस टू' संवाद प्रारूप के तहत पहली बैठक भी हुई. पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने शिखर यात्रा को बेहद प्रतीकात्मक बताया. वे कहते हैं, ''कहना होगा कि अमेरिका से हमारे संबंध किसी भी तरह से रूस के साथ हमारे संबंधों से जुड़े नहीं हैं. यह (नई दिल्ली के) चीन के लिए संकेत है—आखिर इस टू प्लस टू डायलॉग का मकसद क्या है?''

> **बैठक का सबसे ठोस परिणाम 10 सालों के लिए सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर भारत और रूस के बीच समझौता है**

इसका सबसे ठोस परिणाम 2021-31 तक सैन्य तकनीकी सहयोग के लिए एक दशक लंबे कार्यक्रम पर एक समझौता था. इसके साथ, नई दिल्ली ने संकेत दिया है कि मॉस्को के साथ उसके सैन्य संबंध अमेरिकी प्रतिबंधों के अंदेशे के असर से अछूते हैं. अन्य परिणाम कुछ हद तक कम थे. अमेठी में एक आयुध कारखाने में 6,00,000 एके-203 असॉल्ट राइफल बनाने के लिए वास्तव में हस्ताक्षरित एकमात्र सौदा 70 करोड़ डॉलर (करीब 5,200 करोड़ रुपए) का था.

इस अवसर के लिए कई बड़े सौदों पर हस्ताक्षर नहीं किए गए. चार रीफर्बिश्ड किलो-क्लास पनडुब्बियों के लिए रूसी प्रस्ताव अब वार्ता से बाहर है क्योंकि भारतीय नौसेना उन्हें नहीं चाहती है. शिखर वार्ता में 3 अरब डॉलर (करीब 22,600 करोड़ रुपए) से अधिक की दूसरी रूसी नौसेना अकुला-श्रेणी की परमाणु संचालित लड़ाकू पनडुब्बी पर भी चर्चा नहीं हुई. विश्लेषक केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई नई ऊर्जा डील या यहां तक कि डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग समझौता क्यों नहीं किया गया—क्या यह नौकरशाही या सौदेबाजी में फंसा या भारत, अमेरिका से सीधे उलझने के मूड में नहीं था.

मॉस्को स्थित थिंकटैंक सेंटर फॉर एनालिसिस ऑफ स्ट्रैटजीज ऐंड टेक्नोलॉजीज के निदेशक रुस्लान पुखोव कहते हैं, ''शिखर सम्मेलन भारत के लिए कूटनीतिक जीत है. रूस-चीन तालमेल के संदर्भ में और भारतीय कंपनियों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों को रोकने के लिए मोदी ने पुतिन के साथ अच्छे संबंध बनाए.'' उनका कहना है कि अमेरिकी दबाव ने भारत को ''रूस के लिए दोगुना महत्वपूर्ण'' बना दिया है, यही वजह है कि मॉस्को अब प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए पहले से कहीं अधिक तैयार है. यह भारत के रक्षा प्रतिष्ठान के लिए इससे ज्यादा अनुकूल बात कुछ हो नहीं सकती. ■

पंजाब

सबको साधते आगे बढ़ते चन्नी

अनिलेश एस. महाजन

अमृतसर के खौली गांव के रहने वाले गुरिंदर सिंह के घर 6 दिसंबर की रात एक वीवीआइपी मेहमान आया—वह और कोई नहीं बल्कि चरनजीत सिंह चन्नी थे. गांव के आकस्मिक दौरे पर आए पंजाब के मुख्यमंत्री ने अचानक गुरिंदर के साधारण से घर में ही रात का खाना खाने का फैसला किया. वहां पहुंचने पर उन्हें बैठने को खाट दी गई, लेकिन चन्नी उस पर बैठने के परिवार के आग्रह को टालते हुए नीचे फर्श पर ही बैठे और वहीं मक्खन से तर 'सरसों दा साग और मक्की दी रोटी' का भोजन किया. इससे पहले दिन में, चन्नी ने अमृतसर शहर के जोरा फाटक इलाके में एक राजनैतिक कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां उन्होंने विरोध-प्रदर्शन कर रहे निचले तबके के सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात सुनने के लिए अपना सुरक्षा घेरा तोड़ दिया था. इसी तरह, 28 नवंबर को जब वे रोपड़ जिले के मोरिंडा गांव स्थित अपने घर गए तो कई बच्चों को साथ में हेलिकॉप्टर की सवारी पर ले गए थे.

ये ऐसे दृश्य हैं जो पंजाब की राजनीति में लोगों ने काफी समय से नहीं देखे थे. ये लोग राज्य के पहले दलित मुख्यमंत्री 58 वर्षीय चन्नी को अपने पूर्ववर्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह के बिल्कुल विपरीत मानते हैं. ज्यादातर चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में अपने फार्महाउस से अपनी सरकार चलाने वाले जाट सिख और पटियाला के पदवीधारी महाराजा अमरिंदर की आलोचना अक्सर लोगों से दूर रहने वाले मुख्यमंत्री के रूप में की जाती थी. दूसरी ओर, चन्नी खुद को एक ऐसे प्रशासक के रूप में पेश कर रहे हैं जो अपने लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध हैं.

अमरिंदर ने भले ही मुख्यमंत्री पद से अचानक हटाए जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन कांग्रेस में उनके कई वफादार हैं जो चन्नी को परेशान कर सकते हैं. खतरे से वाकिफ नए मुख्यमंत्री व्यवस्थित तरीके से इन लोगों का सामना कर रहे हैं और उन्हें राहुल गांधी का भी समर्थन प्राप्त है. अमरिंदर के ऐसे ही एक वफादार पटियाला के मेयर संजीव शर्मा बिट्टू 25 नवंबर को बहुमत खो बैठे तो उन्हें निलंबित कर दिया गया. इसके बाद राज्य सरकार ने अमृतसर, बटाला और लुधियाना में शहर सुधार ट्रस्ट के प्रमुखों को हटा दिया. अमरिंदर की पत्नी और पटियाला की सांसद परनीत कौर को 'पार्टी विरोधी' गतिविधि के लिए नोटिस दिया गया है, जबकि कैप्टन के खेमे के अन्य सांसदों—जी.एस. औजला, मोहम्मद सादिक, मनीष तिवारी और संतोख सिंह चौधरी—पर कांग्रेस निगाह रख रही है.

असंतुष्टों से त्रस्त पार्टी इकाई में चन्नी की राह आसान बनाने के लिए कांग्रेस ने 6 दिसंबर को राज्य के दो नेताओं, पूर्व अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ और राज्यसभा सदस्य प्रताप सिंह बाजवा, को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रमुख जिम्मेदारियां सौंपी है. जाखड़ को जहां अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया, तो बाजवा घोषणापत्र समिति के प्रमुख होंगे. अजय माकन स्क्रीनिंग कमेटी का नेतृत्व करेंगे और अंबिका सोनी चुनाव समन्वय समिति की अध्यक्ष होंगी. अभियान दल में इन दिग्गजों की उपस्थिति का उद्देश्य चन्नी और सिद्धू दोनों को चुनाव संबंधी फैसलों में एकाधिकारी बनने से रोकना है.

अमरिंदर खेमे के खिलाफ लड़ाई में चन्नी ने सिद्धू को अपने साथ लेकर उससे निपटने की कोशिश की है. लेकिन उन्होंने सिद्धू के लिए भी बहुत जगह नहीं छोड़ी है

अमरिंदर और उनके शासन पर लगातार हमला करके चन्नी उम्मीद कर रहे हैं कि इससे कांग्रेस शासन के खिलाफ विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे मुद्दों—जैसे कुशासन, भ्रष्टाचार, अवैध शराब व्यापार और अवैध रेत खनन आदि—का असर कम कर सकेंगे. उनकी चुनौती न केवल सत्ता-विरोधी लहर पर अंकुश लगाने की है बल्कि खुद को पंजाब में कांग्रेस का भावी नेता साबित करने की भी है. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के रूप में पार्टी के पास पहले से ही मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं. अन्य उम्मीदवारों में उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा, कैबिनेट मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा और प्रताप बाजवा शामिल हैं. ये सभी सिद्धू की ही तरह जाट सिख नेता हैं जो चन्नी की किसी बड़ी गलती पर वार करने का मौका नहीं चूकेंगे.

अमरिंदर खेमे के खिलाफ लड़ाई में चन्नी ने सिद्धू को साथ लेकर उससे निपटने की कोशिश की है. सिद्धू ने शराब की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, कथित रूप से शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के कुछ नेताओं के नियंत्रण वाले व्यापार सिंडिकेट और साल 2015 की बेअदबी की घटनाओं में आगे की जांच को राज्य सरकार की ओर से प्राथमिकता न देने जैसे कई मुद्दों पर चन्नी को घेरने की कोशिश की थी. लेकिन चन्नी ने चतुराई से यह कहते हुए पलवार कर दिया कि ''मैं गरीब हो सकता हूं लेकिन कमजोर नहीं.'' उस टिप्पणी को जातिगत लहजे में देखा गया जिससे सिद्धू को बैकफुट पर जाना पड़ा—भले ही ऐसा सिर्फ फिलहाल के लिए ही हुआ हो.

सिद्धू इन मुद्दों को लगातार उठाते रहे थे क्योंकि ये मुद्दे राज्य के उन पंथिक (सिख धार्मिक) मतदाताओं को प्रभावित करते हैं जो पंजाब की 117 में से 48 विधानसभा सीटों के नतीजे तय करते हैं. वहीं, चन्नी ने कांग्रेस

जमीन से जुड़ाव
खौली गांव में 6 दिसंबर को एक परिवार के साथ भोजन करते मुख्यमंत्री चन्नी (बाएं)

एएनआइ

का पारंपरिक आधार रहे गरीबों और वंचितों के बीच स्थिति मजबूत करने पर नजरें गड़ाई हैं. इसके नतीजतन कई लोकलुभावन घोषणाएं हुई हैं, मसलन 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी, कक्षा 8 तक के सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त स्कूली पोशाक और उपभोक्ताओं के लिए केबल टीवी मासिक शुल्क 100 रुपए तक सीमित करना आदि. इसके अलावा उन्होंने नगर निगमों में सफाई-सेवकों तथा स्वास्थ्यकर्मियों की भर्ती भी शुरू की है.

चन्नी की मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्ति को व्यापक रूप से चुनाव से पहले कांग्रेस के ऐसे चतुराई भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है जिससे पंजाब के 32 फीसद दलित वोट को पार्टी के पक्ष में मजबूती से जोड़ा जा सके. चन्नी पंजाब के सबसे पिछड़े दलित समुदायों में से एक रामदासी सिख समुदाय से हैं. सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (सीएसडीएस) के एक अध्ययन से पता चलता है कि 2017 के चुनावों में कांग्रेस ने ओबीसी सिख वोटों का 37 फीसद, दलितों का 41 फीसद वोट और 28 फीसद जाट सिख वोट हासिल किए थे. जाट सिख बहुल किसान संघों के नेतृत्व में केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे आंदोलन ने राज्य की राजनीति में अधिक महत्व की मांग कर रहे गैर-जाट सिख समुदाय का ध्रुवीकरण कर दिया है. चन्नी की दलित, गैर-जाट सिख पहचान इस वोट बैंक को अपील कर सकती है.

कांग्रेस की ही तरह विपक्षी दल भी पंजाब में दलित वोटों की होड़ में लगे हैं. सुखबीर बादल के नेतृत्व वाले शिअद ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से गठबंधन किया है. शिअद और आम आदमी पार्टी (आप), दोनों ने सत्ता में आने पर किसी दलित को उपमुख्यमंत्री बनाने का वादा किया है. चन्नी को इसका फायदा मिलेगा कि आकर्षक वादों के बावजूद आप पंजाब में वास्तव में प्रभावी नहीं हो सकी है, दूसरी ओर शिअद मजहबी सिखों (सिख धर्म में परिवर्तित होने वाले दलितों) पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है.

राज्य के माझा और दोआबा क्षेत्रों के दलितों के बीच भाजपा का भी बड़ा आधार है, भाजपा केंद्रीय कृषि कानूनों को हाल ही में निरस्त करने और अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) के साथ चुनावी तालमेल से फायदा मिलने की उम्मीद कर रही है.

भाजपा और पीएलसी की नजर कांग्रेस, शिअद और आप से नाता तोड़ने वालों पर भी है. भाजपा पहले ही सुखबीर के विश्वासपात्र मनजिंदर सिरसा और परमिंदर बरार के साथ कांग्रेस छोड़ने वाले पंजाब के पूर्व डीजीपी एस.एस. विर्क को अपने पाले में शामिल कर चुकी है. विर्क ने राज्य में कांग्रेस को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और प्रतिभाशाली लोगों की तलाश में कैप्टन अमरिंदर की मदद की थी. उनके तलाशे लोगों में साल 2012 में कांग्रेस में शामिल होने वाले चन्नी भी शामिल हैं.

खरड़ (चंडीगढ़ के बाहरी इलाके का एक कस्बा) की नगरपालिका समिति के अध्यक्ष से मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने तक चन्नी का राजनैतिक जीवन उल्लेखनीय रहा है. वह चमकौर साहिब से तीन बार विधायक रहे हैं और विपक्ष का नेता रहने के साथ-साथ अमरिंदर सरकार में तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री भी रह चुके हैं. तकनीकी शिक्षा मंत्री रहने के दौरान रोजगार मेले लगवा कर और कौशल केंद्र खोलकर चन्नी ने थोड़ी प्रतिष्ठा भी हासिल की थी. पार्टी को उम्मीद है कि इससे राज्य के युवाओं में उनकी अपील और बढ़ सकती है. सिद्धू के उकसावों में फंसने की बजाए शासन पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने अति-महत्वाकांक्षी सिद्धू को परिपक्व तरीके से संभाला है. चन्नी न केवल अपनी पार्टी के नेताओं की महत्वकांक्षाओं को संभाल रहे हैं, बल्कि अमरिंदर के समय में हुई गड़बड़ियों से पार्टी को उबारने पर भी ध्यान दे रहे हैं. इस कसौटी पर देखा जाए तो चन्नी ठोस योजना वाले सधे हुए नेता नजर आ रहे हैं. ■

बिहार

भ्रष्टाचार पर जोरदार वार

अमिताभ श्रीवास्तव

नोटों की बारिश
कटिहार में ओएसडी मृत्युंजय कुमार के आवास पर छापेमारी के दौरान सतर्कता इकाई के अधिकारी

रंजन राही

पटना के सियासी हलकों में 17 नवंबर को खासी खलबली मच गई. दरअसल, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) नैयर हसनैन खान ने मगध विश्वविद्यालय के वाइस-चांसलर (वीसी) राजेंद्र प्रसाद के दफ्तर और निजी आवासों पर छापेमारी के लिए बिहार की विशेष सतर्कता इकाई (एसवीयू) की टीमें भेज दी थीं. ऐसी बदनामी झेलने वाले वे बिहार के पहले वाइस-चांसलर हैं. उन्हें 2019 में राज्यपाल फागु चौहान ने इस विश्वविद्यालय का प्रमुख बनाया था. चौहान उत्तर प्रदेश के पूर्व भाजपा नेता हैं.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1996 बैच के आइपीएस अफसर खान को जनवरी 2021 में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) का प्रमुख बनाया. सितंबर में उन्हें एसवीयू की कमान भी दे दी गई. दोनों भूमिकाएं मानों ताकतवर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई के जनादेश की तरह थीं. ईओडब्ल्यू ने तब से बड़े सरकारी अफसरों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) के 11 मामले दाखिल किए हैं. गंभीर और सुलझे हुए अफसर के तौर पर खान ने सुर्खियों में आने वाले कई मामलों में एसआइटी (विशेष जांच टीम) की अगुआई करके नीतीश का भरोसा जीता है. इनमें 2017 में बिहार कर्मचारी चयन आयोग का पेपर लीक होने का मामला भी था.

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) के पूर्व अफसरों को लेकर 2006 में बनाई गई एसवीयू नीतीश के दिमाग की उपज बताया गया था. मगर वक्त के साथ यह एक और नाकारा संस्था भर बनकर रह गई थी. नीतीश के मौजूदा कार्यकाल में एक तरह से इसे नई जिंदगी मिली है. एसवीयू, अन्य इकाइयों से इस मामले में अलग है कि यह पुलिस मुख्यालय और राज्य के गृह विभाग से स्वतंत्र रहकर काम करती है. खान सीधे नीतीश को रिपोर्ट करते हैं.

बिहार में नीतीश के जनता दल (यूनाइटेड) या जद (यू) के साथ सत्ता में साझेदार भाजपा ने छापों के बारे में चुप्पी साध रखी है. इसकी एक वजह तो एसवीयू की ओर से की गई सनसनीखेज बरामदगी है. उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित प्रसाद के घर से 2 करोड़ रुपए नकद, एक करोड़ रुपए के गहने और इतनी ही कीमत की जमीन में निवेश से जुड़े दस्तावेज मिले. एसवीयू ने वीसी के एक आवास से विदेशी मुद्रा भी बरामद की. छापे तब मारे गए जब बिना मांग के उत्तर पुस्तिकाएं और दूसरे चीजें छपवाने में 30 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं की रिपोर्ट आई.

प्रसाद पर छापों ने अकादमिक और राजनैतिक हलकों को झकझोर दिया, तो एक हफ्ते बाद अफसरशाही शर्मिंदगी में डूबी दिखाई दी. 26 नवंबर को एसयूवी ने खदान और भूविज्ञान मंत्री जनक राम के ओएसडी (ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी) मृत्युंजय कुमार और उनकी साथी रत्ना चटर्जी के घरों पर छापे मारे. ओएसडी का चयन आम तौर पर मंत्री खुद करते हैं और उनकी पहुंच को देखते हुए उन्हें तकरीबन अपने बॉस जितना ही ताकतवर माना जाता है. बिहार प्रशासनिक सेवा के पूर्व अफसर मृत्युंजय कुमार के ठिकानों से 30 लाख नकद, 30 गोल्ड बार और बिहार तथा पश्चिम बंगाल में संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए. रत्ना पूर्व बाल विकास परियोजना अधिकारी हैं. 2012 में रिश्वत लेते हुए पकड़े जाने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था.

11

केस आय से अधिक संपत्ति के, वरिष्ठ अफसरों के खिलाफ सितंबर से अब तक दर्ज हो चुके हैं

18 करोड़ रुपए

नकद एसयूवी बरामद कर चुकी है, बिहार सरकार के अफसरों के घरों से पिछले 10 महीनों के दौरान

मृत्युंजय कुमार पर छापा इसलिए भी अहम है क्योंकि वे भाजपा के मंत्री जनक राम से जुड़े थे. पूर्व लोकसभा सांसद जनक राम को भाजपा ने नीतीश के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के लिए तब चुना जब वे किसी भी सदन के सदस्य तक नहीं थे (बाद में उन्हें विधान परिषद में मनोनित किया गया). भाजपा से केवल पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और एमएलसी नवल किशोर यादव ने वीसी पर छापों के बारे में मुंह खोला. मोदी ने ट्वीट किया कि वीसी को तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, लेकिन ओएसडी पर छापे के बारे में वे कुछ नहीं बोले. कई बार फोन करने के बावजूद बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे.

मुख्यमंत्री दफ्तर के एक सूत्र कहते हैं, ''भाजपा के मंत्री से जुड़े ओएसडी और राज्यपाल से नियुक्त वीसी के खिलाफ छापों को सियासी चश्मे से भले देखा जाए, पर सच यही है कि मुख्यमंत्री किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं हैं. उन्होंने अफसरों से भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है, फिर वे चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हों.'' कई आइपीएस अफसर भी आय से अधिक संपत्ति के मामलों की जद में हैं. इनमें भोजपुर के पूर्व एसपी राकेश दुबे और औरंगाबाद जिले के पूर्व एसपी सुधीर पोरिका शामिल हैं. पोरिका को रेत खनन माफिया के साथ कथित रिश्तों की वजह से निलंबित कर दिया गया था. 2 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय ने डीआइजी शफी-उल हक को निलंबित कर दिया. यह खान की सतर्कता इकाई की एक और कामयाबी थी क्योंकि एसयूवी ने ही हक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की रिपोर्ट दी थी. ■

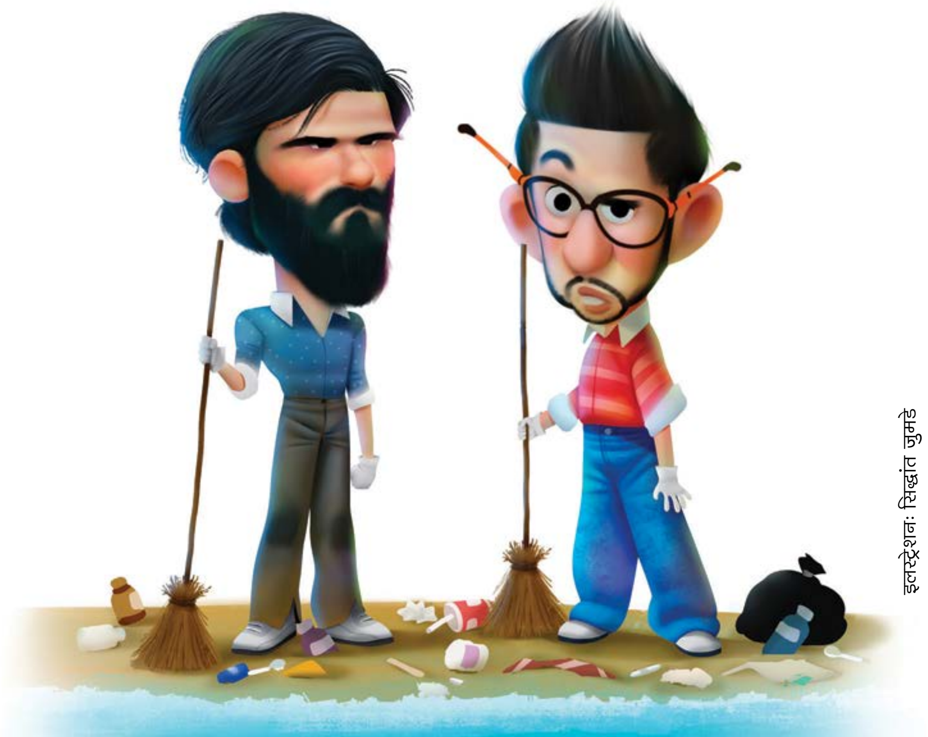

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

समाचार सार

नई पीढ़ी में खींचतान

राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की प्रतिद्वंद्विता अगली पीढ़ी तक पहुंचती दिख रही है. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ने हाल ही में घोषणा की है कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के 40 समुद्र तटों की सफाई करेंगे. एमएनएस का संभावित अभियान स्पष्ट रूप से राज्य के पर्यावरण और पर्यटन मंत्री तथा चचेरे भाई आदित्य ठाकरे से निपटने का अमित का तरीका है. अमित का कहना है कि उनका अभियान समुद्र तटों के रखरखाव में सरकार की विफलता उजागर करेगा. पिछले साल आदित्य ने राज्य सरकार को मुंबई के आरे जंगल में मेट्रो कार शेड की योजना रद्द करने के लिए मजबूर करके पर्यावरण योद्धा के रूप में अपनी साख बनाई थी. साफ है कि यह खेल आगे भी चल सकता है.

कुलाधिपति का फैसला

तमिलनाडु के राज्यपाल **आर.एन. रवि** की भारतीदासन विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेज के प्राचार्यों के साथ प्रस्तावित बैठक ने विवाद खड़ा कर दिया है. एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स ने इसे अनावश्यक बताते हुए रजिस्ट्रार की ओर से प्राचार्यों को भाग लेने की पुष्टि करने के लिए लिखे पत्र को दोषपूर्ण बताया है. प्राचार्यों का तर्क है कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक मामलों में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है. रवि के पूर्ववर्ती बनवारीलाल पुरोहित के दिनों में भी ऐसी ही बैठक के आयोजन का प्रयास विफल हो चुका है.

रहने की जगह

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री **ममता बनर्जी** ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई में एक छोटा सा भूखंड देने का अनुरोध किया है. महाराष्ट्र दौरे पर गईं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री यह भूखंड चिकित्सा के लिए मुंबई जाने वाले बंगालियों की खातिर राजकीय अतिथि गृह का निर्माण करने के उद्देश्य से चाहती हैं. ममता ने स्पष्ट किया है कि उनकी राज्य की राजनीति में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं है. लेकिन कौन जाने.

पीटीआइ

कॉमरेड की वापसी

माकपा नेता कोडियेरी बालकृष्णन का राजनैतिक करियर पिछले साल तब खत्म हो गया लगता था जब केंद्रीय एजेंसियों ने उनके बेटे बिनीश को धनशोधन मामले में गिरफ्तार किया था. कोडियेरी को पिछले नवंबर में केरल पार्टी सचिव का पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन अब वे उसी कार्यालय में वापस आ गए हैं. एजेंसियों को अभी तक उनके बेटे को मामले से जोड़ने का सबूत नहीं मिला है. कोडियेरी अब कहते हैं कि उन्होंने अपने इलाज के लिए पद छोड़ा था. पार्टी के लोग इससे खुश हैं. उन्हें अगले साल माकपा के संगठनात्मक चुनावों का प्रबंधन करने के लिए इस ताकतवर नेता के व्यवहार कौशल की जरूरत है.

वायरल परेशानी

झारखंड के सीएम **हेमंत सोरेन** ट्विटर पर उपस्थिति को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि शिकायतों पर अधिकारियों से जवाब मांगने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं. किसी खुराफाती ने उनकी ओर से कोविड-19 के ओमिक्रॉन वैरिएंट फैलने के कारण राज्यव्यापी तालाबंदी की घोषणा कर दी, तो उनके कार्यालय ने तेजी से स्पष्टीकरण दिया. सुना है कि पुलिस को फर्जी हैंडल और ट्वीट करने वाले अपराधी की पहचान करने को कहा गया है.

*–**संदीप उन्नीथन,** साथ में **किरण डी. तारे, अमिताभ श्रीवास्तव, जीमॉन जैकब रोमिता दत्ता** और अमरनाथ के. मेनन*

असम

झटपट न्याय का चस्का

कौशिक डेका

न्याय की मांग
अनिमेष भुइयां को श्रद्धांजलि देते आसू नेता समुज्जल कुमार भट्टाचार्य; और (इनसेट) असम के सीएम हेमंत बिस्व सरमा

असम के जोरहाट में 29 नवंबर को 50 लोग की भीड़ ने 23 वर्षीय अनिमेष भुइयां की पीट-पीटकर हत्या कर दी. एक अधेड़ उम्र का स्कूटर सवार कथित तौर पर घायल हो गया था और उस सड़क दुर्घटना के लिए गलती से भुइयां को जिम्मेदार मान लिया गया. ऑल असम स्टुडेंट्स यूनियन (आसू) के नेता भुइयां पर हमले का नेतृत्व घायल स्कूटर सवार के बेटे नीरज दास ने किया, जिस पर मादक पदार्थों की तस्करी समेत एक दर्जन से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पुलिस थाने से एक किलोमीटर से भी कम दूरी पर दिनदहाड़े युवक की हत्या पर लोगों में काफी आक्रोश है. भीड़ के हाथों हत्या के बढ़ते मामलों (पिछले दो साल में ऐसे आधा दर्जन मामले) और मामलों की धीमी सुनवाई के मद्देनजर पारंपरिक तथा सोशल मीडिया पर दास का पुलिस एनकाउंटर कर झटपट न्याय की जोरदार मांग होने लगी. एक न्यूज ऐंकर ने टेलीविजन पर असम पुलिस को यह कहकर भी उकसाया कि दास के खिलाफ ''बुलेट का इस्तेमाल'' करके कुछ हिम्मत दिखाए, जो तब पुलिस हिरासत में था. उस अपील के छह घंटे के बाद दास कथित तौर पर पुलिस हिरासत से भागते समय एक दुर्घटना में मारा गया.

'झटपट न्याय' के इस खुल्लम-खुल्ला प्रदर्शन के बाद राज्यभर में जश्न मनाया जाने लगा. पुलिस बल और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा को नायक करार दिया गया. न तो पुलिस, और न ही सरमा को इस 'दुर्घटना में मौत' को कमतर दिखाने की जरूरत महसूस की. इसकी बजाए, 1 दिसंबर को रात में 2.30 बजे एनकाउंटर के एक घंटे बाद कानून-व्यवस्था के विशेष डीजीपी जी.पी. सिंह ने ट्वीट किया: ''हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है—न्यूटन का तीसरा नियम.'' मानो यह काफी नहीं था, इसलिए मुख्यमंत्री सरमा ने सरकार का रुख साफ करते हुए इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी: ''चाहे जो हो, असम अपराध और अपराधी से मुक्त होगा.''

यह मामला कोई अपवाद नहीं है. दरअसल, 10 मई को सरमा के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही असम में 'एनकाउंटर' की मांग का रुझान शुरू हो गया है. जानवरों की तस्करी, बलात्कार, हत्या, मादक पदार्थों की तस्करी और डकैती के आरोप में गिरफ्तार ज्यादातर अभियुक्त पुलिस एनकाउंटर में मारे गए या घायल हो गए. दो दर्जन से अधिक अभियुक्तों को गोली मारी गई और छह लोग कथित तौर पर फरार होने की कोशिश में मारे गए.

शायद लंबे अरसे तक सुनवाई और खराब सजा दर की वजह से लोगों के बीच झटपट पुलिसिया न्याय की मांग बढ़ी है और अब यह असम में आम बात हो गई है

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल में लोकसभा में बताया कि असम में 1 जनवरी और 15 नवंबर, 2021 के दौरान सात लोग पुलिस हिरासत में मारे गए. अगर इसमें 1 दिसंबर को नीरज दास की मौत को जोड़ा जाए तो इसी साल का आंकड़ा 2013 से अब तक की कुल हिरासत में मौत के मामलों का आधा से ज्यादा हो जाएगा. स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह राज्य में अपराध से निबटने में न्यायेतर (गैर-न्यायिक) तरीकों को संस्थागत बनाने का नतीजा है. असम के मानवाधिकार कार्यकर्ता दिव्ज्योति सैकिया का कहना है, ''जो लोग झटपट न्याय के इस फॉर्मूले पर जश्न मनाकर सरकार को इस तरह की न्यायेतर हत्या के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वे भी इस मुसीबत के शिकार हो सकते हैं. हमारे संवैधानिक लोकतंत्र के लिए इस तरह के रुझान को सामाजिक स्वीकृति मिलना खतरनाक है.''

मुख्यमंत्री का पद संभालने के फौरन बाद एक कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा था कि पुलिस फायरिंग का ढर्रा बनने में कुछ भी

एएनआइ

हिरासत में मौत

असम में पुलिस हिरासत में आठ लोग मारे गए हैं. यह संख्या 2013 और 2020 के दौरान हिरासत में हुई मौतों के आधे से अधिक है. राष्ट्रीय स्तर पर भी हिरासत में मरने वालों की संख्या बढ़कर 151 हो गई है, 2013 के बाद सबसे ज्यादा

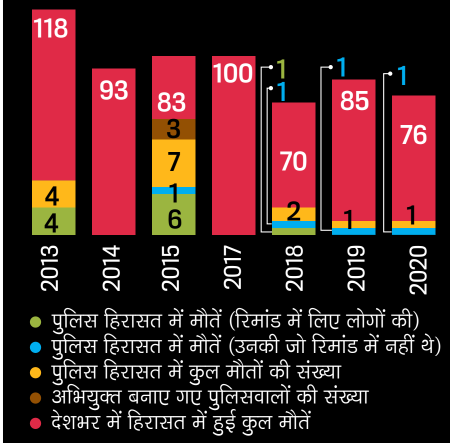

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो

न आरोप, न सजा

असम में आरोपपत्र दाखिल करने की खराब दर की वजह से दोषसिद्धि दर भी काफी खराब है

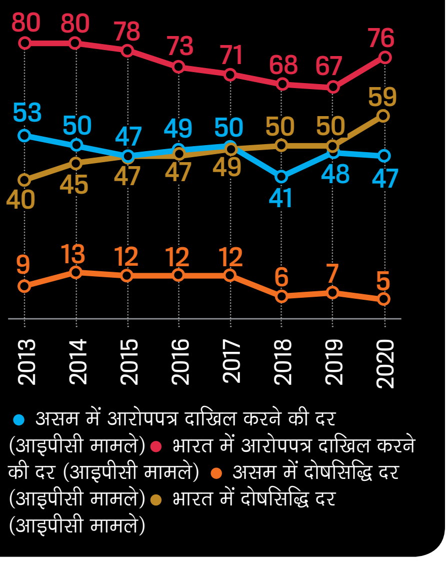

ग्राफिकः असित रॉय

गलत नहीं है क्योंकि हिरासत से फरार होने की कोशिश कर रहे व्यक्ति के पैर में गोली मारना कानून सम्मत है. विधानसभा में उन्होंने पुलिस को जरूरत पड़ने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश देने और राज्य सरकार की ओर से पूरा संरक्षण देने की बात स्वीकार की. जब *इंडिया टुडे* ने सरमा से पूछा कि क्या यह 'ढर्रा' संवैधानिक नियमों के खिलाफ नहीं है, तो उन्होंने कहा, ''मुझे मालूम नहीं है कि किसी खास समय में अपराधी कैसे और क्यों व्यवहार करते हैं. सो, मैं यह नहीं बता सकता कि वे फरार होने की कोशिश क्यों करते हैं. लेकिन असम में कोई न्यायेतर हत्या नहीं होती. पुलिस कानून के मुताबिक ही कार्रवाई कर रही है.''

इससे सरमा के आलोचक सहमत नहीं हैं. उनका मानना है कि सरकार पुलिस को खुली छूट देकर मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक नियमों से समझौता कर रही है. उनका कहना है कि इस तरह के 'शॉर्टकट न्याय' की मांग करने वाले कुछ लोगों को संतुष्ट करना ऐसे राज्य में और ज्यादा खतरनाक है, जहां पुलिस निगरानी का काम ऐतिहासिक रूप से कमजोर रहा है. गुवाहाटी विश्वविद्यालय में राजनीतिशास्त्र पढ़ाने वाले और असम सरकार के शिक्षा विभाग के सलाहकार प्रोफेसर ननी गोपाल महंत कहते हैं, ''इससे भी ज्यादा चिंताजनक पहलू मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों की बहस में इस तरह की 'दुर्घटनाओं' का गुणगान करना है. बहस इस पर होनी चाहिए थी कि इतने ज्यादा अपराधिक मामलों का कोई अभियुक्त आजाद क्यों घूम रहा है और किसी व्यस्त बाजार में दिनदहाड़े कैसे किसी व्यक्ति की हत्या कर सकता है.''

असम उन राज्यों में शुमार है जहां आरोपपत्र दाखिल करने की दर सबसे कम है—राष्ट्रीय औसत 75 फीसद के मुकाबले 50 फीसद से भी कम—और दोषसिद्धि (सजा) की दर भी बहुत कम है—राष्ट्रीय औसत करीब 60 फीसद के मुकाबले केवल 5.4 फीसद. इससे भी बदतर यह है कि दोषसिद्धि की दर धीरे-धीरे घट रही है. साल 2018 में यह 12 फीसद थी.

लंबे अरसे तक सुनवाई के साथ ही दोषसिद्धि की दर कम होने की वजह से राज्य में एनकाउंटर के जरिए हत्या की मांग बढ़ रही है. मिसाल के तौर पर, 2018 में कर्बी आंगलोंग में गलत पहचान के एक और मामले में दो युवकों—अभिजीत नाथ और नीलोत्पल दास—की हत्या कर दी गई थी. इस मामले की फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के बावजूद नाथ और दास के परिजन अब तक इंसाफ का इंतजार ही कर रहे हैं. डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और अपराधशास्त्र पढ़ाने वाले प्रोफेसर जयंत बोरबोरा के मुताबिक, ''अगर आप उपलब्ध न्यायाधीशों की संख्या की तुलना अपराध के आंकड़ों से करें तो पाएंगे कि न्यायपालिका पर जरूरत से ज्यादा बोझ है.''

असम पुलिस इस निराशाजनक रिकॉर्ड के लिए राज्य में कानून-व्यवस्था और अपराध की जांच के बीच अलगाव की कमी को जिम्मेदार ठहराती है. वहीं, राज्य में कई उग्रवादी समूह अब भी सक्रिय हैं पर एक दशक पहले के मुकाबले उनका प्रभाव कम हो गया है. जी.पी. सिंह कहते हैं, ''कानून-व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देने की वजह से हमारे पास जांच के लिए समय कम मिलता है, जिससे आरोपपत्र कमजोर होते हैं और दोषसिद्धि की दर कम होती है. इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले भी हैं. पर मुख्यमंत्री ने इन कमियों पर ध्यान दिया और पुलिस के कामकाज में सुधार के कई उपाय किए हैं. इसके नतीजे तीन साल में दिखेंगे.''

सरमा ने पुलिस को इन कामों को अलग करने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने राज्य में काम कर रही एक फॉरेंसिक लैब के अलावा चार नई लैब तैयार करने का फैसला लिया है. एक ओर जहां पुलिस विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए इस तरह के उपाय जरूरी हैं, वहीं राज्य में 'झटपट न्याय' की घटनाओं का अब आम होना बहुत चिंताजनक चलन है. ■

प्रशांत किशोर ने तैयार कर दिया विपक्ष के लिए ब्लूप्रिंट

दिग्गज चुनावी रणनीतिकार ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विपक्ष की ताकत और खामियों का रेशा-रेशा विश्लेषण किया. साथ ही, 2024 के आम चुनाव में भाजपा को चुनौती पेश करने के लिए विपक्ष की खातिर उन्होंने तैयार किया एक लंबा-चौड़ा गेमप्लान

राज चेंगप्पा

इत्तेफाकन चुनाव रणनीतिकार बने प्रशांत किशोर का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ही कमाल का रहा है. वे नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी, एम.के. स्टालिन, जगन मोहन रेड्डी, अरविंद केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह तक सियासी फलक पर तमाम नेताओं को अपनी सलाहों से नवाज चुके हैं. उन्होंने नौ चुनावों की रणनीति बनाने में मदद की. इनमें से आठ में उनकी रणनीति ने जीत के झंडे गाड़े. सबसे ताजातरीन मई 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव था. इसमें ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीतकर तीसरे कार्यकाल के लिए फिर मुख्यमंत्री बनीं, बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने खेल में अपनी हर मुमकिन ताकत झोंक दी थी. तमिलनाडु में स्टालिन ने भी जीत हासिल की. एकमात्र चुनाव जो किशोर हारे, वह 2017 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, जिसमें उन्होंने कांग्रेस को जिताने का जतन किया था.

संयुक्त राष्ट्र के पूर्व जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ 2010 में उस समय गुजरात के

सभी फोटोः बंदीप सिंह

मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक मुलाकात के बाद पोल एडवोकेसी यानी वे चुनावी हिमायत के खतरनाक पेशे में कूद पड़े. भविष्योन्मुखी मुख्यमंत्री को स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर सलाह देने के साथ शुरू हुआ सिलसिला मोदी के भाषण लिखकर गुजरात सरकार को ताकतवर खुराक देने के अभियान में बदल गया. किशोर बताते हैं, ''एक के बाद दूसरी चीजें होती गईं और मैं उनके राजनैतिक अभियानों से जुड़ता गया.'' उन्होंने 2012 में फिर चुनकर आने के बेहद कामयाब अभियान में मोदी की मदद की और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के उनके अभियान से औपचारिक तौर पर जुड़ गए.

किशोर ने चुनाव सलाहकार समूह सिटिजंस फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस (सीएजी) बनाया. मोदी के प्रधानमंत्री पद के अभियान के शिखर दिनों में इसके 13 राज्यों में 1,200 कर्मचारी थे. किशोर को मोदी के यादगार 'चाय पे चर्चा' अभियान के विचार का श्रेय दिया जाता है. जीत के बाद अपनी भूमिका को लेकर मतभेद के चलते वे मोदी और भाजपा से अलग हो गए. सीएजी को उन्होंने फिर आइ-पीएसी या इंडियन पोलिटिकल ऐक्शन कमेटी में बदल दिया, जो क्रॉस-पार्टी पोलिटिकल एडवोकेसी ग्रुप है. इसी के मार्फत वे देश के प्रमुख राजनैतिक सलाहकार बनकर उभरे.

किशोर जोर देकर कहते हैं कि अब वे आइ-पीएसी से औपचारिक तौर पर जुड़े नहीं रह गए हैं और इन दिनों एक ऐसा राजनैतिक ताना-बाना बुनने में व्यस्त हैं जो 2024 के आम चुनाव में भाजपा को असरदार चुनौती दे सके. *इंडिया टुडे* के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किशोर दो घंटे से ज्यादा वक्त बोले और 2024 में भाजपा को विश्वसनीय चुनौती देने के लिए गेमप्लान का खाका तैयार किया. उनसे हुई बातचीत के अंश:

विक्रम शर्मा

प्र. हाल ही में एक ट्वीट में आपने कहा कि ''कांग्रेस जिस विचार और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, वह मजबूत विपक्ष के लिए अत्यंत अहम है. मगर कांग्रेस का नेतृत्व एक व्यक्ति का दैवीय अधिकार नहीं है, खासकर जब पार्टी बीते 10 सालों में 90 फीसद से ज्यादा चुनाव हार चुकी है. विपक्ष का नेतृत्व लोकतांत्रिक ढंग से घोषित होने दिया जाए.'' साफ है कि आप कांग्रेस नेतृत्व पर हमला कर रहे हैं, पार्टी पर नहीं. वह क्या था जिसने आपको ऐसा करने के लिए उकसाया?

इरादा किसी पर हमला करने का नहीं. हाल की पूरी बहस यह है कि प्रभावी विपक्ष का मतलब कांग्रेस के साथ विपक्ष है या कांग्रेस के बिना विपक्ष है. अपने ट्वीट में बिल्कुल स्पष्ट हूं कि कांग्रेस जिस विचार और स्थान का प्रतिनिधित्व करती है, वह इस देश में प्रभावी विपक्ष के लिए बेहद जरूरी है. मगर कांग्रेस पार्टी, वह विचार, या स्थान, जिसका वह प्रतिनिधित्व करती है, वही नहीं है जो कांग्रेस अपनी मौजूदा बनावट में है. मौजूदा नेतृत्व के मातहत कांग्रेस ने बहुत अच्छा नहीं किया है. बीते 10 सालों में, 50 से ज्यादा राज्य और आम, दोनों चुनावों में, वह करीब 90 फीसद हारी है. बस कर्नाटक के 2012 के राज्य चुनाव, पंजाब के 2017 के चुनाव और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के 2018 के चुनाव छोड़ दें. यह हमें बताता है कि मौजूदा संदर्भ में पार्टी ने खुद को जिस तरह संगठित किया है, जिस तरह वह चुनावों को देखती है, जिस तरह लोगों को जोड़ती है, उसमें कुछ न कुछ बुनियादी खामी है. मैं यह नहीं कह रहा कि संगठन का नेता कौन होना चाहिए. अकेली कांग्रेस पार्टी ही पूरा विपक्ष नहीं है. दूसरी पार्टियां भी हैं. तो उन्हें तय करने दीजिए कि कौन अगुआई करे, बजाए इसके कि कोई एक कहे कि अमुक अध्यक्ष होना चाहिए. मेरे ट्वीट में गलत क्या है?

● कांग्रेस की अगुआई वाले यूपीए (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) ने केंद्र में 2004 से 2014 तक राज किया. इस तथ्य को देखते हुए पार्टी कह सकती है कि ये महज सत्ता-विरोधी

कांग्रेस के बारे में

> “कांग्रेस को पार्टी के रूप में अपने मौजूदा ढांचे, कार्यशैली और फैसले लेने के तौर-तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है. इतने लंबे-चौड़े फैलाव वाली और इतनी पुरानी विरासत वाली सियासी पार्टी तीन साल तक अंतरिम अध्यक्ष या अस्थायी इंतजाम के साथ भला कैसे चलती रह सकती है!

> 2019 में भाजपा से सीधी लड़ाई वाली हर सौ सीटों में से चार पर ही जीत हासिल कर पाई थी कांग्रेस

> भारत के मतदाताओं में 40% भाजपा की हद में हैं क्योंकि 35-37% तो उसका वोट शेयर है ही; बाकी में 20 फीसद दूसरे चैलेंजर्स को जाता है. भाजपा को चैलेंज करने के लिए कांग्रेस को बाकी के 60% में से 40% अपने पास लाने होंगे. अभी हैं सिर्फ 19%

> सोनिया और राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष रहते उनका स्ट्राइक रेट 31 से 35% के बीच था. पर 2019 से, जब से मुखिया का किसी को पता नहीं, यह दर 10% से नीचे आ गई है.”

नतीजों से हुए नुक्सान थे. राहुल गांधी कह सकते हैं, देखो हमने मोदी लहर में भी चार राज्य जीते, यह कांग्रेस के उबरने का संकेत है. तो नेतृत्व पर हमला क्यों?
कांग्रेस का पतन कोई ताजा फेनोमेना नहीं है. आखिरी बार उसने 1984 में यह देश जीता था (जब 404 सीटें जीतीं). 1984 के बाद पार्टी ने एक भी आम चुनाव नहीं जीता. हां, इस बीच उसने 15 साल राज किया, एक बार अल्पमत सरकार के रूप में और दो बार गठबंधन सरकार के रूप में. मगर पार्टी के रूप में उसने देश तो नहीं ही जीता. मसलन, 1989 के आम चुनाव में उसने महज 198 सीटें जीतकर सत्ता गंवाई. मगर 2004 में उसने केवल 145 सीटें जीतकर गठबंधन सरकार बनाई. तो सियासी पार्टी के तौर पर उसका पतन चिरकालिक है.

● **2009 को छोड़ जब 206 सीटें जीती थीं.**
हां, लेकिन तब भी उसके पास अपने दम पर बहुमत नहीं था. उसके प्रदर्शन की बेहतर थाह विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (से ली जा सकती) है. अपने शिखर पर कांग्रेस करीब 3,500 निर्वाचन क्षेत्रों (फिलहाल कुल 4,121 हैं) में नंबर 1 या करीबी नंबर 2 हुआ करती थी. आज यह संख्या घटकर 1,500-1,600 पर आ गई है. उसका ग्राफ गिरता रहा है, खासकर 1984 के बाद. कह मैं यह रहा हूं कि कांग्रेस की गिरावट तात्कालिक परिघटना नहीं है. यह किसी व्यक्ति या प्रसंग से जुड़ी नहीं है. यह ढांचागत है और कांग्रेस के पुनरुत्थान की किसी भी योजना में इन कारकों का ध्यान रखना होगा. वर्ना उन्हें नतीजे नहीं मिलेंगे.

● **कांग्रेस में कई लोग जोर देकर कहते हैं कि चूंकि आप पार्टी को रणनीति पर सलाह देने वाले थे और यह हो नहीं सका, इसलिए आप बदले की भावना से उन पर हमला कर रहे हैं.**
देखिए, यह तो मुमकिन ही नहीं है कि कोई भी बिन बुलाया मेहमान बनकर गांधी परिवार या कांग्रेस नेतृत्व के घर पहुंच जाए और कहे कि जरा मेरी रणनीति जान-सुन लीजिए. उन्होंने मुझसे पूछा और मेरे विचार से जो ठीक लगा, वह मैंने बताया. अब मैंने जो उनके सामने पेश किया, उसे वे मानें या खारिज कर दें, यह उनका अधिकार है. मुझे भी वह करने का अधिकार है जो सही है. कांग्रेस नेतृत्व के साथ मेरी पिछले दो साल से बातचीत चल रही थी. बंगाल चुनाव के बाद यह कहीं ज्यादा विधिवत, गहन बातचीत थी. मैं पार्टी में लगभग शामिल हो ही गया था. मगर कुछ मुद्दों पर हमें एहसास हुआ कि साथ आना दोनों ही पक्षों के लिए मददगार होने की बजाए नुक्सानदायक होगा. हम ससम्मान अलग हो गए. कोई कटुता थी ही नहीं.

प्रशांत किशोर के सभी फोटोः बंदीप सिंह

एएनआइ

● कांग्रेस को क्या करना चाहिए?
कांग्रेस पार्टी के तौर पर जिस तरह ढली है, जिस तरह वह काम करती है और जिस तरह वह फैसले लेती है, उसे बदलने की जरूरत है. आपको एक उदाहरण देता हूं. कांग्रेस के आकार, पैमाने और विरासत वाली राजनैतिक पार्टी पिछले तीन साल से अंतरिम अध्यक्ष या कामचलाऊ व्यवस्था के साथ काम कर रही है. क्या यह स्मार्ट कदम है? सलाह के लिए आपको प्रशांत किशोर या उस लिहाज से किसी की भी जरूरत नहीं. आप जिसे भी चुनें, पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए.

● और?
नेतृत्व के मुद्दे के अलावा उसे तेजी से फैसले लेने और स्थानीय नेताओं को ताकतवर बनाने की जरूरत है. तमाम फैसले लेने को केंद्रीयकृत करके दिल्ली में कुछेक व्यक्तियों के हाथ में सीमित रखने की जरूरत नहीं है. भारत इतना बड़ा और इतना विशाल है कि सारा ज्ञान और विशेषज्ञता कुछेक व्यक्तियों में ही समाई हो, यह मुमकिन नहीं. अगर आप कांग्रेस के शिखर वाले दिनों को देखें तो पाएंगे कि दिल्ली में बैठे चंद महासचिव उसे नहीं चला रहे थे. पार्टी मजबूत थी क्योंकि उसके पास धाकड़ क्षेत्रीय नेता थे. मैं यह नहीं कह रहा कि उसके पास मजबूत नेता नहीं, पर फिलहाल कांग्रेस जिस तरह काम करती है, उसे देखते हुए तो असल ताकत महासचिवों में और जिसे लोग पार्टी हाइकमान कहते हैं उसी में समाई है. बिल्कुल जमीनी स्तर से कांग्रेस के पुनरुत्थान में यही सबसे बड़ा रोड़ा है.

● पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की नेता ममता बनर्जी ने हाल में ऐलान किया कि यूपीए मर चुका है और यहां तक कि उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और खासकर राहुल गांधी पर हमला किया, यह कहकर कि नेता इतना सारा समय विदेश में नहीं बिता सकते.
वे ही बता सकती हैं कि उनका आशय क्या था, पर यह तर्कसंगत है क्योंकि यूपीए केंद्र में सरकार बनाने और चलाने के लिए 2004 में बना था. यह उस स्थिति में राजनैतिक गठबंधन बनाने जैसी बात नहीं थी जब आप सरकार में न हों. अगर आप मान भी लें कि यह दोनों स्थितियों के लिए था, तो इसके गठन, इसके कामकाज पर नए सिरे से विचार का समय आ गया है. क्योंकि इसके घटक बदल गए हैं; इसका हिस्सा रहे कई दल बाहर चले गए हैं, कई जो हिस्सा नहीं थे, इसमें आ गए हैं. डायनैमिक्स बदल गया है. तो आप वही यूपीए नहीं रख सकते जो 2004 में था. आप कहते रहें कि वही संगठन, उन्हीं समर्थकों और उसी कामकाजी तंत्र के साथ मौजूद है. यूपीए और उसके गठन पर नए सिरे से विचार की जरूरत है.

● आपने यह भी कहा कि कांग्रेस नेतृत्व किसी का दैवीय अधिकार नहीं है. साफ है कि आप उसके वंशवादी झुकाव का जिक्र कर रहे थे...
नहीं, यह किसी व्यक्ति की ओर निर्देशित नहीं था. मेरी बात सीधी-सादी है. राजनैतिक पार्टी का नेता होने के नाते जब आप उसकी जीत का श्रेय लेते हैं, तो दुनिया भर में लोकतांत्रिक पार्टी की नीति यह है कि जब आप हारते हैं तो पद छोड़ देते हैं और किसी दूसरे को नेतृत्व संभालने देते हैं. आप जितने चाहे मौके ले सकते हैं पर अगर किसी वजह से यह कारगर नहीं हो रहा, तो यही समय है कि आप किसी और को मौका लेने दें. इस लिहाज से राजनैतिक पार्टी ही क्यों, किसी कॉर्पोरेट, किसी भी संस्था, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान या किसी भी टीम को लीजिए. अगर नेता लगातार नाकाम हो रहा है, तो क्या यह तर्कसंगत नहीं है कि वह अलग हट जाए और किसी और को वह काम करने दे? वह 'कोई और' भी कांग्रेस से हो सकता है.

● राहुल गांधी हट तो गए थे...
मैं राहुल गांधी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस नेतृत्व की बात कर रहा हूं जिसके मातहत पिछले 10 साल से चुनाव लड़े जाते रहे हैं. वह नेतृत्व 90 फीसद चुनावों में नाकाम हो चुका है और यह कड़वा सच है.

विपक्ष के बारे में

> “कई पार्टियों के साथ आ जाने भर को आज की भाजपा के खिलाफ सफलता का सूत्र मान लेना बड़ी भूल होगी. इसके लिए आपको चार चीजें चाहिएः एक समन्वयकारी चेहरा, एक नैरेटिव, फिर समीकरण, और साथ में चुनावी मशीनरी
>
> राष्ट्रीय स्तर पर कोई तीसरी पार्टी सही मायने में भाजपा को चैलेंज नहीं कर सकती, जब तक कि वह आज की कांग्रेस वाली जगह न ले ले. एक ऐसे मुल्क में जहां 60% से ज्यादा आबादी रोज सौ रु. से भी कम कमाती हो, लेफ्ट-ऑफ-सेंटर विचारधारा के लिए एक बड़ी जगह है
>
> एक अदद नेता खोजने की कोशिश फालतू की कवायद है. क्या हम में से कोई भी 1972 में ही अनुमान लगा पाया था कि जेपी (जयप्रकाश नारायण) विपक्ष को जोड़ेंगे और उसका चेहरा बन जाएंगे? 1986 में किसने सोचा था कि वी.पी. सिंह पीएम बनेंगे? 2010 में कौन कहता था कि नरेंद्र मोदी भाजपा का चेहरा बनेंगे? आपके पास सही मुद्दे हों, उसके आसपास नैरेटिव गढ़ें तो नेतृत्व उभर आएगा”

अब जो भी नेता था, नैतिकता और रणनीतिक बोध का तकाजा है कि आप हट जाएं और किसी और को (कमान) संभालने दें.

● क्या आप वंशवादी उत्तराधिकार के खिलाफ हैं?

वंशवाद इस देश की सचाई है. हममें से कइयों को यह दुर्भाग्यपूर्ण लग सकता है, पर यह सच है. डेटा बताता है कि मौजूदा संसद में या पिछली संसदों में 40 से कम उम्र के दो-तिहाई सांसदों का किसी न किसी प्रकार का खानदानी संबंध था. जब चुनावी राजनीति की बात आती है, जिन लोगों की वंशवादी पृष्ठभूमि नहीं है, उनका प्रवेश लगातार मुश्किल होता जा रहा है. मगर यह लंबे वक्त की चुनौती है जिसका मुकाबला भारतीय लोकतंत्र को करना होगा. यह आदर्श स्थिति नहीं है, पर हम चाहने भर से इससे छुटकारा नहीं पा सकते. हालांकि इसके लिए ज्यादातर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया जाता है, पर गलती ज्यादा नहीं तो बराबर से दूसरी पार्टियों की भी है. पर ये ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी.

● आप ममता बनर्जी को सलाह दे रहे हैं.

नहीं, मैं ममता बनर्जी को सलाह नहीं दे रहा. मैंने कहा था कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद मैं जो कर रहा था, वह छोड़ दूंगा. मैं जिस संगठन आइ-पीएसी (इंडियन पोलिटिकल ऐक्शन कमेटी) में काम किया करता था, अगर आप जाकर देखें, तो बीते छह महीनों में उनके दफ्तरों में बमुश्किल 2-3 बार गया होऊंगा. मेरी इच्छा है कि हम एक ऐसा राजनैतिक तानाबाना जुड़ता देख सकें जो असरदार हो, जो उस 60 फीसद जगह को मजबूत करता हो जो गद्दीनशीन निजाम के साथ नहीं है. इसी के लिए मैं लोगों से मिलता हूं लेकिन मोटे तौर पर मैं घर बैठा हूं और कुछ नहीं कर रहा.

● मैं यह पूछना चाहता था कि ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक को तैयार करती मालूम देती हैं. क्या तृणमूल में वंशवादी उत्तराधिकार चल रहा है?

तृणमूल की कमान और कंट्रोल 100 फीसद ममता बनर्जी के हाथ में है. वे खुद बहुत काम करने वाली नेता हैं. ममता बनर्जी ही शो चला रही थीं और चला रही हैं. अभिषेक बनर्जी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से एक हैं.

● अभिषेक बनर्जी की खासियत और योगदान क्या है?

यह तय करना पार्टी का काम है, पर वे तीसरी बार सांसद हैं और मैं मानता हूं कि वे पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं. सार्वजनिक तौर पर घोषित उनकी भूमिका बंगाल के बाहर तृणमूल के विस्तार में मदद करना है.

● वाकई ममता बनर्जी अपने पंख फैलाती मालूम दे रही हैं. तृणमूल गोवा, मेघालय और त्रिपुरा में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है. क्या तृणमूल नई कांग्रेस बनने की कोशिश कर रही है?

यह तो समय ही बताएगा पर तृणमूल के तथाकथित विस्तार को कुछ ज्यादा ही तूल दिया जा रहा है. तथ्य यह है कि इन राज्यों से लोकसभा की महज 4-5 सीटें आती हैं. बार-बार कहा जाता है कि कांग्रेस ही अकेली विपक्षी ताकत है जो राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा का मुकाबला कर रही है लेकिन डेटा दूसरी ही तस्वीर दिखाता है. भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 2019 के लोकसभा चुनाव में महज 4 फीसद और 2014 में 6 फीसद था. जिन पर कांग्रेस ने भाजपा से सीधी लड़ाई लड़ी, ऐसी हर 100 सीटों में से उसने केवल चार जीतीं. उसकी जीत का बड़ा हिस्सा तमिलनाडु, केरल, पंजाब में था, जहां उसका सामना भाजपा से नहीं था. हां, वह भाजपा से लड़ रही है पर जीत कुछ नहीं रही. तो अगर कोई और विपक्षी पार्टी 15-20 सीटों के लिए कोशिश कर रही है तो इसमें गलत क्या है?

● ममता बनर्जी का गेमप्लान क्या है?

यह तो आपको उन्हीं से पूछना पड़ेगा. मुझे लगता है कि अगर तृणमूल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और वाइएसआर कांग्रेस या वे जिनकी जड़ें कांग्रेस के विचार, जगह और विचारधारा से आई हैं, साथ मिलकर कोशिश करें तो वे कांग्रेस के मौजूदा स्वरूप का संभावित विकल्प बनकर उभर सकती हैं. यह कांग्रेस के लिए नई परिघटना नहीं है. उनके लंबे इतिहास में यह कम से कम 3-4 बार हो चुका है. 1969 में जब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस (आइ) बनाई, यह ज्यादा बड़ी कांग्रेस बनकर उभरी. सैद्धांतिक तौर पर यह संभावना मौजूद है कि कोई भी नई कांग्रेस बना सकता है. अगर वह स्पेस ज्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप मौजूदा कांग्रेस में बदलाव आते देखेंगे.

● हमारी समझ से ममता ऐसी विपक्षी एकता चाहेंगी जिसमें जो भी क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है, मसलन तमिलनाडु में स्टालिन, आंध्र में जगन रेड्डी, तेलंगाना में केसीआर या फिर महाराष्ट्र में शरद पवार, वह उस राज्य में बेरोकटोक लड़े. वे यह मानती लगती हैं कि इन इलाकों का कुल योग इतना बड़ा और संपूर्ण हो सकता है कि भाजपा को हरा सके.

यह पूरी की पूरी धारणा कि हर कोई साथ आकर भाजपा को हराने के लिए बहुत मजबूत विपक्ष बना देगा, सफल न होगी. असम में इस साल राज्य के चुनाव में एक महागठबंधन था, वह हार गया. हम यूपी में यही देख चुके हैं, जहां बसपा, सपा और दूसरी पार्टियां 2017 में साथ आईं और हार गईं. तो हमें अतीत से सीखना पड़ेगा. महज कई पार्टियों का एक साथ आना मौजूदा भाजपा के खिलाफ कामयाबी के लिए पक्का उपाय नहीं है. उसके लिए आपको एकजुट करने वाले चेहरे की, नैरेटिव की और फिर समीकरण की दरकार होगी ताकि लोगों को एक संयुक्त विपक्ष दिखाई दे.

● परिदृश्य पर क्या आपको ऐसा कोई नेता दिखाई देता है?

नेता खोजने की यह कवायद गैरजरूरी है. फर्ज कीजिए कि हम यह इंटरव्यू 1972 में कर रहे हैं. अपनी पूरी अक्लमंदी से क्या कोई यह भविष्यवाणी कर सकता था कि जेपी (जयप्रकाश नारायण) नाम का एक नेता विपक्ष को एकजुट करेगा और उसका चेहरा बन जाएगा? अगर हम यह बातचीत 1986 में कर रहे होते, तो भी क्या यह कहा जा सकता था कि वी.पी. सिंह चेहरा बन जाएंगे? 2010 में नरेंद्र मोदी के बारे में किसने सोचा था? मोदी सरकार के लिए तीन बड़े यू-टर्न देखिए. पहला जमीन अधिग्रहण विधेयक था. क्या हम वह चेहरा याद कर सकते हैं जिसने उस विरोध की अगुआई की थी? नहीं. दूसरा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (एनआरसी) था, जिसे रद्द नहीं किया गया है, लेकिन उस पर कदम आगे नहीं बढ़े हैं. क्या हम किसी नेता विशेष को याद कर सकते हैं जिसकी वजह से सरकार कदम पीछे खींचने को मजबूर हुई? हाल में सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए, लेकिन क्या हम किसी एक व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसका श्रेय दिया जा सके? मैं कह यह रहा हूं कि अगर आपके पास सही मुद्दे हैं, तो आप नैरेटिव खड़ा कीजिए, चेहरा उभर आएगा. तो यह पूरी बहस कि पहले चेहरे की पहचान की जाए और तब तक आपके पास कोई चैलेंजर नहीं हो सकता, आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं है.

● क्या इन स्वतःस्फूर्त लेकिन थोड़े-बहुत नेताविहीन विरोध प्रदर्शनों का एक संदेश विपक्ष के लिए यह भी है कि लोगों का उनमें भरोसा नहीं है या उन्होंने उन्हें निराश किया है?

मैं इसे जरूरी तौर पर विपक्ष की नाकामी की तरह नहीं देखूंगा, लेकिन लोग अपने लोकतांत्रिक इंटरफेस यानी राजनैतिक दलों पर भरोसा करने या उन्हें यह काम करने देने की बजाए मामले अपने हाथ में ले रहे हैं. ज्यादा अहम वे कुछ चीजें हैं जो इन विरोध प्रदर्शनों में साझा थीं. एक यही कि लोग इनकी अगुआई कर रहे थे. दूसरी वह दृढ़ता और जिद है जिससे वे लड़ाई जीते. यह जीत एक दिन में नहीं मिली. किसान आंदोलन तो साल भर चला. तो अगर आपमें इच्छाशक्ति है, दमखम है और टिके रहने का माद्दा है तो यह होगा. यह नहीं कि एक ट्वीट करें, अगले दिन लुटियंस की दिल्ली में उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और कुछ कैंडल मार्च निकाल दें और उम्मीद करें कि सरकार घुटनों पर आ जाएगी. कैसे होगा यह!

● लखीमपुर खीरी में कांग्रेस के किसान आंदोलन के बाद आपने कहा कि आसान और फौरी समाधान काम नहीं आएंगे.

देश के तौर पर हम टी20 मोड में आ गए लगते हैं. सब कुछ एक दिन में तय होना है, हर चीज पर हां या नहीं होना है, व्हाट्सऐप यूनिवर्सिटी जहां सब कुछ एक लाइन में कहा जाना चाहिए. बारीक और ब्योरेवार तर्क-वितर्क की कोई जगह ही नहीं है. आप या तो मोदी भक्त हैं या राहुल गांधी भक्त. यह सोच विपक्ष को चोट पहुंचाती और कमजोर करती है. कुछ चुनौतियां बड़ी और जटिल हैं और आपको तफसील से समझना होता है, ऐसे तर्क और स्थापनाएं करनी होती हैं जिनकी कई परतें हैं, वे महज बाइनरी नहीं.

रॉयटर

● **फिर कांग्रेस पर लौटें, क्या आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी पराजित सेनानायक हैं और उन्हें बाहर निकल जाना चाहिए?**
हम उन अकेले को पराजित सेनानायक नहीं कह सकते, क्योंकि हर लिहाज से नेतृत्व मिला-जुला है जिसमें मौजूदा अध्यक्ष और वे इसे चला रहे हैं. मुझे इसे सही नजरिए से रखने दीजिए. मैं सोनिया गांधी के मातहत कांग्रेस का रिकॉर्ड इसलिए देखता हूं क्योंकि वे 25 साल इसकी प्रमुख रहने के साथ सबसे लंबे समय रहने वाली कांग्रेस अध्यक्ष हैं. उनका चुनावी स्ट्राइक रेट कोई 31-32 के आसपास आता है, यानी कांग्रेस ने जितने चुनाव लड़े उनके एक-तिहाई. बतौर अध्यक्ष राहुल गांधी का स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करीब 34-35 फीसद था. दोनों का कोई बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा है. मगर 2019 से, जब किसी को पता नहीं कि नेता कौन है, स्ट्राइक रेट घटकर 10 फीसद या उससे भी नीचे आ गया है. आपको इसे भी देखने की जरूरत है.

● **आपको लगता है कि गांधी परिवार को अब जाना चाहिए?**
नहीं, मैं यह नहीं कह रहा. जरूरत इसकी संरचना बदलने की है. मुमकिन है आप अपनी जगह सही हों पर कभी-कभी बनावट का विन्यास या व्यवस्था बदलकर आप बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि मौजूदा बनावट निश्चित रूप से कारगर नहीं. मौजूदा बनावट और संगठन के स्वरूप को देखते हुए अगले कुछ सालों में भाजपा के खिलाफ इसके कोई बड़ी चुनावी कामयाबी हासिल करने की संभावना कम ही है. मैं कांग्रेस ही नहीं, व्यापक यूपीए की बनावट की बात भी कर रहा हूं.

● **नेतृत्व का सवाल अलग रख दें, तब भी यह तथ्य तो है कि कांग्रेस बड़ी विपक्षी ताकत है. क्या आप किसी भी विपक्षी गठबंधन को ग्रैंड ओल्ड पार्टी को अनदेखा करने की सलाह देंगे?**
कांग्रेस से जिस विचार और स्पेस का प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद की जाती थी और जिस पर वह काबिज है, जमीन पर वह अब भी मजबूत है. सवाल यह है कि आप इसे साथ लाकर चुनावी कामयाबी में कैसे बदलते हैं. मेरा तो पक्के तौर पर मानना है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी तीसरी पार्टी के लिए सही मायने में भाजपा को चुनौती देने की स्थिति में आ पाने की कोई गुंजाइश नहीं, जब तक कि आप वह जगह नहीं लेते जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती है. पर मैं यह भी कह रहा हूं कि आपको भिन्न समीकरण की जरूरत है.

● **बार-बार आप आखिर कांग्रेस की कौन-सी स्पेस की बात कर रहे हैं?**
कांग्रेस की जगह मोटे तौर पर 40-45 फीसद है. भारत के मतदाताओं को देखें, तो आप पाएंगे कि भाजपा सही मायने में करीब 40 फीसद को अपने डिनॉमिनेटर के रूप में देख सकती है, क्योंकि वह 30 से 37 फीसद के बीच वोट हासिल करती रही है. 20 फीसद वोट कई छोटे चैलेंजर क्षेत्रीय दलों को चले जाते हैं. तो कांग्रेस के लिए जगह 40 फीसद तक सिकुड़ गई है. मैं वोटों की नहीं, डिनॉमिनेटर की बात कर रहा हूं. तो कांग्रेस अगर भाजपा की मुख्य चैलेंजर बनना चाहती है तो उसे उस बाकी 60 फीसद में से 40 फीसद हासिल करना होगा, जो भाजपा को वोट नहीं कर रहा. कांग्रेस की वोट हिस्सेदारी 19 फीसद है—यानी

● **अहम मुद्दों के बारे में**

> “हिंदुत्व पॉलिटिक्स की सीमाएं हैं. किसी भी समाज को आप 50-55% से ज्यादा पोलराइज नहीं कर सकते. आंकड़े बताते हैं कि एक हिंदू भाजपा को तो एक खिलाफ वोट डाल रहा है
>
> सत्ता में आने पर पार्टी के ढांचे पर निवेश करने वाली राज्य सरकारों के दोबारा चुनकर आने की संभावना ज्यादा है
>
> वंशवादी राजनीति एक सचाई है. आजकल तो वंशवादी कनेक्शन के बगैर राजनीति में घुस पाना ही मुश्किल है. कांग्रेस ही नहीं, दूसरी पार्टियों में भी यह उतना ही है.
>
> जाति तभी निर्णायक रोल में आती है जब कोई लोकप्रिय चेहरा, दमदार नैरेटिव या फिर कोई जज्बाती घटना मौजूद न हो”

उसे उस 40 फीसद का आधे से भी कम हासिल है. तो समीकरण और रणनीति में बदलाव और बेहतर कोशिशों से इसे 25-30 फीसद तक बढ़ाया जा सकता है और यह बिल्कुल किया जा सकता है.

● **कांग्रेस आखिर किसका प्रतिनिधित्व करती है?**

इस 60 फीसद स्पेस के लिहाज से कांग्रेस अभी भी देश में शासन चलाने की खातिर सबसे उपयुक्त पार्टी है. आज भारत जो कुछ भी है उसमें उसका योगदान है, उसे संविधान और उन मूल्यों के रक्षक के रूप में देखा गया जिसकी कल्पना हमारे देश के संस्थापकों ने की थी. इसलिए, यह सब बहुत बड़ा फायदा है, और इसी पर आगे बढ़ना चाहिए. आगे आने वाली किसी भी दूसरी पार्टी के लिए वह 19 फीसद वोट बड़ा बोनस होगा. पर कांग्रेस के लिए यह बेहद नकारात्मक है क्योंकि आप उस 40 फीसद से नीचे आ रहे हैं जिसका कि आपके लिए अनुमान लगाया गया है.

● **और विचारधारा के संदर्भ में?**

बहुत व्यापक संदर्भ में, मुझे लगता है कि कांग्रेस को अभी भी बुनियादी तौर पर मध्य और वाम के बीच तथा भाजपा को मध्य और दक्षिण के बीच की विचारधारा वाली पार्टी के तौर पर देखा जाता है. मैं इसी सेंटर टु लेफ्ट के बीच की जगह की बात कर रहा हूं. एक देश में जहां 60 फीसद से ज्यादा आबादी रोजाना 100 रुपए भी नहीं कमा पाती, वहां यह बहुत बड़ी जगह है. यही वह जगह है जहां कांग्रेस को महत्वपूर्ण आवाज और खिलाड़ी माना जाता है. इसलिए कांग्रेस के मर जाने की कामना आप नहीं कर सकते या उसे पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते.

● **आपने हाल ही में कहा था कि भाजपा बहुत ज्यादा मजबूत ताकत है और उसे आसानी से नहीं हटाया जा सकता. क्यों?**

राजनैतिक ताकत के रूप में भाजपा को आप बस चाहकर नहीं हटा सकते. पहले आपको देखना होगा कि उन्हें यहां तक कौन-सी चीज लेकर आई है. पिछले 50-60 वर्षों में कई पीढ़ियों के किए गए कामों के नतीजतन बना पुराना संगठन है जो जनसंघ और उससे भी पहले शुरू हुआ था. अब, 60-70 वर्षों के संघर्ष के बाद वे 30-35 फीसद वोट तक पहुंचे हैं. मुमकिन है वे एक या कि कई चुनाव हार जाएं. पर अगर अखिल भारतीय स्तर पर 30 फीसद वोट पाने वाला विशाल संगठन एक बार खड़ा हो चुका है तो वह राजनैतिक संगठन आपके चाहने भर से दूर नहीं बिठाया जा सकता.

● **आपने यह भी कहा था कि भाजपा दशकों तक भारतीय राजनीति का केंद्र बनी रहेगी.**

मैं यह नहीं कह रहा कि भाजपा अगले 30-40 वर्षों तक राज करेगी, लेकिन हां, चाहे वे चुनाव जीतें या हारें, अगले 30-40 वर्षों तक वे भारतीय राजनीति की धुरी बने रहेंगे. ठीक उसी तरह जिस तरह कांग्रेस रही है. 1967 के बाद कांग्रेस को कई चुनावों में मुंह की खानी पड़ी, लेकिन भारतीय राजनीति उसी के इर्द-गिर्द (घूमती) रही क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर उसके पास 30-35 फीसद वोट थे. ठीक यही बात भाजपा पर लागू होती है. कई सारे लोग सोचते हैं कि यह बस वक्त का मामला है और भाजपा का दौर भी खत्म हो जाएगा, वे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. अगर आप भाजपा के खिलाफ हैं, तो आपको एक लंबी सियासी लड़ाई के लिए तैयार रहना होगा, लोगों को यह समझाने के लिए कि आप उन्हें भाजपा से बेहतर विकल्प दे सकते हैं. यह जल्दबाजी में नहीं किया जा सकता; इसका कोई फौरी हल नहीं है.

● **तृणमूल के हाथों भाजपा की हार का सबसे बड़ा पाठ क्या था?**

यह कि आप रक्षात्मक नहीं रह सकते, आप बहुत देर से अभियान नहीं शुरू कर सकते, और यह कि आप मुतमइन नहीं रह सकते. 2019 के लोकसभा चुनाव में जो हुआ, तृणमूल को उसे स्वीकारना पड़ा क्योंकि वह शायद यह मानने को तैयार न थी कि भाजपा बंगाल में मजबूत ताकत बन गई है.

● **भाजपा के बारे में**

“भाजपा ने लोक कल्याण और चरम राष्ट्रवाद के मेल से एक अचूक अस्त्र गढ़ लिया है

भाजपा कम से कम अगले 30-40 साल तक भारतीय राजनीति के केंद्र में रहेगी. चुनाव भले ही वह जीते या हारे, जैसा कि कांग्रेस के साथ हो रहा है

यूपी के चुनाव में 2024 के आम चुनावों का कोई अनुमान निकले, जरूरी नहीं. इसे सेमी-फाइनल न माने. उससे पहले तो और भी कई राज्यों के चुनाव होने हैं ”

ति उपवन, आशियाना लखन
आना बूथ

गेट्टी इमेजेज

अगर आप प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, तो उसकी ताकत को स्वीकार करने में कोई समस्या न होगी. आपको पता रहेगा कि उसे किस तरह से हराना है.

● ममता बनर्जी ने भाजपा के ध्रुवीकरण के दांव का मुकाबला कैसे किया?

ध्रुवीकरण एक पहलू था और इसी वजह से भाजपा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में 38 फीसद वोट हासिल किए. इसमें से बड़ा हिस्सा धार्मिक आधार पर हुए ध्रुवीकरण से आया. लेकिन ध्रुवीकरण की भी अपनी सीमाएं हैं. हमने आंकड़ों पर नजर डाली और पाया कि ध्रुवीकरण 50-55 फीसद तक सीमित है. धार्मिक आधार पर किसी भी समुदाय का ध्रुवीकरण आप 50-55 फीसद से ज्यादा नहीं कर सकते. बंगाल में मोटे तौर पर ऐसा ही हुआ.

● तब क्या आप कहेंगे कि हिंदुत्व की अपनी सीमाएं हैं, जिसे भाजपा और आरएसएस एक चुनावी रणनीति के रूप में प्रचारित कर रहे हैं?

दरअसल, किसी भी रणनीति की अपनी सीमाएं होती हैं. उस हद तक, हिंदुत्व की भी अपनी सीमाएं हैं. क्योंकि हिंदू कोई एक ही जैसे लोगों का धार्मिक समुदाय तो है नहीं. भले तमाम लोग ऐसा ही मानते हों. दूसरी बात, मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय स्तर पर 50 फीसद हिंदू ऐसे हैं जो हिंदुत्व के आधार पर भाजपा को वोट नहीं देना चाहते. इसकी पुष्टि आंकड़े भी करते हैं जो बताते हैं कि भाजपा को वोट देने वाले हर हिंदू पर एक अन्य हिंदू भी होगा जो उसे वोट नहीं करेगा. भाजपा को सियासी चुनौती देने वाली कोई भी पार्टी उसी दूसरी आधी हिंदू आबादी पर नजर गड़ाएगी और चुनावी रूप से भाजपा से मुकाबला करने के लिए उसे पक्ष में करने की कोशिश करेगी.

● फरवरी में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे. वहां ध्रुवीकरण किस तरह काम करेगा, खासकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कट्टर हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं?

ध्रुवीकरण का चेहरा चाहे जो भी हो या ध्रुवीकरण की घटना कोई भी हो, इसकी सीमाएं होंगी ही. मैं कोई अनुमान नहीं लगाना चाहता, इसलिए इस बारे में बात करने की बजाए कि यूपी में चुनावी नतीजे क्या होंगे, मैं एक ठोस बिंदु सामने रखना चाहता हूं: यह जरूरी नहीं कि यूपी चुनाव के नतीजों में यह झलक मिले कि 2024 के आम चुनावों में क्या होगा. कई सारे लोग इसी जाल में फंस रहे हैं कि यूपी के नतीजे ही 2024 का रुख तय करेंगे. मैं आंकड़ों से इसे गलत साबित करूंगा. 2012 में भाजपा यूपी में तीसरे या चौथे नंबर की पार्टी थी. समाजवादी पार्टी ने वह चुनाव जीत लिया था, लेकिन 2014 के आम चुनाव में उसका कोई असर नहीं पड़ा. अगर वह सच था तो आप यह क्यों कह रहे हैं कि 2022 में जो होगा, वहीं 2024 में भी होगा? 2024 के पहले कई दूसरे राज्यों में भी चुनाव होने हैं.

● चुनाव नतीजे तय करने में जाति आधारित राजनीति कितनी महत्वपूर्ण है?

जाति बहुत महत्वपूर्ण है, पर मतदान के समय जाति को कितनी तवज्जो मिलती है, यह बहस का विषय है. मेरी समझ से, कोई पॉपुलर चेहरा या वैसा कोई मुद्दा या फिर कोई भावनात्मक पहलू न होने की स्थिति में ही जाति भूमिका निभाती है. कथित तौर पर लहर वाले चुनावों में, मसलन 1984 में इंदिराजी की मौत के बाद की परिस्थितियों में, जाति के बंधन टूट गए थे. 2014 में नरेंद्र मोदी ने भारत की सोच को साध लिया और जातिगत बंधन तोड़ दिए थे. इसी तरह से वी.पी. सिंह के समय राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है या भ्रष्टाचार-विरोधी योद्धा के रूप में नैरेटिव गढ़े जाने पर भी जातिगत कारक बेअसर हो गए थे. किसी लोकप्रिय चेहरे या नैरेटिव या फिर घटना की गैर-मौजूदगी में लोग अपनी पहचान तक सिमट जाते हैं. चलो कुछ नहीं तो अपनी जाति वाले को (वोट) दे देते हैं.

● तो क्या सरकार के प्रदर्शन का असर मतदाताओं के फैसले पर नहीं पड़ता? हाल ही में हमने राज्यों में कई सरकारों को फिर से चुने जाते देखा है.

इस सवाल का जवाब मुश्किल है. एक संकेत तो यह है कि जो राज्य सरकार सत्ता में आने के बाद अपने राजनैतिक संगठन में निवेश करती है, उसके दोबारा चुने जाने की संभावना ज्यादा होती है. ओडिशा में नवीन बाबू, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तेलंगाना में केसीआर या फिर भाजपा की सभी सरकारों को देख लें. अगर सभी सरकारों का प्रदर्शन एक जैसा है, तो उसके फिर से चुने की संभावना ज्यादा है जिसने अपनी पार्टी के बुनियादी ढांचे पर अच्छा-खासा काम किया है. यह किसी पारंपरिक कांग्रेस सरकार से उलट है जो पार्टी के संगठन की उपेक्षा करती है या उसे पीछे की सीट देती है. इसलिए, यह एक महत्वपूर्ण फर्क हो सकता है. अगर आप कांग्रेस सरकार के फिर से चुने जाने की संभावना को ग्राफ पर देखें, तो

पीआइबी

यह भाजपा की अगुआई वाली सरकार की तुलना में लगभग एक-तिहाई कम है.

● भाजपा के खिलाफ ताकतवर चुनौती पेश करने के लिए विपक्ष को क्या करना चाहिए?
चार पहलुओं को ठीक करना होगा: कोई समन्वयकारी चेहरा होना चाहिए, कोई नैरेटिव हो, कोई युक्ति होनी चाहिए, जैसा कि एकजुट विपक्ष या कोई भी राजनैतिक दल होता है, और उसके साथ-साथ मशीनरी होनी चाहिए. इसमें आपको एक चीज और जोड़नी होगी, वह यह कि भाजपा का मुकाबला करने के लिए उसे खासा चपल और चुस्त-दुरुस्त होना होगा. चाहे वह जमीनी स्तर पर संदेश फैलाना हो या सियासी दांव-पेच हों. अगर आपने ये पहलू दुरुस्त कर लिए तो आप भाजपा को खिलाफ चुनौती पेश कर सकते हैं.

● क्या 2024 तक ऐसा करने के लिए विपक्ष के पास पर्याप्त समय है?
दो साल कम वक्त नहीं होता, इसलिए मैं सब कुछ 2024 पर नहीं छोड़ूंगा. लेकिन अगर आपको वाकई भाजपा का मुकाबला करना है, तो आपके पास 7-10 साल का एक दीर्घकालिक नजरिया होना चाहिए. क्योंकि आप उन्हें 2024 में एक साथ आकर भले हरा दें लेकिन उस जमीन पर बने रहने के लिए आपको उन चार चीजों को लगातार मजबूत करना होगा जिन्हें मैंने रेखांकित किया है.

● भाजपा की क्या कमजोरियां हैं?
जहां कहीं भी उन्हें कठिन सियासी चुनौती का सामना करना पड़ा, वे विरोधियों को अनिवार्य रूप से रोक पाने में नाकाम रहे हैं, कांग्रेस को भले उन्होंने आसानी से शिकस्त दी है. कांग्रेस के खिलाफ उनकी कामयाबी का दर 95 फीसद है. लेकिन दूसरों के खिलाफ यह बहुत अच्छा नहीं रहा है. पूर्वी और दक्षिणी राज्यों को ही देख लें—बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल—जहां लोकसभा की करीब 200 सीटें हैं. उन सभी जगहों पर भाजपा केवल 54 सीटों तक सिमटी हुई है. इसके पास बिहार में 17 सीटें, पश्चिम बंगाल में 18, ओडिशा में 12, तेलंगाना में चार, तमिलनाडु और आंध्र में में एक भी सीट नहीं है. यह बताता है कि इन क्षेत्रों में मजबूत और एकजुट विपक्ष नहीं होने के बावजूद करीब 40 फीसद लोकसभा सीटों में वह कामयाबी हासिल नहीं कर पाई. पिछले 10 वर्षों में वहां व्यक्तिगत पार्टियां और उनके नेता भाजपा के राजनैतिक हमलों का सामना करने में सक्षम रहे हैं. पश्चिम और उत्तर भारत में भाजपा एक ताकत है—अगर आप कर्नाटक से कश्मीर तक एक सीधी रेखा खींचते हैं और गुजरात समेत पश्चिम की ओर देखते हैं, तो यह वह क्षेत्र है जहां भाजपा सचमुच सब कुछ जीत रही है. लेकिन इस इलाके में किसी भी वजह से अगर वे 100 सीटें हार गए तो यह उन्हें काफी कमजोर कर देगा, खासकर पूर्व और दक्षिण में उनकी मौजूदा अनुपस्थिति को देखते हुए.

● इसकी खूबियां क्या-क्या हैं?
कई हैं, लेकिन हिंदुत्व इनकी धुरी बनी हुई है. उन्होंने दो अहम चीजें जोड़ी हैं. एक है आक्रामक राष्ट्रवाद. यह उनके जखीरे का नया हथियार है. इसलिए अगर आप उनकी आलोचना करते हैं, तो वे आपको भारत विरोधी बता देंगे. यह भी एक वजह हो सकती है कि आखिर क्यों हमें महंगाई और बेरोजगारी को लेकर व्यापक असंतोष नहीं नजर आ रहा. नोटबंदी के बाद, हमने टीवी पर देखा कि लोग लंबी कतारों में खड़े हैं, लेकिन यह कहते हुए खुश हैं कि वे मजबूत और नए भारत के निर्माण के लिए ऐसा कर रहे हैं. या फिर महंगाई को ही लें, 50 फीसद ज्यादा कीमत अदा करके भी लोग यह कहते हुए खुश हैं कि ऐसे वे राष्ट्र-निर्माण या राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए कुछ बलिदान तो देना ही होगा. लेकिन हमें उनकी तीसरी ताकत को कमतर नहीं आंकना चाहिए. वह है घर-घर के स्तर पर उनका डिलिवरी सिस्टम. चाहे वह शौचालय हों, उज्ज्वला (खाना पकाने के लिए सब्सिडी वाली गैस) या फिर हर घर नल का जल योजना. आक्रामक राष्ट्रवाद के साथ कल्याणकारी नीति को मिलाकर

> “अनुभव का अनूठा मेल है उनके पासः 15 साल की आरएसएस प्रचारकी, 10-15 साल पार्टी संगठनकर्ता, 13 साल बतौर मुख्यमंत्री और अब 7 साल से पीएम

> जिन मुद्दों पर सरकार जन-विरोधी दिखे, वे कदम पीछे खींचने जैसा लचीला रवैया रखते हैं. साथ ही वे पक्का कर लेते हैं कि कोई दूसरा उसका फायदा न उठा पाए

> वे बहुत धैर्य से सुनते हैं. किसी मुद्दे पर वे ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात सुनते हैं, जिससे वे मामले के सारे पहलुओं से वाकिफ रहते हैं

> सफल नेता को बुद्धिमान होना ही चाहिए. उसमें चरित्र और साहस हो—खुद पर टीका, आलोचना, प्रशंसा सभी को समान भाव से वह ले सके”

भाजपा ने अचूक अस्त्र विकसित किया है. इन तीन कारकों में से दो में जब तक विपक्ष सेंध लगाने में सक्षम नहीं होता तब तक वह राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा को नहीं हरा सकता. कल्याणकारी नीति के मामले में, भाजपा जो दे रही है, आपकी पेशकश उससे बेहतर होनी चाहिए. वहीं आक्रामक राष्ट्रवाद के मामले में आपके पास भाजपा से ज्यादा भरोसेमंद नैरेटिव होना चाहिए. हिंदुत्व के मोर्चे पर, उग्रपंथी और रुढ़िवादी भले भाजपा के साथ हों, उदारवादी आपके साथ हैं. यह सब करके ही विपक्ष भाजपा को चुनौती दे सकता है.

● 2014 से पहले आपने चुनावी रणनीति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी थी. आपके अनुसार मोदी की यूएसपी क्या है?

उनकी कई ताकतें हैं. पहली बात यह कि उनके पास अनुभव का अनूठा मिश्रण है. अगर आप पिछले 50 वर्षों की उनकी यात्रा को देखेंगे तो उन्होंने 15 साल आरएसएस प्रचारक के रूप में बिताए, जहां जनता को समझने, बातचीत करने और जुड़ने का बेहतरीन मौका उनके पास था. फिर, उन्होंने 10-15 साल तक भाजपा में राजनैतिक संगठनकर्ता के रूप में काम किया. वहां उन्होंने राजनैतिक व्यवस्था को उस तरह तैयार करने और उसका प्रबंधन करने का अनुभव हासिल किया जैसा कि उसे होना चाहिए. उसके बाद, 13 वर्षों तक वे मुख्यमंत्री रहे, और आखिरकार सात साल से प्रधानमंत्री हैं. इस 45 साल के उनके अनुभव का मिश्रण देश में अनूठा है. यह उन्हें यह जानने में सक्षम बनाता है कि आखिर लोग क्या चाहते हैं. वे बड़े धैर्य के साथ सुनते भी हैं. किसी भी मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने का गुण उनमें है. इस वजह से शायद वे हर दृष्टिकोण को जान लेने में कामयाब हो जाते हैं. उन्हें निर्णायक के रूप में देखा जाता है, लेकिन धैर्यवान होने के उनके गुण को मैं उससे ऊपर रखूंगा.

● प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस क्यों लिए? आपको क्या लगता है?

इस पर मेरी बिल्कुल अलहदा राय है, जो मोदी के इस चरित्र के बारे में बताती है कि आखिर वे राजनैतिक मसलों को कैसे सुलझाते हैं. व्यक्तियों या पार्टियों के साथ उनका बर्ताव काफी सख्त होता है, लेकिन जनता के खिलाफ वे काफी लचीले होते हैं. आप उनके तीन यूटर्न को देखें; अगर आप उन्हें श्रेय देना चाहते हैं, उन मुद्दों पर पीछे हटने के लिए जिन पर उनकी सरकार जनता के खिलाफ नजर आती है, तो वे काफी विनम्र रहते हैं. लेकिन, ठीक उसी समय वे काफी सावधानी बरतते हैं कि कोई और उसका श्रेय न लूट ले. उन्होंने हर उस चीज को बेअसर कर दिया जो उनके लिए नकारात्मक रूप से बड़ा मसला बन सकता था. साथ ही साथ वे इस बात से भी वाकिफ हैं कि किसी अन्य व्यक्ति या पार्टी को इसका राजनैतिक फायदा नहीं हुआ क्योंकि इन आंदोलनों का नेतृत्व बिखरा हुआ था.

● आपने कई राजनेताओं को सलाह दी है. कामयाब नेताओं की आखिर क्या विशेषताएं होती हैं?

आपको बुद्धिमान होना चाहिए, आप चरित्रवान हों और आपमें साहस होना चाहिए. मैं इसे और विस्तार से समझाता हूं. आप कम बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन आपके पास बुद्धिमान सलाहकार होने चाहिए ताकि आप उस कमी को पूरी कर सकें. राजनीति में चरित्र काफी महत्वपूर्ण होता है. साहस के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते, इसका कोई विकल्प नहीं है. आपमें परखे जाने, टिप्पणी और तारीफ के साथ-साथ आलोचना सुनने का साहस होना चाहिए—साहस एक अनोखी चीज है जो नेता को तैयार करती है.

● और आखिर में रणनीतिकार के रूप में आपकी कामयाबी का क्या मंत्र है?

एक बात तो यह कि हमें बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है. आप चाहे कितने भी होशियार क्यों न हों, आप किसी को हार या जीत नहीं दिला सकते. पार्टियां या नेता अपने प्रदर्शन, अपने पिछले कामकाज और जनता को की गई पेशकश के अलावा इस आधार पर जीतती-हारती हैं कि लोग उनमें क्या देखते हैं. हाशिये पर मौजूद हम जैसे लोग बस आपको खुद को व्यवस्थित करने और आपकी चीजों को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं. इन सीमाओं के साथ, संक्षेप में कहें तो हमारा काम अधिक से अधिक लोगों को सुनना, उसके इर्द-गिर्द तर्कसंगत नैरेटिव गढ़ना और नेता को उसे अपने नैरेटिव या प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार करने देना है. हम लोग इस कहावत को सुनते हुए बड़े हुए हैं कि राजा भेष बदलकर निकले तो उन्हें पता चला. इसका लब्बोलुबाब सदियों से चली आ रही यह धारणा है कि राजा के लिए सबसे कठिन काम यह जानना है कि आखिर जमीनी स्तर पर जनता क्या कह रही है. हम बस बढ़ा-चढ़ा कर पेश किए गए कुशल श्रोता हैं, हम जो सुनते हैं उसका तर्कसंगत अर्थ निकाल सकते हैं और सुसंगत रणनीतियां बना सकते हैं.■

एक्सप्रेसवे प्रदेश बन

वर्ष 2017 से पहले यूपी में केवल दो ही एक्सप्रेसवे थे. मार्च, 2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ''सबका साथ-सबका विकास'' के मंत्र को आत्मसात करते हुए एक ऐसे प्रदेश की संकल्पना की जिसका हर क्षेत्र एक्सप्रेसवे की जद में हो. विकास का क्षेत्रीय संतुलन बनाते हुए मुख्यमंत्री योगी ने हर अंचल को एक्सप्रेस रफ्तार देने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और फिर गंगा एक्सप्रेसवे का खाका खींचा. मुख्यमंत्री योगी की निगरानी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवेलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने एक साथ कई एक्सप्रेसवे को आकार देना शुरू किया. मुख्यमंत्री योगी की सतत निगरानी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो चुका है. बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का काम भी पूरा होने को है. गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जमीन का इंतजाम करीब-करीब पूरा हो चुका है. किसी भी मुख्यमंत्री के एक शासनकाल में इतने एक्सप्रेसवे तैयार होने की मिसाल पहले कभी नहीं दिखी है. इन एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी में विकास ने भी ''लैंडिंग'' शुरू कर दी है.

प्रप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में 16 नवंबर को लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करते ही बहुत बड़ी आबादी की मानों इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं. इन्हीं में से एक रश्मि पटेल, 26, भी हैं. बिहार सीमा पर मौजूद गाजीपुर जिले मोहम्मदाबाद इलाके की रहने वाली रश्मि लखनऊ से सुल्तानपुर रोड पर चंकगंजरिया इलाके में एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलेपर के पद पर कार्यरत हैं. कोविड की दूसरी लहर में अपने पिता को खोने वाली रश्मि इकलौती मां और दो छोटे भाईयों को गाजीपुर में घर पर छोड़कर जुलाई के पहले हफ्ते में लखनऊ आ गई थीं. इसके बाद से रश्मि एक बार भी गाजीपुर नहीं जा पायी थीं. 20 नवंबर को आफिस का काम निबटा कर रश्मि अपने दोस्तों के साथ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए चार घंटे में गाजीपुर पहुंच गईं. रविवार को घर पर रह कर सोमवार की सुबह पांच बजे गाजीपुर से चल कर अपने आफिस पहुंच गईं. उत्साहित रश्मि बताती हैं ''ट्रेन से गाजीपुर जाने में नौ घंटे लगता है और सफर की थकान भी ज्यादा होती है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनने से पहले सड़क मार्ग से गाजीपुर जाने में 13 से 14 घंटे लग जाते थे. मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि चार घंटे में लखनऊ से गाजीपुर पहुंच जाउंगी. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से यह सपना पूरा रहो गया है. अब मैं छुट्टी होते ही गाजीपुर चली जाया करूंगी'' पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रश्मि जैसे करोड़ों लोगों के लिए एक सौगात लेकर आया है. हर छोटी बड़ी आवश्यकता के लिए बड़े शहरों का रुख करने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश की करीब 13 करोड़ जनता के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम सबित नहीं होगा. यह प्रदेश में विकास और अर्थव्यवस्था को एक नई पहचान दिलाने के साथ औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए भी उत्प्रेरक का काम करेगा.

> **''सोचा नहीं था कि तीन साल पहले जिस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, एक दिन खुद उसपर विमान से उतरूंगा. यह यूपी की शान है. इसे यूपी के लोगों को समर्पित करते हुए खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं.''**
>
> *– नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री*

की गरिमामयी उपस्थिति में
मंगलवार, दिनांक 16 नवम्बर 2021 विक्रम सम्वत् 2078, शक सम्वत् 1943, कार्तिक मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी को सम्पन्न हुआ।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा)

रहा है उत्तर प्रदेश

सुल्तानपुर, आजमगढ़, गाजीपुर
Sultanpur, Azamgarh, Ghazipur

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

लंबाई **341** किमी

प्रवेश बिंदु

लखनऊ के गांव चांदसराय से

लाभान्वित जिले

लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, आंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर

अंतिम निकास बिंदु

गाजीपुर का ग्राम हैदरिया

> ‘‘तीन साल पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हुआ था. इस तीन साल में 19 महीने कोरोना महामारी का सामना करने के बावजूद राज्य सरकार ने जीवन और जीविका को बचाते हुए नियत समय से पहले एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया है’’
>
> *–योगी आदित्यनाथ,*
> *मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश*

अनोखा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे

एक्सप्रेसवे छह लेन चौड़ा (आठ लेन विस्तारणीय) है तथा संरचनाएं आठ लेन में विकसित की गई हैं. एक्सप्रेसवे के एक ओर 3.75 मीटर की सर्विस लेन बनाई गई है जिससे आसपास के निवासियों को सुगम आवागमन की सुविधा हो.

मेन कैरिजवे पर कुल 18 फ्लाई ओवर, 07 रेलवे ओवर ब्रिज, 07 दीर्घ सेतु, 114 लघु सेतु, 13 इंटरचेंज (07 टोल प्लाजा समेत, 06 रैंप प्लाजा), 271 अंडर पास तथा 525 पुलियों का निर्माण किया गया है. सुल्तानपुर में 3.2 किमी लंबी हवाई पट्टी भी है.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में सड़क के दोनों ओर ढाल पर (नदी के किनारे या पानी वाले इलाकों को छोड़ कर) पत्थर नहीं लगाए गए हैं. इनकी जगह मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति वाले प्लास्टिक के बने ‘जियो सेल्स’ का प्रयोग किया गया है.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कूड़ेभार इलाके में एक 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई गई है. इसकी खासियत यह है कि हवाई पट्टी के नीचे दो लघु सेतू भी हैं. यह देश की पहली हवाई पट्टी है जो पुलों पर मौजूद है.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में बनने वाली सड़क की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए इसमें सामान्य बिटुमेन की जगह रबर के टुकड़े मिले ‘क्रंब रबर मोडिफाइड बिटुमेन का प्रयोग किया गया है. इससे सड़क लंबे समय तक खराब नहीं हो पाती.

रबर के अलावा कुछ जगहों पर पॉलिमर मिले हुए बिटुमेन का भी उपयोग किया गया है. रबर और पॉलिमर पानी नहीं टिकने देते हैं जिससे सड़क जल्दी खराब नहीं होती है और इस पर गाड़ियां भी नहीं फिसलती हैं

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में मीडियन (आने व जाने वाली सड़क के बीच की जगह) के दोनों किनारों पर भी ‘क्रैश बैरियर’ लगाए गए हैं. क्रैश बैरियर से गाड़ी टकराने पर उसके दूसरी ओर जाकर पलटने का खतरा न के बराबर रहता है.

एक्सप्रेसवे पर चलने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए हर पैकेज पर 112 की गाड़ियां मौजूद रहेंगी. साथ ही हर पैकेज पर 02-02 एंबुलेंस समेत कुल 16 एंबुलेंस तैनात की गई है.

इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) मोड पर बने एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने के कारण ईंधन व समय की बचत होगी और साथ में यह प्रदूषण नियंत्रण में मदद करेगा. साथ ही इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी कम हो जाती है.

आठ पैकेज में बन कर तैयार हुए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के हर सेक्टर में एक आधुनिक लैब भी तैयार की गई थी. जिसमें सभी निर्माण सामग्रियों की गुणवत्ता और मजबूती जांच कर ही उन्हें प्रयोग में लाया गया है.

पूर्वांचल को मिला तरक्की का एक्सप्रेसवे

किसी भी क्षेत्र के विकास का सीधा जुड़ाव वहां के आधाभूत ढांचे से होता है. सुगम सड़कें ही सुगम व्यापार की पहली शर्त हैं. इन सभी कसौटी पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरी तरह से खरा उतरता है. इस एक्सप्रेसवे ने केवल पूर्वांचल में तरक्की की राह खोल दी है बल्कि पूरे प्रदेश में विकास के एक नए अध्याय की शरुआत भी की है.

मजबूत अर्थव्यवस्था

योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल में अर्थव्यवस्था के मजबूत प्लेटफार्म के रूप में तैयार किया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उद्योग, व्यापार, रोजगार और विकास के एक्सप्रेसवे के तौर पर तैयार किय गया है.

कारोबारी गतिविधियां

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले जनपदों में कारोबारी गतिविधियों को नया विस्तार देने के साथ ही एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स स्थापित कर स्थानीय श्रम शक्ति को भी सेवायोजित किया जाएगा. इसके लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास पांच इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स विकसित किए जा रहे हैं. नौ हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि चिन्हित भी की गई है.

कृषि अर्थव्यवस्था

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के दायरे में आने वाले अधिकांश जिले कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं, इसलिए इंडस्ट्रियल क्लस्टर में पहली प्राथमिकता फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स पर है. इसके साथ ही टेक्सटाइल, रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पाद, बेवरेज, केमिकल, मेडिकल उपकरणों से जुड़ी फैक्ट्रियां भी स्थापित होंगी. इन फैक्ट्रियों में स्थानीय श्रम शक्ति को रोजगार मिल सके, इसके लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर उन्हें प्रशिक्षित भी किया जाएगा.

सुदूर कनेक्टिविटी

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को निर्माणाधीन गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और बलिया लिंक एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा. दो लिंक एक्सप्रेसवे से जोड़कर पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की रफ्तार तीन गुना और बढ़ाई जाएगी. इससे गोरखपुर, संतकबीर नगर, बलिया समेत करीब आधा दर्जन अतिरिक्त जिले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएंगे.

दिल्ली तक पहुंच

पूर्वांचल एक्सएप्रेसवे को आउटर रिंग रोड के जरिये लखनऊ में आगरा एक्सदप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. निर्माणाधीन आउटर रिंग रोड पूर्वांचल एक्सरप्रेसवे और लखनऊ आगरा एक्सदप्रेसवे को मोहान और सुल्तान पुर रोड के पास कनेक्टं करेगा. आगरा एक्सप्रेसवे के जरिये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे लोग सीधे दिल्ली पहुंच सकेंगे. इस तरह यह औद्योगिक विकास का प्रवेश द्वार साबित होगा.

बिहार को फायदा

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से न केवल यूपी बल्कि बिहार के लोगों को भी काफी फायदा होगा. इससे दिल्ली से बिहार तक का सफर आसान हो गया है. पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एक छोर गाजीपुर से बिहार की सीमा केवल 18 किलोमीटर दूर है. बिहार की जनता भी पूर्वाचल एक्सप्रेसवे के जरिए काफी कम समय में आसानी से दिल्ली जा सकेगी.

रोजगार के अवसर

एक्सप्रेसवे के नजदीकी क्षेत्रों में औघोगिक प्रशिक्षण संस्थान, शैक्षिक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान और विभिन्न वाणिज्यिक केंद्रों को स्थापित किया जाएगा. इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इसके साथ ही प्रदेश के सामाजिक और आर्थिक विकास की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाएंगी.

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के आसपास औद्योगिक गलियारे की जगह

जिला	उद्योग	चिन्हित स्थान
बाराबंकी	खाद्य उत्पाद, काष्ठ, दवा	02
अमेठी	खाद्य उत्पाद	02
सुल्तानपुर	खाद्य उत्पाद	02
जौनपुर	टेक्सटाइल	02
आजमगढ़	खाद्य उत्पाद	02
गाजीपुर	खाद्य उत्पाद	02
मऊ	खाद्य उत्पाद	02
अयोध्या	फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट	01
संतकबीर नगर	खाद्य उत्पाद	02
गोरखपुर	मेटल डेंटल उपकरण	02
आंबेडकरनगर	टेक्सटाइल	02
बलिया	खाद्य प्रसंस्करण	01

पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश में बिछ रहा एक्सप्रेसवे का जाल

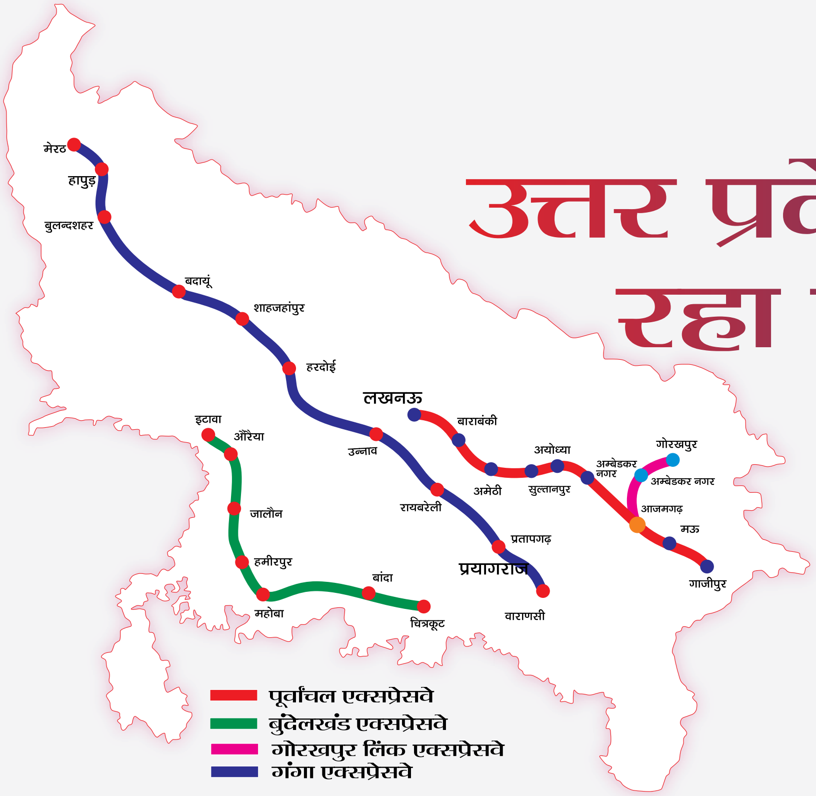
मेरठ
हापुड़
बुलन्दशहर
बदायूं
शाहजहांपुर
हरदोई
लखनऊ
बाराबंकी
इटावा
औरैया
उन्नाव
अयोध्या
गोरखपुर
अम्बेडकर नगर
अम्बेडकर नगर
अमेठी
सुल्तानपुर
जालौन
रायबरेली
आजमगढ़
मऊ
प्रतापगढ़
हमीरपुर
प्रयागराज
गाजीपुर
बांदा
महोबा
चित्रकूट
वाराणसी
🟥 पूर्वांचल एक्सप्रेसवे
🟩 बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे
🟪 गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे
🟦 गंगा एक्सप्रेसवे

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे

लाभान्वित जिले: गोरखपुर बाइपास के गांव जैतपुर से शुरू होकर आंबेडकरनगर, संतकबीरनगर होता हुआ आजमगढ़ में पूर्वांचल एकसप्रेसवे पर समाप्त होगा.

लंबाई
91.4
किलोमीटर

विशेषता: चार लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे जिसे छह लेन तक बढ़ाया जा सकता है. एक्सप्रेसवे के एक ओर पूरी लंबाई में (बड़े पुल को छोड़कर) सर्विस रोड की व्यवस्था.

वर्तमान स्थिति-एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 30 प्रतिशत पूरा

परियोजना से लाभ: एक्सप्रेसवे के निर्माण से गोरखपुर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा. परियोजना से अच्छादित क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ ही कृषि पर्यटन तथा उद्योगों की आय को बढ़ावा मिलेगा.

- ↗ यह गोरखपुर और लखनऊ के बीच एक मार्ग बनेगा. इस एक्सप्रेसवे से नेपाल की कनेक्टिविटी भी आसान होगी.
- ↗ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे से कृषि आधारित उद्योगो के लिए माहौल तैयार होगा. पूर्वी जिलों को इसका काफी फायदा मिलेगा.

गंगा एक्सप्रेसवे

लाभान्वित जिले: मेरठ-बुलंदशहर मार्ग एनएच-334 से शुरू होकर बुलंदशहर, अमरोहा, सम्भल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से प्रयागराज तक.

लंबाई
594
किलोमीटर

विशेषता: देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, छह लेन चौड़ा जिसे बाद में आठ लेन चौड़ा किया जा सकता है. गंगा, रामगंगा, नदियों पर कुल पांच बड़े पुल.

वर्तमान स्थिति 93 फीसदी जमीन खरीदी जा चुकी है.

परियोजना से लाभ: गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से पश्चिम के उद्योगों के लिए पूर्वी जिलों से व्यापार करना सुलभ हो जाएगा. पूर्वी उत्तर प्रदेश में पर्यटन और रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे.

- ↗ गंगा एक्सप्रेसवे से छह घंटे में दिल्ली से प्रयागराज पहुचा जा सकेगा. इससे प्रयागराज हाइकोर्ट आने वाले लोगों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को काफी लाभ होगा.
- ↗ गंगा एक्सप्रेसवे यूपी के सड़क संपर्क को रफ्तार देगा और इससे आर्थियक विकास का एक सकारात्मक महौल तैयार होगा.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

लाभान्वित जिले: चित्रकूट के भरतकूप से शुरु होकर बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरेया होते हुए इटावा में कुडरैल के पास आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे तक.

लंबाई
296.070
किलोमीटर

विशेषता: प्रवेश नियंत्रित एक्सप्रेसवे, चार लेन चौड़ा जिसे छह लेन बढ़ाया जा सकता है. संपूर्ण एक्सप्रेसवे के एक तरफ सर्विसलेन.

वर्तमान स्थिति-एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत पूरा

परियोजना से लाभ: बुंदेलखंड आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा. इससे बुन्देलखण्ड क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा.

- ↗ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे डिफेंस कॉरिडोर के लिए बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा. इससे बड़े पैमाने पर रक्षा उत्पादों का निर्माण करने वाली फर्म बुंदेलखंड में निवेश के लिए आकर्षित होंगी.
- ↗ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हथकरघा उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, भंडारण, दूध पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे

मयंक मखीजा/एएफपी

SAMPLE COLLECTION BOOTH
DELHI INDIRA GANDHI INTERNATIONAL AIRPORT
GMR
INDIA'S FIRST AIRPORT COVID TESTING LAB @ IGI AIRPORT, DELHI
Quarantine the Virus
NABL & ICMR Approved Testing Partner
GENESTRINGS
DIAGNOSTIC CENTRE
A YASHODA HOSPITALS GHAZIABAD GROUP COMPANY
91 9717 300 900

सुरक्षा के वास्ते
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोविड जांच बूथ

खास रपट

ओमिक्रॉन

इधर भी हो रही पूरी तैयारी

कोविड का नया चिंताजनक वैरिएंट ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है लेकिन अब तक इसके कोई गंभीर लक्षण या फिर इससे मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है. फिर भी रहना होगा पूरी तरह चौकन्ना

सोनाली आचार्जी

भारत में ओमिक्रॉन के मामले

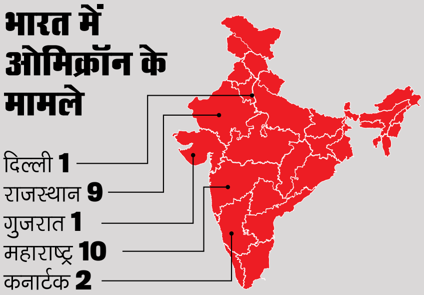

देश में इसकी चाल अभी दबी दबी-सी

- पिछले एक हफ्ते में ओमिक्रॉन के मामलों में सात गुना वृद्धि हुई है
- हालांकि, भारत में सक्रिय मामले घट रहे हैं और बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर (आर नंबर) अभी भी 1 से कम है. यह संकेत करता है कि प्रसार अभी भी सीमित है

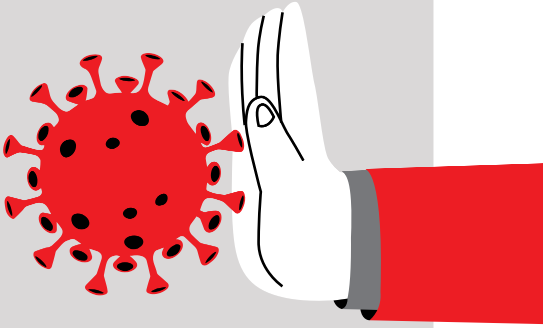

नया वायरस, नए नियम

ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए राज्य कई कड़े कदम उठा रहे हैं

दिल्ली: सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच हो रही. कम से कम पहला टीका लगवा चुके लोगों को ही सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश देने पर विचार चल रहा. प्रमुख कोविड देखभाल केंद्र फिर सक्रिय किए जा रहे. ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता को चाक-चौबंद किया जा रहा

राजस्थान: अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की जांच होगी और कोविड लक्षणों के लिए 16 दिनों तक उनकी निगरानी होगी. प्रमुख कोविड केंद्रों को फिर से शुरू किया गया है. कोविड हॉटस्पॉट इलाकों में कर्फ्यू लगेगा. सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य किया जा चुका है

गुजरात: आठ शहरों में रात्रि कर्फ्यू बढ़ा, रेस्तरां 75 फीसद क्षमता के साथ आधी रात तक ही खुल सकेंगे. सभी आयोजनों में सिर्फ 400 लोग जमा हो सकते हैं. सिनेमा हॉल में केवल 100 लोगों की अनुमति. सभी यात्रियों की जांच और पॉजिटिव मिलने पर क्वारंटीन होंगे

महाराष्ट्र: पूरी आबादी का टीकाकरण. सार्वजनिक जगहों पर मास्क और दूरी अनिवार्य. राज्य में आने वाले सभी यात्रियों को कोविड निगेटिव टेस्ट दिखाना होगा, 'खतरे की आशंका' वाले देशों से आए यात्रियों की जांच होगी और उन्हें क्वारंटीन रहना होगा

कर्नाटक: सिर्फ वही छात्र स्कूल आ सकेंगे जिनके मां-बाप ने दोनों खुराक ले ली है. दोनों खुराक ले चुके लोग ही मॉल और सिनेमा हॉल जा सकेंगे, सभी आयोजनों में सिर्फ 500 लोगों तक की अनुमति. राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य जांच

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

भारत में 7 दिसंबर को 24 घंटे में कोविड-19 के 6,822 नए मामले सामने आए और 200 मौतें दर्ज की गईं. यह पिछले 18 महीनों में एक दिन की सबसे कम बढ़ोत्तरी थी. फिलहाल सक्रिय मामले 95,014 हैं जो पिछले 554 दिनों में सबसे कम हैं. फिर भी, देशभर के सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी राहत की सांस लेने के बजाय एक बार फिर लड़ाई के लिए कमर कस रहे हैं. भारत में जब से कोविड के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों की पुष्टि हुई है, केंद्र और राज्य सरकारें भी यह पक्का करने के लिए कदम उठा रही हैं कि इसका प्रसार यथासंभव कम रहे. डेल्टा वैरिएंट को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए गए थे. नतीजा: हालात बेकाबू हो गए थे. कोई नहीं चाहता कि उस तरह के हालात फिर से बनें. मिसाल के तौर पर, दिल्ली के शाहदरा में दिल्ली पुलिस वालों के लिए आरक्षित एक कोविड देखभाल केंद्र को फिर से शुरू किया गया है. इसके 78 बिस्तरों को झाड़-पोंछकर दुरुस्त किया गया है और 20 बिस्तरों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है. इससे थोड़ी ही दूरी पर राजधानी के सबसे बड़े कोविड अस्पताल लोकनायक जय प्रकाश (एलएनजेपी) नारायण अस्पताल ने भी बिस्तरों और ऑक्सीजन की स्थिति का जायजा लेना शुरू कर दिया है. एलएनजेपी के निदेशक सुरेश कुमार बताते हैं, ''हम कोई जोखिम नहीं लेना चाहते. कोविड के मामले में तैयार रहना हमेशा बेहतर होता है. उछाल अचानक और अप्रत्याशित हो सकता है. यहां तक कि जब आप फैलाव रोकने की दिशा में काम करते हैं तो आपको प्रसार के लिए भी तैयार रहना चाहिए.''

ओमिक्रॉन तेजी से फैला है. 3 दिसंबर को कर्नाटक में पहली बार इसके दो मामलों का पता चला. उसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में मामले सामने आने के साथ ही चार दिनों में ही इनकी संख्या सात गुना बढ़कर 23 हो गई. राज्यों ने पूर्ण लॉकडाउन लगाने से मना किया है, पर प्रसार को रोकने के लिए दूसरे उपाय किए

> **‘‘कोविड पहले की तरह फैल नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास रोकथाम और इलाज के वास्ते नए विकल्प हैं. इसलिए अधिक संक्रामक बनकर यह एक तरह से हमारे साथ रहना सीख रहा है’’**
>
> **—डॉ. श्रीनाथ रेड्डी**
>
> *अध्यक्ष, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया*

हैं. मसलन, कर्नाटक में टीके की दोनों खुराक ले चुके माता-पिता के बच्चों को ही स्कूल आकर क्लास में शामिल होने की अनुमति होगी. महाराष्ट्र में दोनों खुराक ले चुके लोग ही पार्क और सरकारी बसों जैसे सार्वजनिक स्थानों और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं. गुजरात ने रात का कर्फ्यू आठ शहरों तक बढ़ा दिया है और राजस्थान ने सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य कर दिया है. राज्यों ने लोगों के जमावड़े पर अंकुश लगाया है और स्थानीय तथा विदेशी यात्रियों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं. माइक्रोबायोलॉजिस्ट और वायरोलॉजिस्ट डॉ. गगनदीप कंग कहती हैं, ‘‘कर्नाटक में ओमिक्रॉन के और मामले मौजूद हो सकते हैं जिनका हमें पता न चल पाया हो क्योंकि वहां एक ऐसे शख्स में यह मामला सामने आया जिसकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी. हमें तत्काल समझ जाना चाहिए कि यह वैरिएंट कितनी तेजी से फैलता है, इसके लक्षण कितने गंभीर हैं और हम लोगों को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं.’’

शोधकर्ता इस बात से चिंतित हैं कि ओमिक्रॉन के स्पाइक प्रोटीन (इसके अकेले प्रोटीन बाइंडिंग रिसेप्टर में ही डेल्टा स्ट्रेन की तुलना में आठ अधिक म्यूटेशन हैं. डेल्टा स्ट्रेन भारत की घातक दूसरी लहर का कारण बना था) में म्यूटेशन उसको टीके या कोविड के खिलाफ प्राकृतिक रूप से प्राप्त प्रतिरक्षा के सामने अधिक ताकतवर बना देगा. पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका में शोधकर्ताओं के एक समूह ने एक अध्ययन पोस्ट किया जिसमें पाया गया कि बीटा और डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन के फिर से संक्रमण का जोखिम 2.4 गुना ज्यादा है. भारत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आइएमए) ने चेतावनी दी कि यदि जरूरी सावधानी नहीं बरती गई तो देश में कोविड की तीसरी लहर आ सकती है. नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 (एनईजीवीएसी) के चेयरमैन डॉ. वी.के. पॉल कहते हैं, ‘‘ओमिक्रॉन से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना जरूरी है. सक्रिय मामलों में गिरावट के साथ मास्क का उपयोग कम हुआ है. लोगों को कोविड संबंधी उपयुक्त व्यवहार पर वापस जाने की जरूरत है.’’

ओमिक्रॉन का प्रसार रोकना आखिर क्यों इतना अहम है

लक्षणों की शुरुआती रिपोर्ट्स इशारा करती हैं कि ओमिक्रॉन से लोग गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ेंगे. दुनिया में अभी तक इस वैरिएंट से किसी की जान जाने की खबर नहीं है. दिल्ली के मणिपाल अस्पताल की संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकिता वैद्य कहती हैं, ‘‘लगता है, यह मुख्य रूप से ऊपरी श्वसन तंत्र को संक्रमित करता है और डेल्टा वैरिएंट की तरह निचले श्वसन तंत्र में समस्या नहीं पैदा करता.’’ महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 10 मामले सामने आए और इनमें किसी को ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ी. फोर्टिस मुंबई में क्रिटिकल केयर मेडिसन और आइसीयू के निदेशक तथा राज्य के कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉ. राहुल पंडित कहते हैं, ‘‘हम ज्यादातर थकान, खांसी और थोड़े हल्के बुखार की रिपोर्ट सुन रहे हैं. दवा, आराम और हल्के आहार से इन लक्षणों का इलाज हो सकता है.’’ वे कहते हैं कि दूसरी लहर के विपरीत, देश में अब उन लोगों के लिए ऐंटीबॉडी कॉकटेल का विकल्प उपलब्ध है जिनके गंभीर रूप से बीमार पड़ने का सर्वाधिक खतरा है. वे बताते हैं, ‘‘अहम बात यह है कि लोग जांच कराएं और इलाज के लिए जल्दी आएं.’’

ओमिक्रॉन से लोग भले ही गंभीर रूप से बीमार न पड़ें पर विशेषज्ञ जोर देते हैं कि संक्रमण दर कम रखना होगा. बेंगलूरू स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर जेनेटिक्स ऐंड सोसाइटी के निदेशक और इंडियन सार्स-कोविड-2 जीनोम सीक्वेंसिंग कंसोर्टिया (आइएनएसएसीओजी) के सदस्य डॉ. राकेश मिश्र कहते हैं, ‘‘हर बार जब कोई वायरस फैलता है तो उसके म्यूटेट होने की संभावना रहती है. नए स्ट्रेन संभवतः पहले के स्ट्रेन के खिलाफ बनाए गए टीकों से बच सकते हैं. इसलिए प्रसार को कम रखना जरूरी है.’’ विशेषज्ञ बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के नए स्ट्रेन से संक्रमित होने के खतरों को लेकर भी चिंतित हैं. डॉ. कंग कहती हैं, ‘‘सभी कोरोनावायरस में लोगों को फिर से संक्रमित करने की क्षमता होती है. अगर पुनः संक्रमण हल्के होते हैं, तो यह चिंता की बात नहीं है. पर जिन लोगों ने टीका नहीं लिया है या जो गंभीर बीमारी के उच्च जोखिम में हैं, उन पर ओमिक्रॉन का असर क्या होगा, यह चिंता का विषय है. फिलहाल हम यह नहीं जानते.’’ भारत में 7 दिसंबर तक लगभग 48.6 करोड़ वयस्कों यानी देश की कुल वयस्क आबादी के लगभग आधे ने टीके की दोनों खुराक ले ली है. सरकार जोर दे रही है कि सभी लोगों का टीकाकरण अभी उसकी प्राथमिकता है, लेकिन कई विशेषज्ञों ने ओमिक्रॉन सरीखे नए स्ट्रेन के असर को कम करने के लिए बूस्टर खुराक की सिफारिश करनी शुरू कर दी है.

कितनी उपयोगी होगी बूस्टर खुराक?

दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया कहते हैं, ‘‘कोरोनावायरस के नए वैरिएंट के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में कथित रूप से 30 से अधिक म्यूटेशन हैं और इसलिए इसमें प्रतिरक्षा से बच निकलने की क्षमता होने की संभावना है. अधिकतर स्ट्रेन स्पाइक प्रोटीन पर निशाना साधते हैं, ऐसे में स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में इतने सारे म्यूटेशन टीकों का असर कम कर सकते हैं.’’ लेकिन अभी इस बार में पक्के तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता.

दक्षिण अफ्रीका में सरकार ने 2 दिसंबर को रिपोर्ट दी कि नवंबर में जिन 249 वायरस जीनोम की सिक्वेंसिंग की गई, उनमें से 74 फीसद मामले ओमिक्रॉन के थे. इससे संकेत दिया गया कि देश में ओमिक्रॉन ने पहले ही डेल्टा की जगह ले ली है. लेकिन, दक्षिण अफ्रीका में टीकाकरण की दर सिर्फ 25 फीसद है. विशेषज्ञों के मुताबिक, ओमिक्रॉन पर मौजूदा टीके कितने असरदार हैं, इसका आकलन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका के आंकड़े पर्याप्त नहीं हैं. आने वाले हफ्तों में विभिन्न न्यूट्रलाइजेशन अध्ययनों के नतीजे वैज्ञानिकों को इस बात का बेहतर अंदाजा लगाने में मदद कर सकते हैं कि ओमिक्रॉन मौजूदा टीकों से किस हद तक बच सकता है. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) के

FROM THOSE WIELDING PENS TO THOSE HOLDING GAVELS

We believe in just one thing.

Your voice matters. Irrespective of who you are, where you come from, where you stand, what you do, and who you support.

We are the **India Today Group.**

Where every voice finds its right.

And every right finds a voice.

WE'RE ALWAYS IN CONVERSATION WITH YOU.

INDIA
TODAY
GROUP

INDIA'S DEMOCRATIC NEWSROOM

ओमिक्रॉन के प्रमुख लक्षण

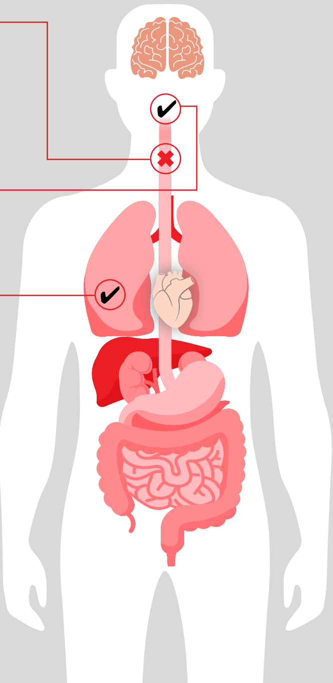

- जुकाम, खांसी और बुखारः ओमिक्रॉन के ये सबसे सामान्य लक्षण हैं जो गंभीर नहीं और ऊपरी श्वसन तंत्र में ही दिखे
- अभी तक गंध और स्वाद के चले जाने के मामले सामने नहीं आए हैं
- डेल्टा वैरिएंट के विपरीत, शुरुआती अध्ययन बताते हैं कि नए स्ट्रेन से निचले श्वसन तंत्र में समस्या नहीं हो रही है, इससे संकेत मिलता है कि ओमिक्रॉन से संक्रमित व्यक्ति की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी
- दुनिया में कहीं भी अभी ओमिक्रॉन से किसी की मौत की सूचना नहीं है

ओमिक्रॉन के इलाज से संबंधित विकल्प

- इलाज मुख्य तौर पर लक्षण आधारित ही होगा, आराम के साथ दवाएं और पोषक तत्वों से युक्त हल्का भोजन
- भारत में कोविड दवा की गोलियां (मर्क गोलियां या ओरल ऐंटीवायरल मोलनुपिराविर और फाइजर की एक नई गोली) अभी तक उपलब्ध नहीं
- मोनोक्लोनर ऐंटीबॉडी कॉकटेल का एक विकल्प उपलब्ध है. यह लक्षण वाले कोविड के खतरे को 77 फीसद कम कर देता है
- लक्षण शुरू होने के एक हफ्ते के भीतर ऐंटीबॉडी कॉकटेल को लेना होगा. बुजुर्गों और अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए यह कहीं ज्यादा अनुशंसित विकल्प है. हालांकि इसकी कीमत 60,000 रुपए है जो काफी ज्यादा है

महानिदेशक बलराम भार्गव का कहना है कि नए स्ट्रेन के खिलाफ टीकों के असर पर टिप्पणी करना अभी जल्दबाजी होगी. उनका कहना है, ''अभी हम नए वैरिएंट को अलग कर रहे हैं. फिर, इसके खिलाफ टीका कितना असरदार है, यह पता लगाने के लिए इसे प्रयोगशाला में रखा जाएगा और इसका परीक्षण किया जाएगा.''

कुछ अटकलें बरकरार हैं. मसलन यही कि नए स्ट्रेन की वजह से गंभीर रूप से बीमार पड़ने से रोकने में कोवैक्सीन असरदार बना रहेगा. कोवैक्सीन दरअसल, संक्रमण के खिलाफ शरीर को तैयार करने के लिए कोविड के स्पाइक प्रोटीन (वायरस का वह हिस्सा जिसमें ओमिक्रॉन में सबसे अधिक परिवर्तन देखा गया है) का उपयोग नहीं करता. डॉ. पॉल कहते हैं, ''अभी सबसे अहम बात यह पक्का करना है कि सभी पात्र नागरिकों को कोविड टीके की पूरी खुराक मिल जाए.'' फिलहाल सरकार ने बूस्टर खुराक देने से मना किया है. पर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बुजुर्गों को तीसरी खुराक दी जानी चाहिए. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की रिपोर्ट 'एल्डरली इन इंडिया 2021' के मुताबिक, देश में बुजुर्ग आबादी अभी 13.8 करोड़ है. डॉक्टरों का कहना है कि अगर इस आबादी का आधा हिस्सा भी कोविड से गंभीर रूप से संक्रमित हुआ तो देश का मौजूदा स्वास्थ्य ढांचा चरमरा जाएगा. इसके अलावा, अभी इसके सबसे प्रभावी इलाज ऐंटीबॉडी कॉकटेल की कीमत 60,000 रुपए है और यह अधिकतर भारतीयों की पहुंच से बाहर है. डॉ. कंग कहती हैं, ''कमजोर लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बूस्टर दिया जाना चाहिए. दो या तीन खुराक देने में बुजुर्गों को तुरंत प्राथमिकता दी जानी चाहिए.''

ओमिक्रॉन कोविड के आम बीमारी बनने का संकेत है?

विशेषज्ञों का कहना है कि जिस तरह इसका म्यूटेशन हो रहा है, वह शुरुआती संकेत है कि सार्स-कोविड-2 वायरस खुद को नई परिस्थितियों—टीका या प्राकृतिक रूप से विकसित प्रतिरक्षा और लोगों के मास्क पहनने—के अनुकूल बना रहा है. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया (पीएचएफआइ) के अध्यक्ष डॉ. श्रीनाथ रेड्डी कहते हैं, ''कोविड पहले की तरह फैल नहीं पा रहा है क्योंकि हमारे पास रोकथाम और इलाज के लिए नए उपकरण हैं. सो, यह अधिक संक्रामक बनकर अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखने के लिए एक तरह से हमारे साथ रहना सीख रहा है.''

दिलचस्प यह है कि बायोमेडिकल सूचनाओं का विश्लेषण करने वाली फर्म एनफेरेंस ने अपने एक अध्ययन में पाया है कि ओमिक्रॉन ने सामान्य जुकाम के वायरस से आनुवांशिक सामग्री को ले लिया है. ऐसी अटकलें हैं कि इस तरह का निशान नए स्ट्रेन के ज्यादा ताकतवर होने का एक कारण हो सकता है. डॉ. मिश्र कहते हैं, ''हमारी नई निवारक तकनीकों के कारण पुराने स्ट्रेन जीवित नहीं रह सकते और अधिक संक्रामक स्ट्रेन आखिरकार उन पुराने स्ट्रेन की जगह ले लेंगे.'' इस तरह से विशेषज्ञों के मुताबिक, सबसे अच्छी स्थिति में ओमिक्रॉन कोविड के नए रूप में बदल जाने का संकेत दे रहा है—एक ऐसे रूप में जो ज्यादा संक्रामक होगा पर ज्यादा नुक्सानदेह नहीं होगा और सामान्य जुकाम की तरह होगा. वैसे, नए स्ट्रेन ने विविध प्रकार की आबादी को अभी संक्रमित नहीं किया है और डॉक्टरों का कहना है कि पक्के तौर पर यह बताना जल्दीबाजी होगी कि ओमिक्रॉन गंभीर रूप से बीमार करेगा या नहीं. जब तक पर्याप्त आंकड़े जमा नहीं हो जाते, उनका विश्लेषण नहीं हो जाता, व्यावहारिक सावधानियां बरतना सबसे बेहतर उपाय है. ■

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

9:41
INDIA TODAY
LIVE
TOP NEWS
VIDEOS
PROGRAMMES
TOP STORIES

LOK SABHA 2019

Narendra Modi Live: By Congress-mukt India we will fulfil Gandhi's dream

PM Narendra Modi was speaking in Lok Sabha

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

किसानों के भरोसे पर खरे उतर रहे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी राज्य के किसानों से जुड़े मुद्दों पर बेहद संवेदनशील हैं. किसानों की हर छोटी से छोटी जरूरतों और समस्याओं पर मुख्यमंत्री की बारीक नजर है. यही वजह है कि मुख्यमंत्री धामी ने न केवल गन्ना किसानों को राहत देते हुए समर्थन मूल्य में इजाफा किया है बल्कि बंद पड़ी चीनी मिल को शुरू करके भी किसानों को सौगात दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों के बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. इसने किसान और मुख्यमंत्री धामी के बीच के रिश्ते को काफी मजबूत किया है.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गन्ने के समर्थन मूल्य में 28 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी कर किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है. अब किसानों को अगैती गन्ने का मूल्य 355 रुपए प्रति क्विंटल व सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 345 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा. उत्तर प्रदेश के 350 रुपए प्रति क्विंटल के सापेक्ष उत्तराखंड में किसानों को अगैती गन्ने पर पांच रुपए अधिक मिलेगा. पिछले 20 वर्षो में पहली बार किसी सरकार ने इतनी बढ़ोतरी की है. राज्य में अभी तक गन्ने की अगैती किस्म पर 317 रुपए प्रति क्विंटल व सामान्य के लिए 317 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को मिल रहा था. साथ ही गन्ना भाड़े में भी कमी की गई है. पिछले वर्षों में क्रय केंद्रों से गन्ना खरीद पर 11 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना भाड़ा किसानों को चुकाना पड़ता था जिसे घटाकर 9.50 रुपए प्रति क्विंटल करने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने की है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लंबे समय से बंद पड़ी ''दि किसान सहकारी चीनी मिल'' सितारगंज को दोबारा शुरू कराया है. 29 नवंबर को मुख्यमंत्री धामी सितारगंज चीनी मिल में पेराई सत्र की शुरुआत की. सितारगंज चीनी मिल चालू होने के साथ विकास का नया अध्याय शुरू हो गया. बाजपुर, किच्छा या बहेड़ी गन्ना लेकर जाने वाले किसानों को अब आसानी होगी. सितारगंज चीनी मिल प्रारंभ होने से पांच हजार हेक्टेयर में गन्ना उत्पादक 25 हजार से ज्यादा किसानों को चीनी मिल का लाभ मिलेगा. उत्तराखंड सरकार गन्ना किसानों को बकाया मूल्य भुगतान करने के लिए भी विशेष प्रयास कर रही है.

उत्तराखंड के सेब को मिलेगी नई पहचान

उत्तराखंड के सेब को नई पहचान दिलाने के लिए धामी सरकार ने 24 सितंबर से पहली बार तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सेब महोत्सव का आयोजन किया. देहरादून के रेंजर कालेज ग्राउंड में आयोजित सेब महोत्सव में सेब के अलग-अलग किस्मों की प्रदर्शनी लगाई गई. इसमें उत्तराखंड समेत हिमाचल और जम्मू कश्मीर के प्रगतिशील किसान उत्पादों को प्रदर्शित किया गया. अभी तक राज्य के कुल सेब उत्पादन का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा देहरादून और उत्तरकाशी से आता है. अब नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, टिहरी और रुद्रप्रयाग में नए बाग विकसित किए जा रहे हैं. उत्तराखंड सेब उत्पादक एवं विपणन सहकारी संघ ने इन जिलों में सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्ययोजना तैयार की है. राज्य समेकित सहकारी विकास परियोजना के तहत 18 सहकारी समितियों का गठन कर इससे करीब 30 हजार किसानों को जोड़ा जाएगा. सातों जिलों में सेब के नए बाग

> **“किसान परिवार से होने के नाते मैं किसानों के दर्द को अच्छी तरह से जानता हूं. किसान हमारे अन्नदाता हैं. किसानों के हित में जो संभव हो, वे निर्णय लिये जाएंगे.”**
>
> *– पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड*

विकसित करने के लिए क्षेत्र में पहले से काम कर रही जम्मू-कश्मीर और हिमाचल की एजेंसियों से अनुबंध किया जाएगा जो किसानों को बाग विकसित करने में हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराएंगी. नए बाग लगाने वाले किसानों को दीन दयाल उपाध्याय कृषि कल्याण योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे किसान अगले तीन साल में चुका सकेंगे. योजना के तहत एक हजार नए बाग लगाए जाएंगे और एक हजार पुराने बागों का सुधारीकरण किया जाएगा. हर जिले में सौ से अधिक बाग लगाने का लक्ष्य है. राज्य में विकसित होने वाले तमाम नए बागों में नई तकनीक के प्रयोग के साथ कम समय में अधिक उत्पादन देने वाले पौधे रोपित किए जाएंगे. इसमें अल्ट्रा हाइडेंसिटी प्लांट लगाए जाएंगे और सीड लिंक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा. इस तकनीक से पौधे 18 माह में फल देने लगते हैं. मुख्यमंत्री धामी ने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सेब मिशन का बजट दोगुना करने की घोषणा की है. अभी तक सेब मिशन का बजट तीन करोड़ है. जिसे बढ़ा कर छह करोड़ किया जाएगा.

माल्टा और गलगल का समर्थन मूल्य भी बढ़ा

धामी सरकार ने गन्ना किसानों के साथ पर्वतीय क्षेत्र के किसानों को राहत देते हुए माल्टा व पहाड़ी नींबू गलगल के समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की है. चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सी-ग्रेड के माल्टा का आठ रुपये प्रति किलो और गलगल का पांच रुपये प्रति किलो समर्थन मूल्य घोषित किया गया है. बीते वर्ष के मुकाबले समर्थन मूल्य में एक रुपये की वृद्धि की गई है. राज्य में इस वर्ष 1000 टन माल्टा की खरीद पर 80 लाख रुपये व गलगल की खरीद पर 25 लाख रुपये एवं अन्य खर्चों समेत 1.31 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. माल्टा व गलगल के लिए प्रमुख उत्पादक जिलों में उद्यान विभाग ने उपार्जन संग्रह केंद्र भी तय किए हैं. जिला उद्यान अधिकारियों को ऐसे केंद्रों के माध्यम से खरीद के लिए निर्देशित किया गया है. उत्तराखंड के फल उत्पादक इस व्यवस्था से प्रोत्साहित होंगे. साथ में किसानों की आय में सकारात्मक वृद्धि होगी. इस योजना से राज्य में स्थापित प्रसंस्करण इकाइयों को उचित दर पर कच्चे माल की आपूर्ति हो सकेगी.

मछली पालन में आत्मनिर्भर बनेंगे किसान

धामी सरकार मछली पालन के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम कर रही है. खटीमा में राज्य का पहला ब्रूड बैंक स्थापित किया गया है. 23 एकड़ में बने ब्रूड बैंक से राज्य के मत्स्य पालकों को मछलियों के उन्नत किस्म (रोहू, जयंती मछली) के बीज मिलेंगे. अब ब्रिडिंग की समस्या से मछली पालकों को जूझना नहीं पड़ेगा. सरकार मछली पालन के क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है ताकि किसान अधिक आय प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें. मछली पालन में एससी-एसटी वर्ग के लिए 60 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान देने की वयवस्था की गई है. छोटे किसानों को निःशुल्क ब्रूड दिए जा रहे हैं.

गांवों की खुशहाली को लगातार बढ़ते कदम

- ‘‘हर घर को नल से जल’’ योजना में ग्रामीण घर में पानी का कनेक्शन दिया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्रों में केवल एक रुपए पर पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है.
- पौड़ी जिले के जयहरीखाल ब्लाक में भैरवगढ़ ग्राम समूह पम्पिंग योजना से इलाके के 75 गांवों और तोक को पानी मिलने लगा है. वर्ष 2016 से यह योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी.
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राज्य के नौ लाख से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1300 करोड़ की धनराशि दी जा चुकी है.
- प्रदेश में आठ लाख 82000 किसानों को मृदा कार्ड दिए गए. मिट्टी की पहचान होने से खाद की खपत घटने पर प्रदेश को 200 करोड़ से अधिक की बचत हुई है.
- प्रधानमंत्री आवास योजना (गामीण) के तहत भवन निर्माण के बाद राज्य सरकार लाभार्थी को घर के सामान आदि के लिए पांच हजार रुपए भी देगी.
- राज्य में उद्यान और बागवानी से जुड़े काश्तकारों को कोरोना वॉरियर घोषित करते हुए आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.
- ‘मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना’ योजना के तहत पशुपालक परिवार की हर महिला को राज्य सरकार की ओर से किट दी जाएगी, जिसमें दो कुदाल, दो दरांती, एक पानी की बोतल और एक खाने का टिफिन शामिल होगा.
- उत्तराखंड में आर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जैविक खेती करने वाले किसानों को 10 प्रतिशत सब्सिडी देगी.
- वन अनुसंधान केंद्र ने रानीखेत के द्वारसों में देश का पहला घास संरक्षण केंद्र स्थापित किया है. तीन एकड़ क्षेत्र में फैले इस केंद्र में घास की 90 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है.
- जनपद नैनीताल के लालकुआं में एक लाख लीटर प्रति दिन क्षमता की नई आधुनिक दुग्धशाला स्थापित की जाएगी.
- जनपद ऊधमसिंह नगर में 10 मै. टन प्रति दिन के आधुनिक दुग्धचूर्ण संयत्र की स्थापना की जाएगी.
- चमियाला क्षेत्र में 32 किमी पर्वतीय नहरों का जीर्णोद्धार किया जाएगा. बूढ़ाकेदार व विनयखाल की 20 पर्वतीय नहरों का जीर्णोद्धार होगा.
- राज्य में पलायन को दृष्टिगत ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग का गठन किया गया है. आयोग द्वारा जनपदों एवं विभागों के संबंध में राज्य सरकार को पलायन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 13 सिफारिशें प्रस्तुत की जा चुकी हैं.

पंचायतों को सबल बना रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

कोरोना काल में जनता की मदद और सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए उत्तराखंड के सभी प्रधानों को 10-10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है. पंचायतों को मजबूत करने को सरकार की प्रतिबद्धता बताते हुए मुख्यमंत्री धामी ने उपाध्यक्ष जिला पंचायत का मानदेय 5000 हजार से बढ़ाकर 7000 करने, उप प्रमुख, ज्येष्ठ कनिष्ठ क्षेत्र पंचायत का मानदेय 1500 से 2500 करने की भी घोषणा की है. मुख्यमंत्री ने जिला पंचायत अध्यक्षों को पूर्व की भांति मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 25 नवंबर को गांधी पार्क, रूद्रपुर में आयोजित लोक योजना अभियान ‘‘सबकी योजना सबका विकास’’ के अंतर्गत कुमाऊं मंडल के पंचायत प्रतिनिधियों की राज्य स्तरीय अभिमुखीकरण कार्यशाला में प्रतिभाग किया. इससे पहले 22 नवंबर को पंचायत प्रतिनिधियों की कार्यशाला में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10 हजार रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 14 हजार रुपए प्रतिमाह, ब्लाक प्रमुख का मानदेय 6000 रुपए प्रतिमाह से 9800 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा की है. जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्यों को प्रति बैठक के हिसाब से मानदेय मिलता है. अभी तक जिला पंचायत सदस्य को प्रति बैठक में शामिल होने पर 1000 रुपए, बीडीसी सदस्य को 500 रुपए मिलता है, अब इन्हें क्रमशः 1500 और 700 रुपए मिलेंगे. धामी सरकार ने प्रदेश के 7791 ग्राम प्रधानों का मानदेय 1500 रुपये प्रति माह बढ़ाकर 3500 रुपये कर दिया है.

हाइटेक हुई पंचायतें

पंचायतीराज विभाग ने सभी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के बैंक खातों को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल के माध्यम से पीएफएमएस के साथ जोड़ा है. इसी का फायदा पंचायतों को मिल रहा है. अब बजट सीधे इनके खातों में भेजा जा रहा है. इससे जरूरतमंदों तक त्वरित लाभ पहुंच रहा है. मई माह में प्रदेश सरकार ने कोरोना से निबटने के लिए भी पंचायतों को बजट जारी किया था. उत्तराखंड की 7500 से अधिक पंचायतों को कोरोना काल में करीब 90 करोड़ रुपये राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के आधार पर जारी किए गए थे. यह पैसा सीधे पंचायतों के खाते में गया है और इसमें से 20 प्रतिशत का उपयोग कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किया गया है. ग्राम पंचायतों को 27.20 करोड़, क्षेत्र पंचायतों को 20.40 करोड़ और जिला पंचायतों को 42.64 84 करोड़ रुपये दिए गए थे. पंचायतों में विकास योजनाओं के साथ-साथ कोरोना महामारी संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी उपायों और प्रवासियों के लिए संस्थागत क्वारंटीन संबंधी व्यवस्था के लिए विद्यालय, पंचायत भवन, अन्य सामुदायिक भवन आदि की साफ-सफाई, विद्युत, पेयजल, शौचालय व्यवस्था, तथा सैनिटाइजेशन आदि पर इस बजट में से व्यय किया गया है.

पंचायतों में क्लस्टर

‘‘क्लस्टर एप्रोच’’ परियोजना के अंतर्गत कृषि एवं औद्यानिकी को पर्वतीय सीमान्त कृषकों हेतु लाभकारी गतिविधि के रूप में विकसित करने के लिए सड़क मार्गों के समीप स्थित दो-तीन निकटवर्ती ग्राम पंचायतों को क्लस्टर के रूप में चयनित किया गया है. क्लस्टर एप्रोच के अंतर्गत परियोजना क्षेत्र में नकदी फसलों तथा फलों की अलग-अलग एक या दो प्रजातियां चयनित कर कृषकों को सामूहिक उत्पादन तथा विपणन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है. परियोजना के अंतर्गत लगभग 4031 हेक्टेयर क्षेत्र में औद्यानिक फसलों तथा सब्जी फसलों के क्लस्टर बनाए जा चुके हैं. परती भूमि पुनरुद्धार परियोजना के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के परिणामस्वरूप परती हो चुकी कृषि भूमि के पुनरुद्धार हेतु गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. परियोजना के तहत निर्मित जल संभरण तथा सिंचाई अभिसंरचनाओं, नमी संरक्षण गतिविधियों तथा जल उपयोग दक्षता वृद्धिह हेतु नवीन तकनीकों के उपयोग से परती हो चुकी कृषि भूमि को पुनः कृषिमय भूमि में परिवर्तित किया गया है. परियोजना के तहत बरानी क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाने के कारण अब तक 2530 हेक्टेयर परती भूमि कृषि तथा उद्यान स्थापना गतिविधियों के माध्यम से कृषिमय भूमि में परिवर्तिनत की जा चुकी है.

गुणवत्तापरक पानी

उत्तराखंड के हर गांव में अब पानी की जांच होगी. वहीं हर ब्लॉक में पानी टेस्टिंनग लैब भी बनेगी. प्रदेश में पानी की जांच के लिए 27 लैब हैं. अब धामी सरकार हर ब्लॉक में लैब बनाने जा रही है, जो उस ब्लॉक के इंटरकालेज में स्थापित की जाएगी. सभी गांव में पांच-पांच लोगों की टीम को प्रशिक्षण दिया गया है जो किट के माध्यम से पानी की गुणवत्ता जांचेंगे. अगर पानी पीने योग्य नहीं हुआ तो दवाओं का प्रयोग करके उसे ठीक किया जाएगा. उत्तराखंड में अक्टूबर में आयी आपदा क्षतिग्रस्त हुई

> **‘‘कोरोना काल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने जनता के दर्द को बांटा है. उन्होंने इस दौरान विभिन्न सुविधाओं को स्थापित करने में विशेष योगदान दिया है. इस दौरान कुछ प्रतिनिधियों पर दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मुकदमे भी दर्ज हो गए. कोरोना काल में त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाएगा.’’**
>
> ***– पुष्कर सिंह धामी,***
> ***मुख्यमंत्री, उत्तराखंड***

पेयजल योजनाओं के लिए 38 करोड़, 15 लाख का बजट जारी किया गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्ति के बंटवारे के बाद उधमसिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 04 नहरों समेत कुल 24 नहरों का अधिकार उत्तराखंड को हस्तांतरित हो गए हैं.

जल स्रोतों का पुनरुद्धार

विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अंतर्गत चयरनित 82 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों के समग्र विकास के दृष्टिगत सूक्ष्म जलागम योजनाएं बनाकर उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है. इन सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में स्थिंत जलस्रोतों के उपचार हेतु विशेष रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य, मृदा संरक्षण गतिविधियां संचालित करने के लिए विशेष योजनाएं बनायी गयी हैं. स्थानीय आवश्यकता के अनुसार आवश्यक मृदा एवं जल संरक्षण गतिविधियां क्रियान्वित किए जाने से पर्वतीय क्षेत्रों में सूख रहे जल स्रोतों के उत्सर्जन में वृद्धि हो रही है. परियोजना के अंतर्गत चिन्हित 1530 जल स्रोतों में से 1485 जल स्रोतों का उपचार किया गया जिसमें प्री-मानसून डिस्चार्ज 13.8% से बढ़कर 22.2% हो गया है. मानसून के बाद की अवधि में वाटर डिस्चार्ज में प्रतिशत वृद्धि 13.8% से 27.8% तक हुई है.

गांव में पहुंचा विकास

रोजगार गारंटी

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कुल 3103.30 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय करते हुए 1068.8.97 लाख मानव दिवस सृजित किए. जिनमें 6.54 लाख परिवारों के 9.10 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया गया. इस दौरान 99.87% श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान 15 दिन के भीतर किया गया जो वर्ष 2017 से पहले मात्र 37.47% था. वर्ष 2017 के उपरान्त राज्य को कुल 15 पुरस्कार प्राप्त हुए.

ग्रामीण आजीविका

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत 2.58 लाख महिलाओं को संगठित कर 29897 समूहों, 3578 ग्राम संगठन तथा 210 क्लस्टर संगठनों का गठन किया गया. 110577 सदस्यों द्वारा विभिन्न आजीविका संवर्धन गतिविधियां संचालित कर स्वरोजगार उत्पन्न किया जा रहा है. पशुपालन आधारित गतिविधियों में कुल 8556 समूहों के 42395 सदस्यों द्वारा आय सृजन का कार्य किया जा रहा है.

कौशल विकास

दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के अतंर्गत कुल 80.10 करोड़ रुपए व्यय करते हुए 4153 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित कर 1510 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया गया है. 13 जनपदों में 11 सरस सेंटर का संचालन संगठनों द्वारा किया जा रहा है. एस.वी.ई.पी. योजना के अंतर्गत राज्य के दो विकासखंडों सहसपुर और जसपुर में 647 उद्यमों की स्थापना कर स्वरोजगार से जोड़ा गया है.

ग्रामीण आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पहले फेज में पात्र पाए गए सभी 12662 परिवारों को आवास आवंटित किया गया है. प्रथम फेज के सभी 539 भूमिहीन परिवरों को भूमि पट्टा एवं आवास आवंटित किए गए हैं. द्वितीय फेज के आवास प्लस सूची के कुंल 16472 आवासों के निर्माण का लक्ष्य केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किया गया है. इसके सापेक्ष 15163 आवासों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है.

रूर्बन गांव

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना के तहत अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांवों के छह क्लस्टरों को ‘‘रूर्बन गांवों’’ के रूप में विकसित किया जा रहा है. केंद्र सरकार द्वारा राज्य की प्रगति को देखते हुए एक अतिरिक्त नवीन क्लस्टर जनपद पिथौरागढ़ के मल्लाघोरपट्टा हेतु स्वीकृत किया गया है.

सीमान्त क्षेत्र

उत्तराखंड में वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना संचालित की गई है. प्रदेश के अंतरराष्ट्रीय सीमा से लगे पांच जनपदों के 09 सीमांत विकास खंडों में आवासित परिवारों को सतत आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध कराते हुए अवस्थापना सुविधाएं विकसित की जा रही हैं. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा स्वयं के संसाधनों से 116 स्वीकृत कार्यों हेतु 1418.62 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं.

शांति प्रक्रिया को झटका

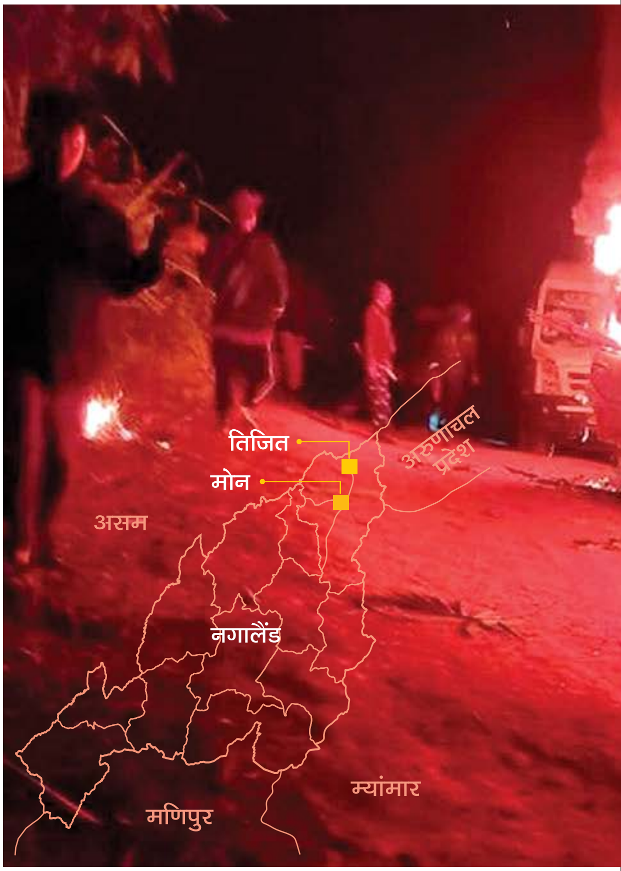

अशांत नगालैंड में घात लगाकर किए गए हमले में गलती से 14 नागरिकों की मौत से केंद्र और सशस्त्र बल बचाव की मुद्रा में. नाजुक शांति प्रक्रिया पड़ी खतरे में. कठोर एएफएसपीए कानून को लेकर उठे सवाल

कौशिक डेका

नगालैंड के मोन जिले में 4 दिसंबर को 'गलत पहचान' से शुरू हुई एक घटना में सशस्त्र बलों के हाथों 14 निर्दोष नागरिकों की मौत ने बीते छह सालों से राज्य में व्याप्त शांति को छिन्न-भिन्न कर दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली केंद्र सरकार ने 3 अगस्त, 2015 को नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (इसाक-मुइवाह) या एनएससीएन (आइ-एम) के साथ एक 'रूपरेखा समझौते' पर दस्तखत किए थे, जिससे टिकाऊ शांति समझौते का मार्ग प्रशस्त हुआ था. एनएससीएन (आइ-एम) राज्य का सबसे दुर्दांत उग्रवादी संगठन है और कई दूसरे धड़ों की तरह नगा लोगों के संप्रभु देश की मांग करता रहा है. 2017 से आठ और संगठन नगा नेशनल पोलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के बैनर तले शांति प्रक्रिया से जुड़े थे.

नतीजतन राज्य में आतंक से जुड़ी घटनाओं में काफी कमी आई. मरने वालों की संख्या 2015 में 47 से घटकर इस साल 3 दिसंबर तक महज चार रह गई. इसीलिए 4 दिसंबर को जब 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज के जवानों ने छह युवा खदान कामगारों को 'गलती से' आतंकवादी समझकर मार डाला, तो इस पहाड़ी राज्य में विरोध की आग भड़क उठी. सामाजिक-राजनैतिक संगठनों ने सशस्त्र बलों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की, वहीं राज्य में कई जगहों पर मामूली हिंसा हुई. एनएससीएन (खापलांग) धड़े से टूटकर बने उग्रवादी धड़े, एनएससीएन/जीपीआरएन ने ऐलान किया कि ''आज नहीं तो कल निर्दोषों के खून का बदला लिया जाएगा.'' वहीं 'अशांत क्षेत्रों' में विद्रोह-विरोधी कार्रवाइयों में सशस्त्र बलों को रक्षाकवच देने वाले सशस्त्र बल (विशेष अधिकार) कानून (एएफएसपीए या अफ्प्सा) 1958 हटाने का अभियान जोर पकड़ने लगा. नगालैंड और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने भी इसे हटाने की मांग की.

4 दिसंबर को हुआ क्या?

रक्षा सूत्रों के मुताबिक, 21 पैरा को मोन जिले के तिझित में ओटिंग गांव के नजदीक विद्रोही धड़े एनएससीएन-के (वाइए) का काडर गुजरने की खुफिया जानकारी मिली थी. उग्रवादियों पर हमला करने के लिए उनकी टीम घात लगाए बैठी थी. 21 पैरा स्पेशल फोर्सेज इत्तफाकन वही जंगल युद्ध इकाई है, जिसने 2015 में 'ऑपरेशन हॉट परस्यूट' के तहत म्यांमार के भीतर घुसकर आतंकी शिविरों पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था.

तभी एक बोलेरो गाड़ी तिरु घाटी की कोयला खदानों से आठ युवाओं को लेकर आ रही थी. कमांडो ने गाड़ी से रुकने को कहा. सेना के बयान के मुताबिक, गाड़ी नहीं रुकी तो जवानों ने खदान कामगारों में से एक के 'हंटर राइफल लिए होने' के कारण उन्हें आतंकवादी मान लिया और गोलियां चला दीं. छह लोग घटनास्थल पर ही मारे गए. सेना की टीम को तत्काल गलती का एहसास हुआ. उन्होंने घायलों को अस्पताल भेजा और पुलिस के आने का इंतजार करने लगे.

पुलिस टीम आती, उससे पहले ही खदान कामगारों की तलाश करते हुए गांव वाले आ पहुंचे जवानों से उनकी भिड़ंत हुई. उन्होंने तीन वाहनों में आग लगा दी. आत्मरक्षा में जवानों ने फिर गोलियां चलाईं, जिसमें सात और नागरिक मारे गए. सेना का एक जवान भी मारा गया. केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने 5 दिसंबर को संसद में इसी वृत्तांत की तस्दीक की और कहा कि गोलीबारी 'गलत पहचान' का मामला था.

मगर स्थानीय लोगों और राज्य पुलिस का वृत्तांत अलहदा है. इसका ब्यौरा एफआइआर में है. यह कहती है कि कमांडो ने बगैर किसी उकसावे के बोलेरो पर गोलियां चला दीं.

एएनआइ

दुस्साहस
4 दिसंबर के टकराव के बाद सेना के वाहन को आग लगा दी गई

कार्रवाई के दौरान जवानों के साथ पुलिस गाइड भी नहीं था, जो कानूनन जरूरी है. एफआइआर का निचोड़ यह है कि सशस्त्र बलों की मंशा नागरिकों को चोट पहुंचाने और उनकी हत्या करने की थी.

नगालैंड सरकार के सूत्र यह भी आरोप लगाते हैं कि गांव वालों ने जब सैन्य कर्मियों को शव छिपाते और दूसरे ट्रक में लादते देखा, तब उन्हें गुस्सा आया. अगले दिन नाराज ग्रामीणों ने नजदीक की एक चौकी पर हमला कर दिया, जिसका काम दूसरी इकाई 27 असम राइफल्स संभालती है. असम राइफल्स हालांकि पूर्वोत्तर में विद्रोह से लड़ रहा सबसे प्रमुख बल है, पर मोन की कार्रवाई में वह शामिल नहीं था. भीड़ तितर-बितर करने के लिए जवानों ने गोलियां चलाईं, जिसमें एक और नागरिक मारा गया. इस बीच शाह ने संसद में कहा कि घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआइटी) बनाया गया है और रिपोर्ट एक महीने में आ जाएगी. सेना ने भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है.

शांति प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है?

समयबद्ध जांच के आश्वासन के बावजूद केंद्र जानता है कि यह घटना राज्य की शांति प्रक्रिया में बाधा डाल सकती है. नई दिल्ली ने शांति बनाए रखने की अपील की और उसने नगा धड़ों से संपर्क साधा है. इनमें एनएससीएन (आइ-एम) भी है, जिसने 4 दिसंबर को 'नगाओं का काला दिवस' करार दिया.

इतने सालों में बातचीत की बहुतेरी कोशिशों के बाद भी नगालैंड में शांति छलावा ही साबित होती रही है. नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) के अंगामी झापू फिजो की अगुआई में नगाओं ने 14 अगस्त, 1947 को भारत सरकार के खिलाफ पहली बगावत की थी. फिजो को जुलाई 1948 में गिरफ्तार किया गया, पर अगले साल रिहा कर दिया गया. 1952 में तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के साथ फिजो की मुलाकात भी बेनतीजा रही. चार साल बाद फिजो ने भूमिगत सरकार का गठन किया, जिसे नगा फेडरल गवर्नमेंट (एनएफजी) कहा. अप्रैल 1956 में केंद्र सरकार ने 'असम के नगा पहाड़ी जिले' में (आज का नगालैंड तब यही था) विद्रोह को कुचलने के लिए सेना भेजी. फिजो दिसंबर 1956 में भागकर तब के पूर्वी पाकिस्तान और वहां से जून 1960 में लंदन चले गए.

1 दिसंबर, 1963 को नगालैंड राज्य बना, पर छिटपुट हिंसक आंदोलन उसके बाद भी जारी रहे. एनएनसी सशस्त्र संघर्ष चलाती रही. 1972 में केंद्र ने इस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया. सुरक्षा बलों ने राज्य में जबरदस्त विद्रोह

शांति पर फिर ग्रहण?

वर्ष 2015 में जब नगा उग्रवादी समूहों से शांति की सबसे ताजा प्रक्रिया शुरू हुई तब से नवंबर 2021 तक नगालैंड में आतंकी घटनाओं में सालाना मरने वालों की संख्या 47 से घटकर चार पर आ गई. मोन में 14 लोगों के मारे जाने की घटना से शांति के उस लक्ष्य को धक्का पहुंचा

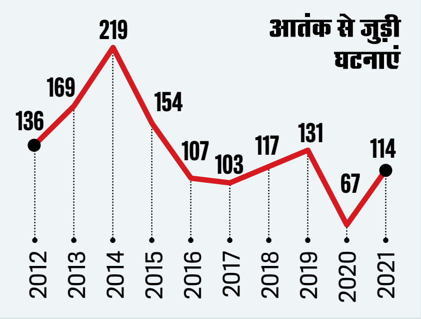

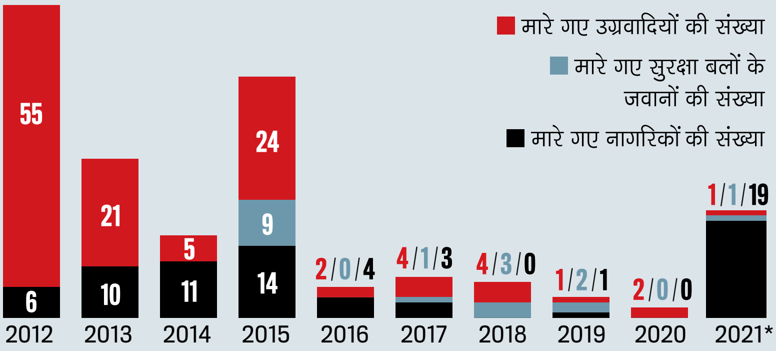

*मोन में मारे गए 14 नागरिकों और 1 सुरक्षाकर्मी इस संख्या में शामिल हैं

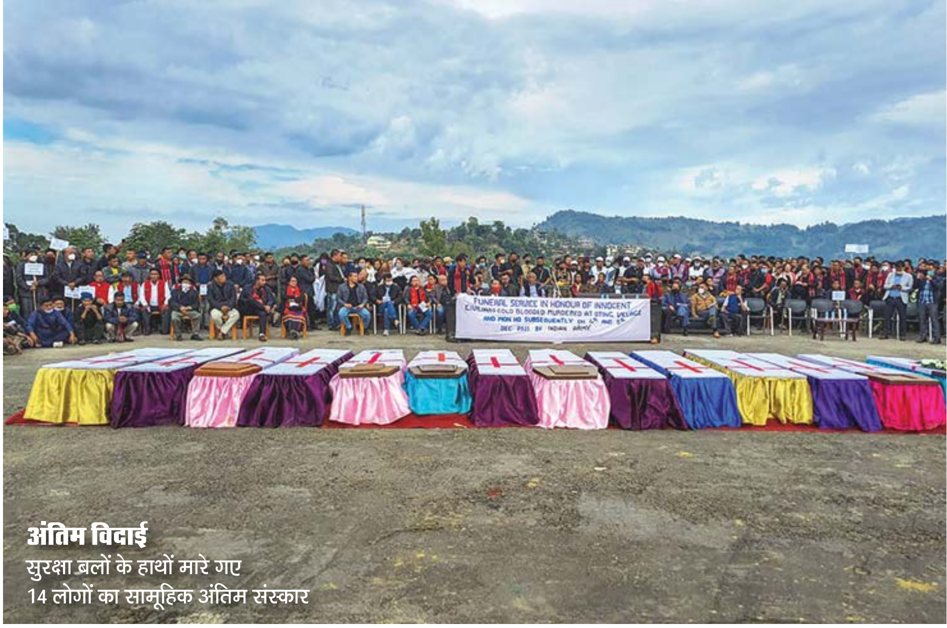
FUNERAL SERVICE IN HONOUR OF INNOCENT CIVILIANS COLD BLOODED MURDERED AT OTING VILLAGE AND MON HQ SUBSEQUENTLY ON 4th AND 5th DEC 2021 BY INDIAN ARMY

अंतिम विदाई
सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए
14 लोगों का सामूहिक अंतिम संस्कार

एएफपी

विरोधी अभियान छेड़ा. इसकी बदौलत उग्रवादी बातचीत की मेज पर आए. 11 नवंबर, 1975 को केंद्र और एनएनसी के बीच ऐतिहासिक शिलांग समझौते पर दस्तखत हुए. समझौते की शर्तों के मुताबिक, एनएनसी ने भारतीय संविधान स्वीकार किया.

अलबत्ता उसके तीन नेताओं—इसाक चिसी स्वु, थुइंगलेंग मुइवाह और एस.एस. खापलांग—ने समझौते को ठुकरा दिया. 31 जनवरी, 1980 को उन्होंने नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) का गठन किया. इसका उद्देश्य संप्रभु नगालिम (ग्रेटर या वृहत्तर नगालैंड) की स्थापना करना था, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर के नगा आबादी वाले इलाके भी शामिल थे. आठ साल बाद खापलांग अलग हो गए और उन्होंने एनएससीएन (खापलांग) बनाया, जबकि दूसरा धड़ा एनएससीएन (आइ-एम) कहलाने लगा. तभी से दोनों धड़े इतनी बार टूटे कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से जुड़े नाम वाले उग्रवादी धड़ों का तांता लग गया. गैर सरकारी सूत्रों के मुताबिक, विद्रोह में बीते 40 सालों में करीब 5,000 लोगों की जान जा चुकी है.

एनएससीएन के उभार के बाद नगा विद्रोह के समाधान की पहली अहम कोशिश 1995 में हुई, जब प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव ने पेरिस में स्वु और मुइवाह से मुलाकात की. राव के उत्तराधिकारी देवगौड़ा 1997 में स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में बागी नेताओं से मिले. उसी साल एनएससीएन (आइ-एम) ने केंद्र सरकार के साथ संघर्ष विराम संधि पर दस्तखत किए. तब से दोनों के पक्षों के बीच करीब 80 दौर की बातचीत हुई. उसके बाद कहीं जाकर 2015 में 'रूपरेखा समझौते' पर दस्तखत हुए.

एनएससीएन (के) ने भी 2001 में संघर्षविराम का ऐलान किया, पर 2015 में तोड़ दिया. केंद्र सरकार ने चार अन्य धड़ों एनएससीएन (एनके), एनएससीएन (आर), एनएससीएन (के-खांगो) और एनएससीएन (निकि सुमि) के साथ युद्धविराम समझौते किए. केंद्र सरकार ने जब देखा कि महज किसी एक धड़े के साथ संधियों से स्थायी शांति नहीं आ सकती, तो उसने धीरे-धीरे दूसरे धड़ों को भी इस प्रक्रिया से जोड़ा. 2017 से एनएनपीजी और दूसरे धड़ों के साथ केंद्र की बातचीत चल रही है. मगर नगालैंड के लिए अलग झंडे और संविधान की मांग पर अड़े एनएससीएन (आइ-एम) के साथ शांति समझौता दूर तक नजर नहीं आता.

पिछले साल मामला तब और बिगड़ गया जब केंद्र के वार्ताकार और नगालैंड के तत्कालीन राज्यपाल आर.एन. रवि ने बयान जारी कर व्यापक समझौते के मसौदे में देरी के लिए एनएससीएन (आइ-एम) को 'टालमटोल वाला रवैया' अपनाने का दोषी ठहराया. बदले में उग्रवादी धड़े ने भी रवि पर रूपरेखा समझौते में घालमेल करने का आरोप जड़ा. एनएससीएन (आइ-एम) ने नगालैंड के मुख्यमंत्री नेइफियू रियो को लिखी रवि की उस चिट्ठी पर भी नाराजगी जाहिर की, जिसमें उनका जिक्र समानांतर सरकार चला रहे 'सशस्त्र गिरोह' कहकर किया गया था. कैंप हेब्रन में पनाह लिए एनएससीएन (आइ-एम) का प्रशासनिक और सैन्य मुख्यालय दिमापुर में है और यह 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ नगालिम' की भूमिगत सरकार चलाता है. यह कथित तौर पर लोगों, कारोबारी प्रतिष्ठानों और यहां तक कि सरकारी अफसरों और महकमों से भी 'कर' वसूलता है. राष्ट्रीय राजमार्गों पर चल रहे व्यावसायिक वाहनों को भी निशाना बनाता है. रवि ने रियो सरकार से इन 'अवैध वसूलियों' को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा था.

एनएससीएन (आइ-एम) इस बात से भी चिढ़ गया कि सरकार एनएनपीजी के साथ

परेशान करता एएफएसपीए

सुरक्षा बलों को व्यापक अधिकार प्रदान करने के अनेक आलोचक

एएफएसपीए या आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पॉवर्स) ऐक्ट, 1958 संसद में इसलिए लाया गया ताकि 1950 के दशक में नगालैंड में फैले उग्रवाद से निपटा जा सके. इसका मसौदा अशांत क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई को कानूनी तौर पर दंडमुक्त रखने के मकसद से तैयार किया गया. इस कानून की धारा-4 के तहत सैन्य अफसरों को इस वाजिब शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है कि उस पुरुष/महिला ने संज्ञेय अपराध किया है.

सैन्य बलों को परिणाम की परवाह किए बगैर गोली चलाने की अनुमति है बशर्ते, पांच या इससे अधिक लोगों के एक जगह जुटने या हथियार लेकर चलने की की निषेधाज्ञा लागू की गई हो. धारा 6 कहती है कि सिवाय केंद्र सरकार की लिखित अनुमति को छोड़कर सैन्य बलों को अपनी ड्यूटी का निर्वाह करने के लिए अभियोजन अथवा अन्य कानूनी कार्यवाहियों से छूट रहेगी.

एएफएसपीए तब लागू होता है जब केंद्र या राज्य सरकार किसी क्षेत्र को अशांत घोषित करते हैं. इस तरह की घोषणाओं की हर छह महीने में समीक्षा की जरूरत होती है. एक बार किसी क्षेत्र के अशांत घोषित हो जाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के पास एएफएसपीए लागू करने की समवर्ती शक्तियां होती हैं. वर्तमान में जम्मू-कश्मीर, असम, नगालैंड, मणिपुर (इंफाल नगर परिषद क्षेत्र को छोड़कर), अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग, लांगडिंग और तिरपा जिलों और असम की सीमा से लगते इसके आठ पुलिस थाना क्षेत्रों में एएफएसपीए लागू है.

आलोचक दावा करते हैं कि एएफएसपीए के तहत दी गई असीमित शक्तियों के परिणामस्वरूप नागरिकों के विभिन्न अधिकारों का उल्लंघन हुआ.

इंडिया टुडे
देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

विशेषांक
इंडिया टुडे
ऊंचे और असरदार
रसूखदारों की सूची 2021

इंडिया टुडे
इंडिया टुडे कॉन्क्लेव 2021
बेहतरी की उम्मीद
महामारी के बाद उपजी आशंका और आशा के बारे में राजनीति, कारोबार, विज्ञान और खेलकूद की प्रमुख हस्तियों की राय

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.......................है और इसे दिनांक................ को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में .... (बैंक का नाम)......................रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम.. पता..

.... शहर...................... राज्य...................... पिन......................

मोबाइल.. ईमेल...

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

बातचीत शुरू कर रही थी. शांति प्रक्रिया पर उसका दबदबा जो कमजोर होता था. उसने तब भी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की जब नई दिल्ली ने एनएससीएन (के) के निकि सुमि धड़े के साथ 'कार्रवाई निलंबन' समझौते पर दस्तखत किए. एक सरकारी अफसर कहते हैं, ''ये प्रक्रिया में देरी के बहाने भर हैं. एनएससीएन (आइ-एम) का नेतृत्व मणिपुर की तंगखुल जनजाति से है. यह नगाओं का मुश्किल से ही प्रतिनिधित्व करता है. नगा दो दर्जन से ज्यादा जातीय समूहों की नुमाइंदगी करने वाला शब्द है. शांति समझौते पर दस्तखत हो जाते हैं, तो एनएससीएन (आइ-एम) को हथियार डालने पड़ेंगे और फिर वह नगा समाज में अपनी प्रासंगिकता गंवा बैठेगा.'' स्वु, जिनका 2016 में निधन हो गया, नगालैंड में जन्मे सेमा थे, तो मुइवाह मणिपुर में उखरूल के तंगखुल हैं.

चिंता अब यह है कि सशस्त्र बलों जब जनता की उग्र प्रतिक्रिया का सामना कर रहे हैं, विद्रोही धड़े लाभप्रद स्थिति में आ गए हैं और भर्ती अभियान चला सकते हैं. अफ्स्पा पर निशाना साधते हुए, एनएनपीजी ने कहा, ''कई दशकों के दौरान कठोर कानूनों और सेना के अत्याचारों ने नगा लोगों को एहसास दिलाया है कि वे भारतीय नहीं हैं और न कभी होंगे.''

एएफएसपीए हटना चाहिए?

एएफएसपीए हटाने की मांग विपक्षी दलों ने ही नहीं, भाजपा के सहयोगी और एनडीए घटक दलों ने भी की है. नगालैंड के मुख्यमंत्री नेइफियू रियो की पार्टी एनडीपीपी (नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी) एनडीए का हिस्सा है. रियो इस कानून को ''देश की छवि पर काला धब्बा'' कहते हैं, तो मेघालय में उनके समकक्ष और भाजपा के एक और सहयोगी दल एनपीपी (नेशनल पीपल्स पार्टी) के प्रमुख कोनराड संगमा ने भी इसे हटाने की मांग की है. मेघालय में यह विवादास्पद कानून संगमा के कमान संभालने के महीने भर बाद 2018 में हटा लिया गया था.

एएफएसपीए की समीक्षा के लिए बनी न्यायमूर्ति बी.पी. जीवन रेड्डी समिति ने 2004 में इसे पूरी तरह रद्द करने की सिफारिश की.

मोन में नागरिकों की हत्या जीता-जागता उदाहरण है कि एएफएसपीए से सशस्त्र बलों को दी गई व्यापक अधिकारों के चलते किस तरह की गलतियां हो सकती हैं. 2017 में आरटीआइ के तहत मिले एक जवाब से पता चला कि 2012 और 2016 के बीच एएफएसपीए वाले राज्यों में सशस्त्र बलों के खिलाफ मौत और यौन अपराधों सहित मानवाधिकार उल्लंघनों की 186 शिकायतें दर्ज की गईं. इनमें से 91 फीसद शिकायतें तीन राज्यों जम्मू-कश्मीर, असम और मणिपुर से थीं. नगालैंड से केवल एक शिकायत थी.

सशस्त्र बल अलबत्ता हिंसाग्रस्त इलाकों में एएफएसपीए के प्रयोग की वकालत करते हैं: कठिन परिस्थितियां कठिन उपायों की मांग करती हैं. ज्यादातर रक्षा अधिकारियों का कहना है कि चूंकि विद्रोह विरोधी कार्रवाइयां अत्यंत जोखिम भरी होती हैं और उनमें बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करनी होता है इसलिए एएफएसपीए सरीखा कवच जरूरी है.

चौदह नागरिकों की मौत से भाजपा और मुख्यमंत्री रियो के रिश्तों में दरार पड़ सकती है. रियो राज्य का निर्विवाद नेता बनने का सपना देख रहे हैं. 60 सदस्यीय नगालैंड विधानसभा में रियो की पार्टी एनडीपीपी की 21, एनपीएफ (नगा पीपल्स फ्रंट) की 25 और भाजपा की 12 सीटें हैं. हाल में जब रियो को भनक लगी कि भाजपा पड़ोसी मणिपुर की अपनी सहयोगी पार्टी एनपीएफ के साथ पींगे बढ़ा रही है, तो उन्होंने अपनी पूर्व पार्टी को सरकार में शामिल होने का न्यौता देकर खतरे की भ्रूणहत्या कर दी. बहाना यह बनाया गया कि नगा शांति प्रक्रिया के सुचारू अमल के लिए सर्वदलीय सरकार की जरूरत है. इससे भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व निश्चित ही चिढ़ गया. उसे डर है कि एनपीएफ को साथ लाकर रियो ईसाई बहुसंख्यक राज्य में भगवा पार्टी को खत्म करने पर उतारू हैं. नगालैंड में भाजपा के एक बड़े नेता कहते हैं, ''हम केंद्र और राज्य में सत्ता में हैं; बेहतर तालमेल होना चाहिए था... दुर्भाग्य से हमारे केंद्रीय नेता राज्य इकाई के साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं.''

मोन की गोलीबारी तब हुई जब मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर उग्रवादी धड़ों के घात लगाकर किए हमले को एक महीना भी नहीं हुआ था. उस हमले में कमांडिंग अफसर के पत्नी और बेटे के अलावा पांच जवान मारे गए थे. ताजा घटना हालांकि हादसा ही थी, पर यह भी सच है कि सेना अत्यधिक अलर्ट की स्थिति में थी और बदले की ताक में थी. इस बीच दोनों ही पड़ोसी राज्यों में, जिनके शांति प्रक्रिया में ऊंचे दांव लगे हैं, बेचैनी का माहौल है. इससे जिन-जिन के हित जुड़े हैं, उन सभी को चौकन्ना रहना होगा, ताकि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए और क्षेत्र में एक बार फिर अफरातफरी न फैले. सबसे कठिन काम सरकारी मशीनरी के कंधों पर है. उन्हें लोगों को भरोसा दिलाना होगा कि मोन की हत्याएं दुर्भाग्यपूर्ण भूल भर थीं. ■

उग्रवादियों का बोलबाला

नगाओं में ग्रेटर नगालिम के लिए लड़ने वाले संगठनों की कमी नहीं है

आधी शताब्दी से ज्यादा समय से नगा लोगों के लिए स्वतंत्र देश की मांग पर नगालैंड में उग्रवादी संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं. नगाओं ने पहली बार 1947 में नगा नेशनल काउंसिल (एनएनसी) के अंगामी झापू फिजो के नेतृत्व में भारत सरकार के खिलाफ बगावत की थी. 31 जनवरी, 1980 को इसाक चिसी स्वु, थुइंगलेंग मुइवाह और एस.एस. खापलांग ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालैंड (एनएससीएन) बनाई और तब की एनएनसी के केंद्र सरकार के साथ हुए शिलांग समझौते को खारिज कर दिया.

आठ साल बाद खापलांग ने स्वु और मुइवाह से अलग होकर एनएससीएन (खापलांग) बनाया जबकि दूसरा धड़ा एनएससीएन (आइ-एम) के नाम से पहचाना गया. तब से दोनों धड़े इतने बार टूट चुके हैं कि उग्रवादी गुटों के नाम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का मेल बन गए हैं. इनमें एनएससीएन (के) निकी सूमी, एनएससीएन (के) खांगो, एनएससीएन-खांगो कोन्याक गुट (एनएससीएन-के20), एनएससीएन-निओपाओ कोन्याक/किटोवी (एनके), एनएससीएन-किटोवी-निओपाक (केएन), एनएससीएन-के-युंग आंग (के-या) और एनएससीएन (रिफॉर्मेशन) शामिल हैं. 3 अगस्त, 2015 को केंद्र सरकार ने उग्रवादी गुटों के साथ अंतिम शांति समझौते का रास्ता तैयार करने के लिए एनएससीएन (आइ-एम) के साथ ''रूपरेखा समझौते'' पर हस्ताक्षर किए. 2017 से केंद्र सरकार नगा समूहों के संगठन नगा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप (एनएनपीजी) के साथ एनएससीएन के धड़ों—एनएससीएन-केएन, एनएससीएन (रिफॉर्मेशन), एनएससीएन-के2 और एनएनसी के चार धड़ों फेडरल गवर्नमेंट ऑफ नगालैंड (एफजीएन), एनएनसी-पेरेंट बॉडी, एनएससीएन का नॉन-एकॉर्डिस्ट धड़ा/नेशनल पीपल्स गवर्नमेंट ऑफ नगालैंड (एनपीजीएन/एनएनसी-एनए) और गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नगालैंड/एनएनसी-एनए (जीडीआरएन) के साथ वार्ता में जुटी हुई है. छह साल बाद भी शांति दूर-दूर तक नजर नहीं आती.

FROM THE VOICES THAT CRACKLE WITH AGE TO THE FIERY VOICES OF THE YOUTH

We believe in just one thing.

Your voice matters. Irrespective of who you are, where you come from, where you stand, what you do, and who you support.

We are the **India Today Group.**

Where every voice finds its right.

And every right finds a voice.

TAP THE TA
PUT A
STOP
TO THE DROP

WE'RE ALWAYS IN CONVERSATION WITH YOU.

INDIA TODAY GROUP

INDIA'S DEMOCRATIC NEWSROOM

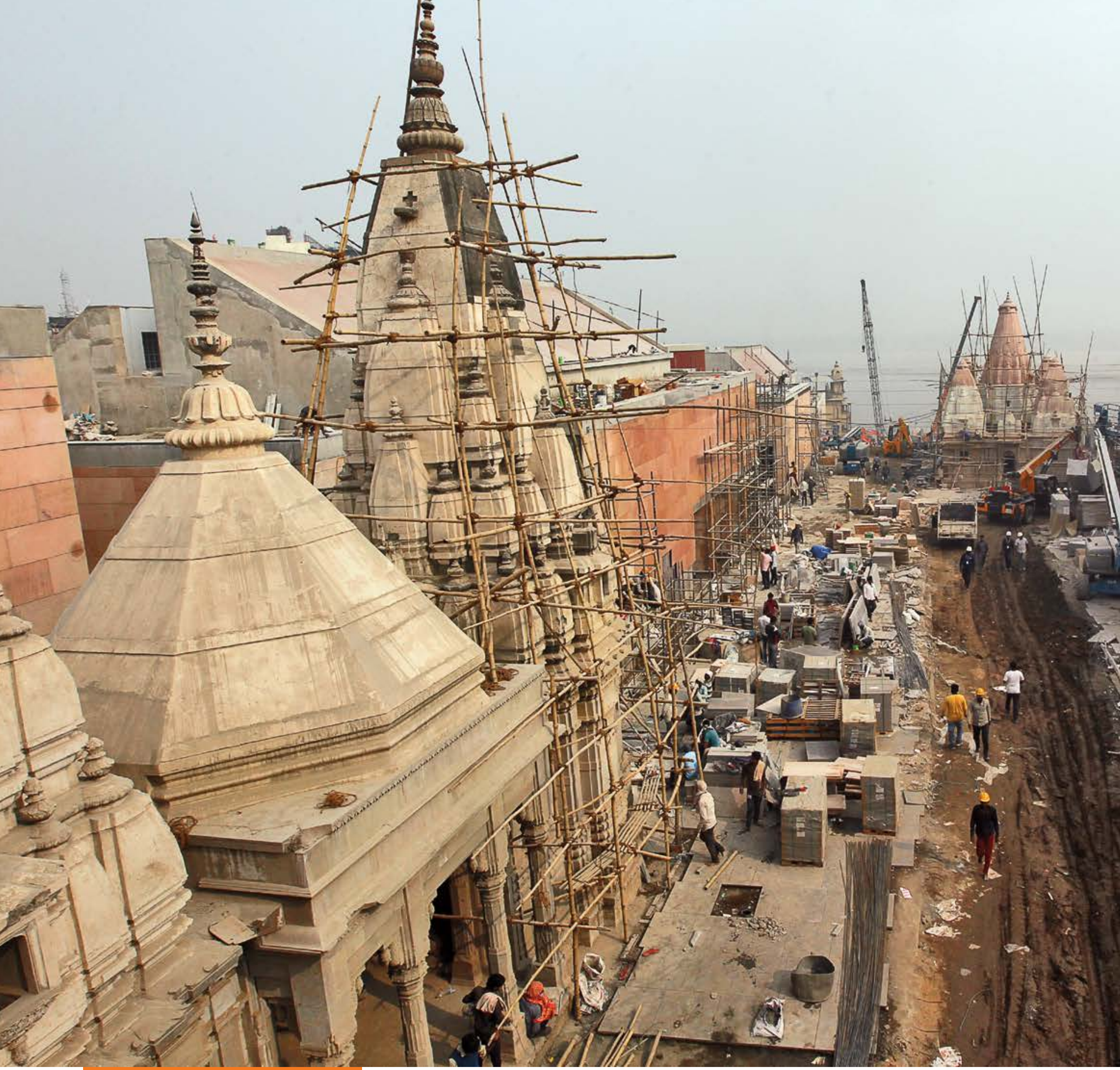

आस्था का गलियारा

आठ सौ करोड़ रु. की लागत से बने काशी विश्वनाथ मंदिर के नए गलियारे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों लोकार्पित हो रहा. तीर्थयात्रियों के लिए यह बनेगा वरदान

आशीष मिश्र

आनंद सिंह/इंडिया टुडे के लिए

आनंद सिंह/इंडिया टुडे के लिए

धार्मिक पुनरुत्थान

काशी विश्वनाथ मंदिर के गलियारे के निर्माण का दृश्य (बाएं और ऊपर)

लखनऊ के राजाजीपुरम इलाके में रहने वाले बैंककर्मी मयंक अग्रवाल के बुजुर्ग माता-पिता ने 13 फरवरी, 2018 को शिवरात्रि के मौके पर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने की इच्छा जाहिर की थी. मयंक उन्हें लेकर एक दिन पहले ही वाराणसी पहुंच गए. अगले दिन तड़के छह बजे वे सभी मंदिर की तरफ निकल पड़े. महाशिवरात्रि के कारण मंदिर की ओर जाने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं से भरे हुए थे. उधर की गलियों में तो पैर रखने की भी जगह न थी. मयंक बताते हैं, ''70 से ऊपर की वय के मम्मी-पापा के लिए भीड़ में लंबे समय तक खड़े रह पाना संभव न था. शौचालय और दूसरी सुविधाएं न होने से भी दिक्कतें थीं. कुछ देर श्रद्धालुओं की भीड़ में खड़े होने के बाद मम्मी-पापा को लेकर मैं मैदागिन चौक आ गया. यहां पर लगी एलईडी स्क्रीन पर ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए.''

मयंक जैसी पीड़ा उन लाखों श्रद्धालुओं की है जो किसी भी प्रकार की नागरिक सुविधाओं के बगैर तंग गलियों में जमा भारी भीड़ में काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने का हौसला नहीं दिखा पाते. ऐसे श्रद्धालु भी अब पूरी गरिमा के साथ आराम से दर्शन कर सकेंगे. वे सीधे गंगा से जल लाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी कर सकेंगे. वाराणसी में गंगा नदी से काशी विश्वनाथ मंदिर को एक कॉरिडोर से जोड़ने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना पूरा हुआ है. अब मंदिर के आसपास तंग गलियों की जगह बेहद चौड़े गलियारे ने ले ली है. पहले 3,000 वर्ग फुट में फैला काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर अब कॉरिडोर बनने के बाद से पांच लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला हो गया है. सड़क मार्ग पर उमड़ने वाली भीड़ से बचने के लिए अब श्रद्धालु गंगा नदी के रास्ते भी कॉरिडोर में प्रवेश कर सकेंगे. दर्शन करने के लिए रैंप और एस्कैलेटर की सुविधा वाले कॉरिडोर में श्रद्धालुओं को एक भी सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी.

मयंक भी इस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर उत्साहित हैं. वे कहते हैं ''अगले मार्च में 1 तारीख को पड़ने वाली महाशिवरात्रि पर मम्मी-पापा को दर्शन कराने ले जाऊंगा. चार साल पहले अधूरी रह गई इच्छा अगली महाशिवरात्रि में पूरी होगी.''

वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रत्याशी के तौर पर वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर को मुद्दा बनाया था और चुनाव जीतने के फौरन बाद 17 मई, 2014 को वाराणसी पहुंचकर मंदिर में पूजा की थी. इसके बाद उन्होंने इस मंदिर का विकास गुजरात के सोमनाथ मंदिर की तर्ज पर कराने का संकल्प लिया था. मोदी के संकल्प को गति 2017 में मिली जब यूपी में भाजपा की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने. 4 अप्रैल, 2017 को वाराणसी से जुड़ी विकास योजनाओं की समीक्षा करने के दौरान ही योगी ने अधिकारियों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में प्रयास करने का निर्देश दिया था. निर्माण के लिए जमीन का प्रबंध और अन्य सुविधाओं के निर्माण में तेजी लाने के लिए योगी कैबिनेट ने ''श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद'' के गठन को मंजूरी दी. सरकार ने मंदिर परिसर के विस्तार के लिए जमीन का इंतजाम करना शुरू किया. 60 फीसद जमीन का इंतजाम होते ही 2019 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से कुछ दिन पहले 8 मार्च को मोदी ने कॉरिडोर का शिलान्यास किया. अब 33 महीने बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का 13 दिसंबर को उद्घाटन करके मोदी उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले

कुछ यूं बदला काशी विश्वनाथ मंदिर का नजारा

योगी कैबिनेट ने 19 जून, 2018 को काशी मंदिर परिसर के समग्र विकास के लिए एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर ''श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद'' का गठन किया. परिषद का चेयरमैन वाराणसी के कमिश्नर को बनाया गया

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 8 मार्च, 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी को सीधे काशी विश्वनाथ मंदिर से जोड़ने के लिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मास्टर प्लान नई दिल्ली में संसद भवन (सेंट्रल विस्टा) के नवीनीकरण की परियोजना के परामर्शदाता के तौर पर काम कर रही अहमदाबाद की 'एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग ऐंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड' ने ही काशी विश्वनाथ कोरिडोर का मास्टर प्लान बनाया है. अहमदाबाद की कंपनी पीएसपी प्रोजेक्ट्स ने कोरिडोर का निर्माण किया है.

कॉरिडोर के निर्माण से पहले मंदिर परिसर केवल तीन हजार वर्ग फुट में फैला हुआ था. अब यह 5 हेक्टेयर या 48,730 वर्ग मीटर या पांच लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला हो गया है

सामान्य दिनों में 20,000 श्रद्धालु रोज काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने आते हैं. शिवरात्रि और सावन के महीने में यह संख्या 2 लाख श्रद्धालु रोज से ज्यादा हो जाती है. अब एक दिन में पांच लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे

कुल लागत कॉरिडोर के लिए जमीन की व्यवस्था करने में 390 करोड़ रुपए खर्च हुए, पुनर्वास और ध्वस्तीकरण में 70 करोड़ रु. लगे. पहले चरण के निर्माण में 339 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं. दूसरे चरण में गंगा घाट पर रैंप बिल्डिंग और ललिता घाट पर गेट तथा जेट्टी के निर्माण में 66 करोड़ रुपए खर्च होंगे

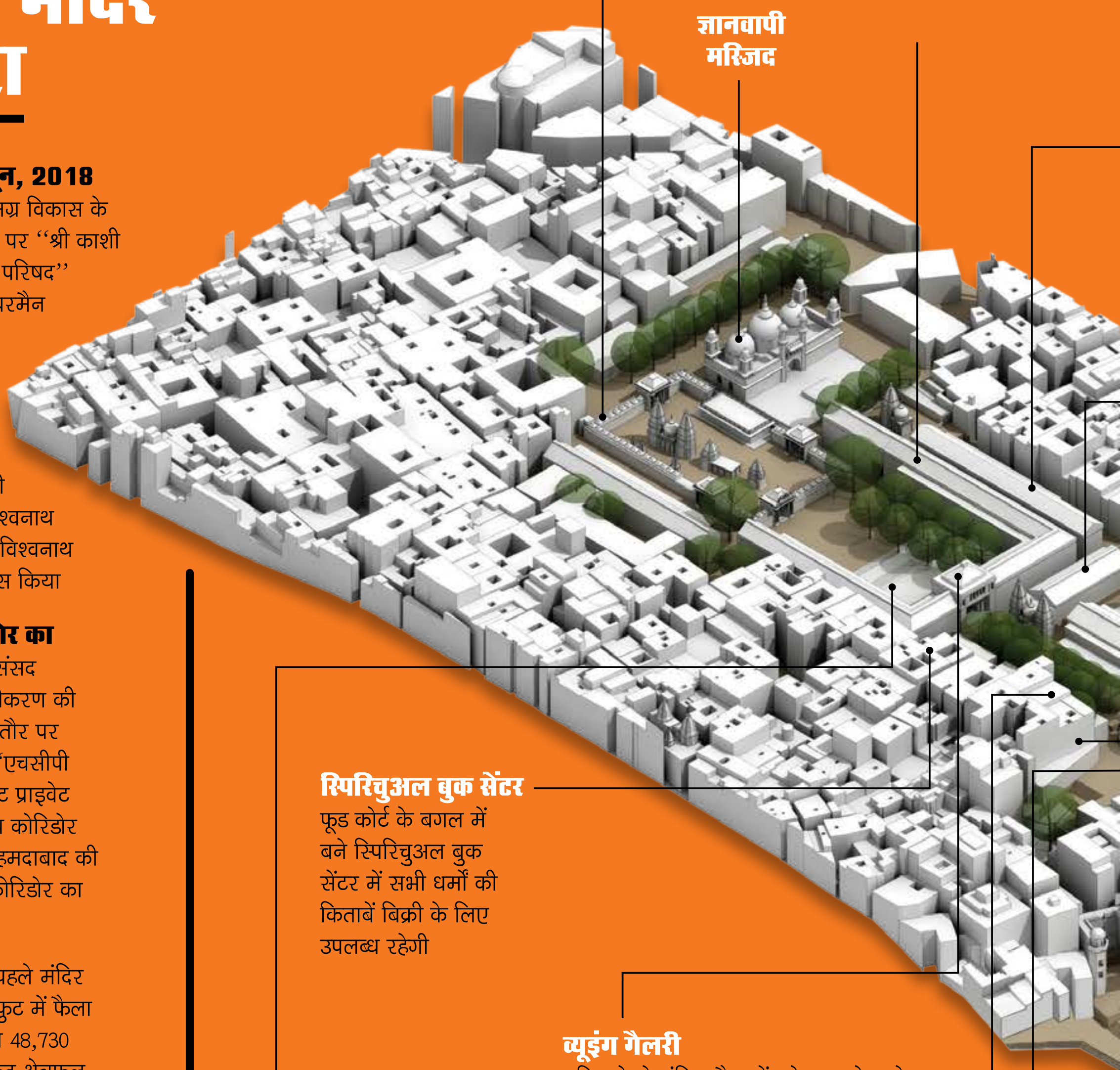

मंदिर परिसर
यहां कोई भवन नहीं है. मंदिर के चारों ओर 11 फुट चौड़ी एक गैलरी है. यहां सरस्वती फाटक पर यात्री सुविधा केंद्र के पीछे भोगशाला है. मंदिर में रहने वाले साधुओं के लिए भोजन यहीं तैयार होगा

नीलकंठ पैवेलियन
इसमें पहले तल पर श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास बोर्ड का दफ्तर है और भूतल पर अग्निशमन प्रणाली लगी है

स्पिरिचुअल बुक सेंटर
फूड कोर्ट के बगल में बने स्पिरिचुअल बुक सेंटर में सभी धर्मों की किताबें बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी

मंदिर चौक
मंदिर चौक के दोनों तरफ तीन मंजिला भवन हैं. भूतल पर दोनों तरफ टॉयलेट कॉम्प्लेक्स और लॉकअप रूम हैं. प्रथम तल पर इंपोरियम है जहां अलग-अलग प्रदेशों के हस्तशिल्प बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. दूसरे तल पर ''श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास बोर्ड'' का हॉल है, यहां बोर्ड की मीटिंग की जा सकेगी

व्यूइंग गैलरी
गलियारे से मंदिर चौक में प्रवेश करने वाले गेट के ऊपर व्यूइंग गैलरी बनी है. यहां से श्रद्धालु एक तरफ गंगा नदी तो दूसरी ओर काशी विश्वनाथ मंदिर को देख सकेंगे

फूड कोर्ट
मंदिर चौक में प्रवेश से पहले बाईं ओर श्रद्धालुओं के जलपान के लिए रेस्तरां की व्यवस्था रहेगी

वैदिक सेंटर
गलियारे में बाईं ओर वैदिक सेंटर है. यहां एक साथ 100 लोगों को कर्मकांड, योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा. इस केंद्र में प्राचीन शास्त्रों को भी रखा जाएगा

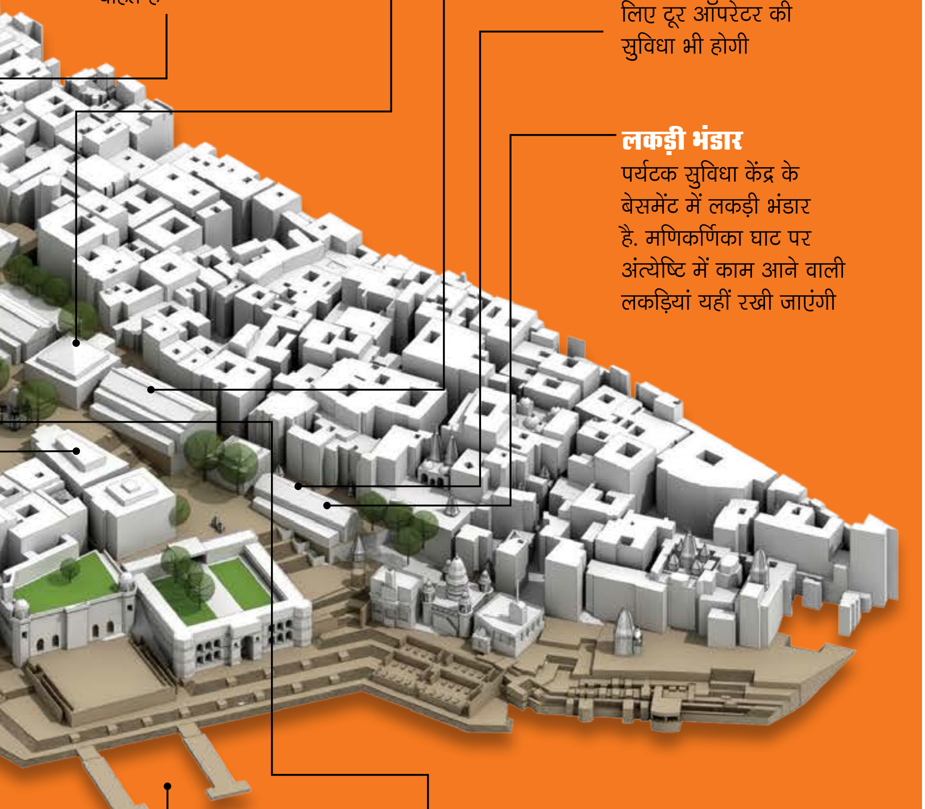

गेस्ट हाउस
नीलकंठ पैवेलियन के बगल में दो मंजिला गेस्ट हाउस है. हर मंजिल पर 18 कमरे हैं

वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम
दाहिनी ओर वाराणसी गैलरी में डिजिटल माध्यम से मंदिर के इतिहास से लेकर उसके नए रूप में आने तक की कहानी बताई जाएगी. कॉरिडोर के निर्माण के दौरान मिले पुराने मंदिर, मूर्तियां, कलाकृतियों को यहां प्रदर्शित किया जाएगा

मल्टीपर्पस हॉल
कॉरिडोर में गंगा की तरफ से आने पर दाहिनी ओर यह दो मंजिला भवन है. हर मंजिल की क्षमता 330 श्रद्धालुओं की है. यहां सत्संग, गोष्ठी जैसे आयोजन किए जा सकेंगे

मुमुक्षु भवन
वाराणसी गैलरी और सिटी म्यूजियम के पीछे मुमुक्षु भवन है. डॉरमेट्री में 48 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी. यहां पर वे बुजुर्ग रह सकेंगे जो अपने अंतिम दिन काशी में व्यतीत करना चाहते हैं

पर्यटक सुविधा केंद्र
कॉरिडोर में गंगा घाट की तरफ एक पर्यटक सुविधा केंद्र भी बनाया गया है. यहां ट्रेन या जहाज का टिकट बुक कराने के साथ वाराणसी के आसपास घूमने के लिए टूर ऑपरेटर की सुविधा भी होगी

लकड़ी भंडार
पर्यटक सुविधा केंद्र के बेसमेंट में लकड़ी भंडार है. मणिकर्णिका घाट पर अंत्येष्टि में काम आने वाली लकड़ियां यहीं रखी जाएंगी

घाट और जेट्टी
मणिकर्णिका घाट के बगल में जलासेन घाट और ललिता घाट से कॉरिडोर में प्रवेश का रास्ता है. गंगा से होकर आने वाले श्रद्धालु नाव से सीधे ललिता घाट पर बनी जेट्टी पर उतर सकेंगे

काशी विश्वनाथ कॉरिडोर
में प्रवेश के तीनों गेट पर यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है. यहां पर आरती बुक कराने से लेकर सामान रखने के लिए लॉकर लेने की सुविधा मिलेगी. यहीं पर सभी श्रद्धालुओं की सुरक्षा जांच भी होगी

क्यू मैनेजमेंट सिस्टम
कॉरिडोर में लंबी लाइनों से श्रद्धालुओं को बचाने के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो रहा है. इसमें टिकट बुक करते ही श्रद्धालु को दर्शन के लिए 'टाइम स्लॉट' की जानकारी मिल जाएगी

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

विधानसभा चुनाव में भाजपा को इसका भरपूर फायदा दिलाने की कोशिश करेंगे. काशी हिंदू विश्वविद्यालय में समाज विज्ञान और राजनीति शास्त्र विभाग के डीन प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र बताते हैं, ''काशी विश्वनाथ मंदिर में देश ही नहीं, विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. लोगों ने कभी कल्पना नहीं की होगी कि बेहद तंग गलियों के बीच बसा काशी विश्वनाथ मंदिर एक भव्य कॉरिडोर का रूप ले सकेगा. यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसका उद्घाटन करके मोदी विकास का एजेंडा सेट करेंगे. यही नहीं, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने का जिक्र करके भाजपा भी आक्रामक ढंग से हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएगी.''

करीब 3,000 वर्ग फुट में फैले मंदिर परिसर को पांच लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाले कॉरिडोर में तब्दील करना आसान काम न था. मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर अधिकारियों ने मंदिर के आसपास 314 भवनों को चिन्हित किया था जो प्रस्तावित कॉरिडोर की जद में आ रहे थे. मार्च, 2018 में वाराणसी मंडल के कमिशनर की जिम्मेदारी संभालने वाले दीपक अग्रवाल ने सभी 314 भवनों को प्रोजेक्ट में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई. श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद के चेयरमैन के तौर पर अग्रवाल के सामने दो विकल्प थे. परिसर के आसपास मौजूद 314 भवनों का अधिग्रहण या आपसी समझौते के माध्यम से इन्हें कॉरिडोर में शामिल किया जाए. योगी के निर्देश पर तय हुआ कि सभी संपत्तियों को आपसी समझौते से खरीदा जाए. अग्रवाल बताते हैं, ''स्वामित्व के आधार पर 314 संपत्तियां मुख्य रूप से तीन तरह की थीं. पहली, निजी स्वामित्व वाली संपत्ति में हर संपत्ति के एक से ज्यादा स्वामी थे. दूसरी ट्रस्ट संपत्ति और तीसरी वे संपत्तियां थीं जिनका केवल कस्टोडियन ही मौजूद था. इसमें 'कस्टोडियन राइट्स' हस्तांतरित कराने पड़े.'' निजी संपत्ति को आपसी समझौते के आधार पर खरीदा गया. संपत्ति का मूल्य भूअधिग्रहण अधिनियम के अनुसार निर्धारित बाजार मूल्य का दोगुना दिया गया.

मार्च, 2019 तक सारी संपत्तियां खरीद लीं गईं. समस्या इन संपत्तियों को खाली कराने की थी क्योंकि 100 से ज्यादा संपत्तियां ऐसी थीं जिसमें उनके मालिक और रहने वाले अलग-अलग थे. ये किराएदार या अतिक्रमणकारी के रूप में थे. अग्रवाल बताते हैं, ''ऐसे लोग जिनके पास संपत्ति से जुड़ा कोई भी कानूनी

दस्तावेज नहीं था पर वे उसका उपयोग व्यवसाय के लिए कर रहे थे. इनसे आपसी समझौते के जरिए 'वन टाइम सेटलमेंट' किया गया. एक से 10 लाख रुपए प्रति यूनिट ''रिहैबिलिटेशन ग्रांट'' के रूप में दिए गए. इस ग्रांट में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का भी ध्यान रखा गया. विधवा, एससी-एसटी वर्ग से जुड़े लोगों को निर्धारित से अधिक धन दिया गया. मसलन, वे 37 परिवार जिनकी जीविका मणिकर्णिका घाट पर होने वाले अंतिम संस्कार से जुड़ी थी, उन्हें करीब 50 फीसद तक अधिक राशि दी गई. ये सभी परिवार अब मणिकर्णिका घाट के आसपास ही किराए पर मकान लेकर रहते हैं. इस व्यवस्था के चलते यहां खरीदी गई जमीनों से जुड़ा एक भी मामला किसी भी अदालत में लंबित नहीं है.

कॉरिडोर के लिए जमीन का इंतजाम करने में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली. कॉरिडोर के विस्तार में ज्ञानवापी मस्जिद के सामने मौजूद 1,700 वर्ग फुट जमीन आड़े आ रही थी. 1993 में यह जमीन सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने स्थानीय प्रशासन को दी थी जिस पर पुलिस कंट्रोल रूम बना था. साल भर तक कई वार्ताओं के बाद जुलाई में मंदिर प्रशासन और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बीच जमीन की परस्पर अदला-बदली पर सहमति बनी. जमीन की कीमत के आधार पर हुई अदला-बदली में कॉरिडोर को 1,700 वर्ग फुट जमीन मिली. बदले में मंदिर प्रशासन ने 200 मीटर दूर बांसफाटक इलाके में 1,000 वर्ग फुट जमीन अंजुमन इंतजामिया मसाजिद (ज्ञानवापी मस्जिद का संचालन करने वाली संस्था) को दी. मसाजिद के संयुक्त सचिव एस.एम. यासीन बताते हैं, ''सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की संपति के बदले में अंजुमन को 1,000 वर्ग फुट जमीन मिली है. आर्टिकल-31 में निहित एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टी के तहत संपत्तियों का हस्तांतरण हुआ है.''

जमीन का इंतजाम होने के बाद 2019 में भवनों को ढहाने का काम शुरू हुआ. तंग गलियों में होने की वजह से सबसे पहले इन्हें मैनुअली ढहाया गया. इस दौरान 61 प्राचीन मंदिर और देवी-देवताओं की मूर्तियां भी निकलीं. अग्रवाल बताते हैं, ''कॉरिडोर का डिजाइन तैयार करते वक्त सोचा गया था कि मंदिर के आसपास का पूरा परिसर एक समतल मैदान के रूप में मिल जाएगा. ढहाने पर निकले मंदिरों को भी कॉरिडोर का हिस्सा बनाने के लिए डिजाइन में बदलाव किया गया. वैदिक सेंटर, मुमुक्षु भवन समेत कई भवनों को रीलोकेट किया गया. '' वहीं निकले 27 बड़े मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है. परिसर में एक देव गैलरी भी बनाई जा रही है, जहां निकले मंदिरों के अवशेष और देवी-देवताओं की मूर्तियों को श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए रखा जाएगा.

कॉरिडोर के लिए मंदिरों के आसपास भवनों को तोड़ने पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलाजी (आइआइटी), बीएचयू के प्रोफेसर और वाराणसी के प्रसिद्ध संकट मोचन मंदिर के महंत विश्वंभर नाथ मिश्र कहते हैं, ''कॉरिडोर के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के मंदिरों को तोड़ने से पूरे इलाके का ईकोसिस्टम बदल गया है. आने वाले दिनों में इसके कुप्रभाव देखने को मिलेंगे.'' उनके आरोपों का खंडन करते हुए, योगी सरकार में वाराणसी जिले के प्रभारी मंत्री आशुतोष टंडन कहते हैं, ''मंदिर के आसपास के भवनों से जिस संख्या में मंदिर निकले हैं उससे साबित होता है कि प्राचीन काल में बाबा विश्वनाथ मंदिर परिसर में कई मंदिर थे जिन पर बाद में अतिक्रमण करके भवन बना दिए गए. कॉरिडोर से इन्हें फिर संरक्षित किया गया है.''

तीन हजार वर्ग फुट वाला मंदिर परिसर अब पांच लाख वर्ग फुट वाले कॉरिडोर से जुड़ रहा है जो इसे सीधे गंगा से जोड़ेगा

……

भाजपा को उम्मीद है कि मंदिर परिसर के इस पुनर्विकास से पार्टी को प्रदेश में 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में खासा सियासी फायदा होगा

इस आयोजन से पूर्व माता अन्नपूर्णा की प्रतिमा मंदिर परिसर में स्थापित की गई. स्थापना से पहले निकाली गई इसकी धर्मयात्रा के जरिए भाजपा ने सांस्कृतिक एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया है. 18वीं सदी की यह प्रतिमा 1913 में काशी से चोरी कर कनाडा ले जाई गई थी. यह वहां के रेजिना विश्वविद्यालय में रखी थी. मोदी को इसकी जानकारी मिलने के बाद इसे भारत लाने के प्रयास शुरू हुए. कनाडा से यह मूर्ति मिलने के बाद 11 नवंबर को गोपाष्टमी पर दिल्ली से शोभायात्रा के जरिए गाजियाबाद, अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या होते हुए इसे वाराणसी लाया गया. 15 नवंबर को देवोत्थानी एकादशी पर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसे काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित किया. के.के. मिश्र बताते हैं, ''एक दर्जन शहरों में निकली शोभायात्रा से साफ है कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के मुद्दों के जवाब में भाजपा आक्रामक हिंदुत्व का सहारा लेगी.''

काशी विश्वनाथ कोरिडोर के लोकार्पण को भव्य बनाने और देश भर में संदेश पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को परिवार समेत आने का न्योता भेजा है. कोरिडोर केलोकार्पण के बाद इन नेताओं को परिवार समेत अयोध्या में राम मदिर का भी दर्शन कराया जाएगा.

क्षेत्रीय भाजपा अध्यक्ष महेशचंद्र श्रीवास्तव बताते हैं, ''काशी विश्वनाथ के प्रसाद को गांव-गांव तक पहुंचाया जाएगा. इसके लिए भाजपा पदाधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है कि वे ब्लॉकवार ग्रामीणों को काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कराएं.''

भाजपा की रणनीति पर सवाल खड़े करते हुए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश यादव सरकार में पर्यटन मंत्री रहे ओमप्रकाश सिंह कहते हैं, ''काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट सपा सरकार में शुरू किया गया था. इसके लिए पांच भवनों की खरीद भी की गई थी. जनता भाजपा की नीयत पहचान चुकी है. इसके निर्माण से इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला.'' यह कॉरिडोर भाजपा की सियासी हसरतों का भी कॉरिडोर साबित होगा कि नहीं, यह अगले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे. ■

FROM THOSE BETTING ON EXPERIENCE TO THOSE BATTING ON TALENT

We believe in just one thing.

Your voice matters. Irrespective of who you are, where you come from, where you stand, what you do, and who you support.

We are the **India Today Group.**

Where every voice finds its right.

And every right finds a voice.

WE'RE ALWAYS IN CONVERSATION WITH YOU.

INDIA TODAY GROUP

INDIA'S DEMOCRATIC NEWSROOM

वादी का दुल्हन बाजार

वादी में खर्चीली शादियों की वजह से गरीब युवाओं के लिए जीवनसाथी ढूंढना मुश्किल हो रहा है. अधेड़ उम्र के कशमीरी दलालों की मदद से देश के विभिन्न इलाकों के निपट निर्धन परिवारों की कमसिन लड़कियों को विवाह करने के लिए राजी कर रहे हैं

मोअज्जम मोहम्मद

आई दुल्हन बिहार से

लकवाग्रस्त अब्दुल राशिद शेख श्रीनगर के नौपोरा में बिहार से आई अपनी जीवनसंगिनी और बिटिया के साथ

कश्मीर की वादी में हर साल बर्फ जमने और सर्दियां आने के साथ ही यहां के सैकड़ों स्थानीय लोग बसों और हवाई जहाज से देश के मैदानी इलाकों के लिए निकल पड़ते हैं. इनमें से कई तो ज्यादा गर्म जगहों पर काम-धंधे या कारोबार के वास्ते जाते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं जो हाड़ कंपाती ठंड से बचने के लिए यहां से बाहर जाते हैं. इस लिहाज से 2017 में फैयाज अहमद की यात्रा कुछ ज्यादा ही तनाव भरी साबित हुई. हफ्तों पहले से उन्होंने तैयारी की थी. नए कपड़े सिलवाए, करीबी नाते-रिश्तेदारों से मिले और मोहल्ले के मौलवी की दुआएं भी लीं.

खिचड़ी दाढ़ी और गंजे सिर वाले श्रीनगर के मूल बाशिंदे 54 वर्षीय अहमद कहते हैं, ''दसेक बरस के इंतजार के बाद आखिर मुझे औरत मिली थी. मैं उसे जानता नहीं था पर बहुत खुश था.'' दिहाड़ी मजदूर अहमद बताते हैं कि दुल्हन न मिलने की वजह से इतनी उम्र तक ताने ही सुनता आया. ''इस शर्मिंदगी'' से छुटकारा पाने की तड़प ही उन्हें दुल्हन की तलाश में बस और रेल से 2,000 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल ले गई.

अपनी दास्तान बयान करते-करते अहमद का गला भर आता है. उन्हीं के शब्दों में, ''मेरे रिश्तेदारों के बच्चों तक की शादी हो गई, मगर मैं एक दुल्हन तक नहीं खोज पाया. इस तरह के हालात में एक दिन एक जलसे में एक दलाल ने मेरे लिए कोलकाता में दुल्हन खोजने की पेशकश रख दी.'' अहमद कश्मीर घाटी के उन तमाम अधेड़ों में से हैं जो मुख्यत: अपनी कमजोर सामाजिक हैसियत, शारीरिक खामियों या फिर हाथ से फिसलती उम्र की वजह से इस परेशानी से दो-चार हैं. दूसरी जगहों के लोगों की तरह कश्मीर के परिवार भी अपनी बेटियों की शादी होनहार भविष्य वाले कामकाजी नौजवानों के साथ करना पसंद करते हैं. दुल्हनों की तलाश को लेकर मची इस तरह की बेताबी ने अंतरराज्यीय अवैध व्यापारियों

आबिद भट

अहमद कश्मीर के उन तमाम अधेड़ों में शुमार हैं जो गरीबी, दिव्यांगता या फिर बढ़ती उम्र के चलते इस मुश्किल से दो-चार हैं. अपने लिए कोलकाता से दुल्हन लाने के वास्ते उन्होंने 60,000 रुपए खर्च किए लेकिन तो भी बात बन नहीं पाई

के लिए दरवाजे खोल दिए हैं. वे दो जून की रोटी की खातिर अपनी बेटियों को ब्याह देने के इच्छुक मजबूर परिवारों की कम उम्र लड़कियों की तलाश में रहते हैं.

अपने एक रिश्तेदार को साथ लेकर अहमद दलाल के साथ दुल्हन से मिलने निकल पड़े. तीन दिन के सफर के बाद कोलकाता पहुंचे. दुल्हन आठ भाई-बहनों में चौथी थी. लड़की के वालिद और चाचा अहमद को एक नीम अंधेरे कमरे में ले गए. उन्हें चाय-नाश्ता पेश किया गया. उसके बाद इलाके के ही एक मौलवी ने शाम को 50 बरस के अहमद का निकाह 19 साल की आसिया से करवाया. उससे पहले ‘‘लेन-देन की औपचारिकताएं’’ पूरी की गईं. अहमद एक बार फिर से वह वाकया याद करते हुए बताते हैं, ‘‘लड़की के मां-बाप को 55,000 रुपए दिए और लड़की को 5,000 रुपए की सोने की बालियां दीं. सब कुछ चुपचाप हुआ...मुझे लगता है, पड़ोसियों तक को शादी की भनक नहीं थी.’’

अहमद के एक भाई बताते हैं: हफ्ते भर बाद जब दोनों अपने घर श्रीनगर लौटे तो रिश्तेदार और पड़ोसी दुल्हन के लिए मिठाइयां लेकर नए जोड़े को मुबारकबाद देने आने लगे. मगर जल्दी ही बात बिगड़ने लगी. अहमद के शब्दों में, ‘‘वह फोन लेती और बिस्तर में घुसकर अपने चचेरे-ममरे भाई-बहनों के साथ घंटों बातों में लगी रहती.’’ वे अपने फोन पर आसिया की एक तस्वीर भी दिखाते हैं. तस्वीर में वह गुलाबी ड्रेस पहने थी, जो कि वे उसके लिए लाए थे. अहमद कहते हैं, ‘‘वह भोर तक जागती रहती थी. मुझे उसकी जबान भी समझ नहीं आती. पता ही नहीं चलता कि क्या बात कर रही है. करीब जाता तो रोने-चिल्लाने, हाय-तौबा

मचाने लगती.''

उसके इस बर्ताव पर हक्का-बक्का अहमद ने जोड़ी मिलाने वाले को बुलाया. इस पर उसने लड़की के परिवार से संपर्क साधा और रकम वापस मांगी. अहमद बताते हैं कि ''उसके वालिद और चाचा हमारे घर आए. उन्होंने लड़की को समझाया-बुझाया. उससे भी कुछ नहीं हुआ. मैंने उनसे कह दिया कि वह मेरी बात तो सुनना ही नहीं चाहती.''

अहमद के भाई के मुताबिक, दुल्हन के चाचा ने कहा कि वे रकम नहीं लौटा सकते. वे कहते हैं, ''उन्होंने खुद अपनी बेटी से मेरे भाई की शादी की पेशकश कर दी. यहां तक कि उन्होंने कोलकाता अपनी बीवी को फोन मिलाया और अपनी बेटी को भेजने के लिए कहा. वह लड़की तो इससे भी छोटी थी. हमने पेशकश ठुकरा दी. हमारा पैसा भी हाथ से गया.'' कुछ वक्त लगा पर मायूस मन से अहमद ने फिर मान लिया कि वे शादी के लिए बने ही नहीं हैं. अब वे अपना ज्यादातर वक्त नमाज पढ़ने और टेलीविजन पर आने वाले धर्मप्रचारकों के वीडियो देखते हैं.

अपनी बेटी देने वाले मैदानी इलाकों के ये ढेरों परिवार भी दलालों के झांसे में आ जाते हैं. श्रीनगर के पुराने इलाके में नासिर (बदला हुआ नाम) सेल्समैन हैं. 2014 में उन्होंने बिहार की 22 वर्षीया फहमीदा से निकाह किया. उन्होंने उसे 80,000 रुपए में खरीदा था. वे कहते हैं, ''शादी के लिए 17 साल तक बेसब्री से इंतजार करने के बाद भी मुझे लड़की नहीं मिली. बिहार में मुझे एक दिन में 4-5 लड़कियां दिखाई गईं. सब 20 से कम की थीं. मगर रेट अलग-अलग था. उसी दिन दलाल को रकम देकर मैंने शादी कर ली.''

कई साल बाद उन्हें पता चला कि दलाल ने परिवार को महज 5,000 रुपए दिए. बाकी पैसा खुद रख लिया. नासिर कहते हैं, ''बाद में मैंने खुद अपनी जेब से उन्हें पैसा दिया क्योंकि वे बिल्कुल कंगाली में रह रहे थे. दलाल ने उनसे झूठ बोला, कहा कि मैं कारोबारी और ठीक-ठाक हैसियत वाला हूं. उन्होंने नेग के तौर पर 5,000 लिए, जबकि दलाल ने उन्हें 50,000 देने का वादा किया था. अब मैं सफर का खर्च नहीं उठा सकता, इसलिए तब से उसे उसके घर भी नहीं ले जा पाया हूं.''

हालांकि कोई भरोसेमंद आंकड़े नहीं हैं, पर ''बंगाली दुल्हन खरीदना'' घाटी के शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में आम-सी बात हो गई है. श्रीनगर के बेमिना की बोटमैन कॉलोनी को ही लीजिए, जिसका डल झील से यहां लाकर बसाए गए लोगों पर नाम पड़ा है. यहां काम कर चुकी सामाजिक कार्यकर्ताओं का एक मोटा अंदाजा है कि यहां ऐसी 200 औरतें हैं. इसी तरह दक्षिण और उत्तर कश्मीर के कई गांवों के आदमियों के लिए दर्जनों ऐसी औरतें खरीदी गई हैं. ये वे लोग हैं जो कश्मीर की महंगी शादियों का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते. यहां की शादियों का खर्च बाज दफे लोगों को मुफलिसी की हालत में ला छोड़ता है (पिछली सरकारों ने मेहमानों की तादाद और वाजवान पकवानों पर पाबंदियां लगाकर इस रुझान को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी, पर सब बेकार).

सना मजीद दीन अनंतनाग की जिला बाल संरक्षण इकाई में लीगल-कम-प्रोबेशन अधिकारी हैं. वे बताती हैं कि ज्यादातर औरतें किसी न किसी बहाने से खरीदकर लाई जाती हैं. लिहाजा यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये शादियां कानूनन की गई हैं या खरीद-फरोख्त के मामले हैं. उन्होंने 1 नवंबर को असम के शिवसागर जिले की एक नाबालिग लड़की को छुड़ाया. उसे फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में नौकरी दिलवाने का वादा करके यहां लाया गया था. सना बताती हैं, ''वह अक्तूबर में

काम नहीं तो दुल्हन कैसे मिले

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में बेरोजगारी की दर 22.2 फीसद है जो कि भारत में सबसे ज्यादा है. कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री की मानें तो 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के बाद यहां के 5,00,000 लोगों ने अपनी नौकरियां गवांई हैं. नौकरी की असुरक्षा और दहशतगर्दों के खिलाफ चल रहे सशस्त्र टकराव ने बड़े पैमाने पर अनिश्चितता पैदा कर दी है. लोग अब सरकारी नौकरी को तरजीह देने लगे हैं. जम्मू और कश्मीर में 4,50,000 कर्मचारियों के साथ सचमुच सरकार ही सबसे नौकरियां देने वाली इकाई है. नौकरी को लेकर इसी ऊहापोह के चलते शादियां देर से होती हैं क्योंकि सुरक्षित नौकरी वाले दूल्हे मुश्किल से मिलते हैं. कामकाज के मोर्चे पर महिलाओं की तादाद बढ़ने से भी पुरुषों के लिए पेशे का संकट बढ़ा है.

श्रीनगर के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) की सदस्य डॉ. आसिमा हसन कहती हैं, ''खासकर मिडल क्लास की औरतें अब हायर एजुकेशन में जा रही हैं और उनमें बेहतर नौकरियों के लिए खासी ललक है. इससे भी उनके लिए उसी पाए का लड़का मिलने की संभावना कमजोर पड़ जाती है.'' डॉ. हसन ने 'कॉन्फ्लिक्ट ऐंड यूथ इन कश्मीर' विषय पर शोध कार्य भी किया है. वे बताती हैं कि कश्मीर में और खासकर शहरी इलाकों में देर से शादियों होने में दहेज और बेहद खर्चीली शादियों की परंपरा का भी अहम रोल है.

'पारंपरिक तरीके से जोड़ी मिलाने' के लिए जाने जाते रहे, श्रीनगर के बाहरी इलाके नारबल के गुलजार अहमद बताते हैं कि उन्हें जोड़ा मिलाने में बरसों लग जाते हैं क्योंकि हर कोई ऐसा दूल्हा चाहता है जिसका तयशुदा करियर हो और अच्छी-खासी माली हालत हो. कोविड ने यह मुश्किल और बढ़ा दी है. कश्मीर में नुक्सान इसलिए और भी ज्यादा हुआ क्योंकि लॉकडाउन के पहले उसे 2019 में जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म होने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन रोकने के लिए सैन्य बंदी से गुजरना पड़ा था.

आबिद भट

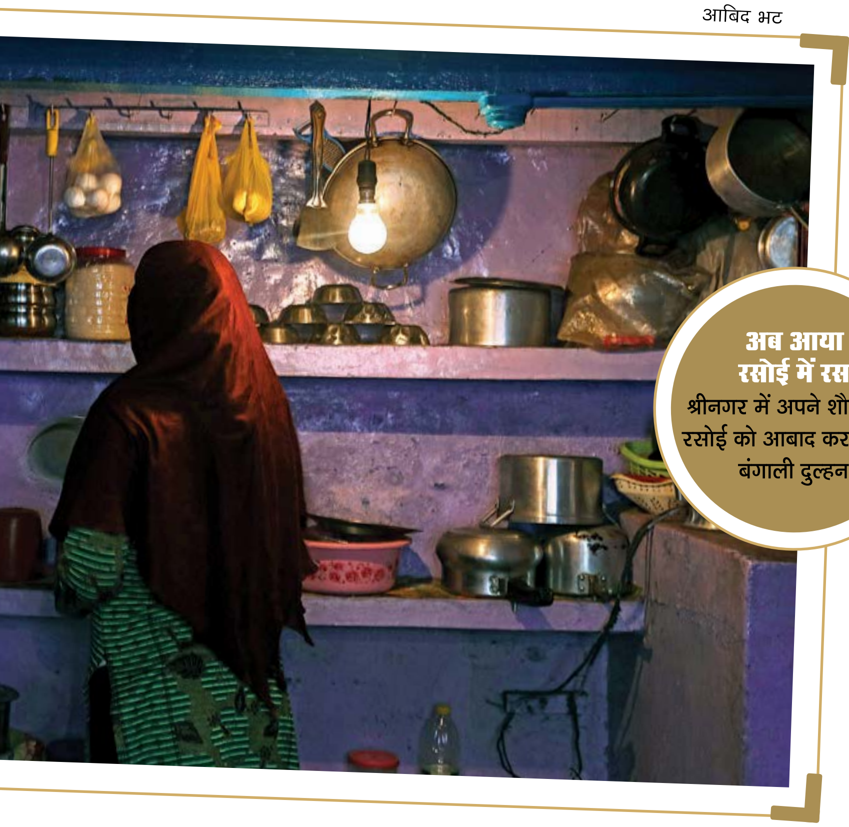

अब आया रसोई में रस

श्रीनगर में अपने शौहर की रसोई को आबाद करती एक बंगाली दुल्हन

> **वैसे इसका अभी तक कोई ठोस आंकड़ा तो नहीं मिल पाया है पर अब ''बंगाली दुल्हन खरीदकर लाना'' घाटी के शहरी और ग्रामीण दोनों ही इलाके में आम चलन बन गया है**

इतना लंबा सफर करके अपने गांव की आठ और लड़कियों के साथ यहां आई. उनके पड़ोसी ने 5,000 रुपए महीने की तनख्वाह के वादे से उन्हें फुसलाया था. पर उस नाबालिग लड़की को कश्मीर में घरेलू नौकरानी के तौर पर एक परिवार को बेच दिया गया. वह किसी तरह भागकर अनंतनाग रेलवे स्टेशन जा पहुंची. वहां पुलिस ने उसे छुड़वाया.''

पर सब इस असमिया लड़की की तरह नहीं होतीं. उनमें से ज्यादातर भाग नहीं पातीं और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देती हैं. घाटी के जाने-माने क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉ. मुजफ्फर खान कहते हैं कि ऐसी कई कम उम्र लड़कियां मानसिक विकारों की शिकार हैं. यहां कई साल बिताने के बाद भी उन्हें बाहरी माना जाता है. उनसे जन्मे बच्चों के साथ भेदभाव भी होता है. अक्सर उनके 'बंगाल', 'बिहार' या 'पंजाब' सरीखे नाम रख दिए जाते हैं. घाटी में एक बड़े नशा पुनर्वास केंद्र के मुखिया डॉ. खान कहते हैं, ''आदमी नशे का लती हुआ या उसकी पहली शादी बिगड़ गई हो तो समस्या और विकराल हो जाती है.''

हालांकि ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2020-21 के आंकड़े बताते हैं कि जम्मू-कश्मीर में मानव तस्करी का केवल एक मामला दर्ज हुआ. अधिकारी इसकी वजह बताते हैं कि अमूमन तो मामला दाखिल ही नहीं किया जाता. मगर विशेषज्ञों का कहना है कि सरकारी निगरानी का कोई तंत्र ही नहीं है. सना जमीनी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को जोड़ने का सुझाव देती हैं, जो अधिकारियों को इन 'शादियों' की इत्तला दे सकती हैं. वे कहती हैं, ''इन औरतों के लिए पुलिस के पास जाना भी मुहाल है, क्योंकि उन्हें जगह की मालूमात है, न जबान की. न ही वे किसी को जानती हैं.''

वकील फैसल कादरी कहते हैं, ''उन्हें तो अक्सर फोन तक रखने नहीं दिया जाता. उन्हें ससुराल वालों की लगातार निगरानी में भी रहना पड़ता है.'' जम्मू-कश्मीर में ऐसे ही एक मामले को चुनौती देने के लिए यूएनएचसीआर ने कादरी की सेवाएं ली थीं. म्यांमार की एक नाबालिग रोहिंग्या लड़की तस्करी के जरिए कश्मीर लाकर 2015 में 80,000 रुपए में अनंतनाग के एक अधेड़ आदमी को बेच दी गई थी. महीनों बाद वह म्यांमार में अपने माता-पिता से संपर्क करने में सफल रही. परिजनों ने दिल्ली में कार्यरत उसके चाचा को फोन किया. उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का दरवाजा खटखटाया, जिसने फिर वह मामला उठाया. कादरी कहते हैं, ''छल-प्रपंच से ब्याह कर या घरेलू नौकरानी बनाकर लाई गई इन लड़कियों की नामजदगी की कोई व्यवस्था होनी चाहिए. ये बंधुआ मजदूर की तरह हैं. इनकी प्लेसमेंट एजेंसियों का भी पंजीकरण होना चाहिए.''

कमजोर बैसाखियां

कम उम्र से ही पैरों से लाचार अब्दुल राशिद शेख ने कई बार ठुकरा दिए जाने के बाद 43 की उम्र में बिहार की एक लड़की से निकाह किया. कोविड महामारी के दौरान जून 2020 में वे सफर करके बिहार की राजधानी पटना गए. परिवार वीडियो कॉल पर बात करके रिश्ते के लिए तैयार हुआ. हालांकि शुरुआत में उन्होंने ठुकरा दिया था. जेऐंडके हैंडीकैप्ड एसोसिएशन के संस्थापक शेख कहते हैं, ''पर बाद में वे मान गए.''

निकाह की रस्में स्थानीय मौलवी ने पूरी कीं. डल झील के किनारे खाने की दुकान भी चलाने वाले शेख कहते हैं, ''मैंने लड़की को पहले नहीं देखा था. असल में, वे उस शाम कुछ इस फुर्ती से मौलवी को लाए और शादी की तैयारियां कीं कि मैं दंग रह गया.'' अब वे श्रीनगर के नौपोरा मुहल्ले में अपनी बीवी के साथ रहते हैं. शेख कहते हैं कि पूरी शादी का खर्च 1.2 लाख रुपए आया. 10,000 रुपए इसमें दलाल के थे. लड़की के कपड़ों और गहनों के लिए परिवार ने भी 15,000 रुपए लिए. शेख को लड़की के माता-पिता से तोहफे भी मिले. वे कहते हैं. ''गरीबी ही बड़ी वजह है जिससे उन्होंने मुझे लड़की दी. उनके परिवार ने चांदी की जो चीजें दी थीं, वे तो मैंने लौटा दीं. उन्होंने कहा कि वे अपनी छोटी बेटी की शादी के लिए इन्हें रखे रहेंगे.'' ■

मंदार देवधर

सबसे पहले पौष्टिक आहार
श्रीरामपुर के एसडीएमटी हेल्थ क्लिनिक में शिवानी दहानुकर (बीच मे काले परिधान में)

श्रीमती मालती दहानुकर ट्रस्ट

श्रीरामपुर

महाराष्ट्र

सेहतभरी *मुस्कान*

प्रसन्नता का प्रसारः यह ट्रस्ट कुपोषण मिटाने के लिए माताओं को शिक्षित करने, बच्चों को पौष्टिक आहार देने और स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने की दिशा में काम कर रहा है

किरण डी. तारे

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के तिलक नगर इलाके में रहने वाली गृहिणी अश्विनी ढोकचौले लोगों को यह बताते नहीं थकतीं कि कैसे उनके एक साल के पहले बच्चे शिवतेज ने सिर्फ छह महीने की उम्र में अंडे खाना शुरू कर दिया था. उनके स्वस्थ बच्चे का वजन अब 11.45 किलो है जबकि उसकी उम्र के बच्चों का औसत वजन 9.5 किलो है. उसकी लंबाई 77 सेंटीमीटर है जो उसी उम्र के अन्य बच्चों की तुलना में 2 सेमी ज्यादा है. कृषि स्नातक अश्विनी कहती हैं, ''जब मेरा बेटा तीन महीने का था और उलटी करता रहता था तब मैं उसे केयर सेंटर लाई थी. यहां के डॉक्टरों ने मेरे और मेरे बच्चे के लिए पोषण योजना तैयार की, जिससे हम फिट और स्वस्थ हो गए.''

अश्विनी अपने बच्चे को लेकर जिस केयर सेंटर पर गई थी वह श्रीमती मालती दहानुकर ट्रस्ट (एसएमडीटी) की ओर से संचालित है और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत पौष्टिक चावल देने की नीति की घोषणा किए जाने से बहुत पहले से छोटे बच्चों को पौष्टिक चावल दे रहा है.

एसएमडीटी की ट्रस्टी शिवानी दहानुकर और उनकी पोषण विशेषज्ञ मित्र डॉ. रूपल दलाल के बीच एक बातचीत के बाद से एसएमडीटी ने 2010 में कुपोषण के क्षेत्र में काम करना शुरू किया. एक डिस्टिलरी चलाने वाले परिवार से आने वाली दहानुकर बताती हैं, ''मैंने रूपल से पूछा था कि क्या हम तिलक नगर में एक चिकित्सा शिविर आयोजित कर सकते हैं.'' वे कहती हैं, ''रूपल इसकी बजाए कुपोषण पर ध्यान केंद्रित करने के विचार ले आई.'' तब से, एसएमडीटी ने आसपास के 52 इलाकों की 11,000 गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और उनके बच्चों को पोषण संबंधी टिप्स और भोजन प्रदान किया है.

एसएमडीटी गर्भावस्था की तारीख से पहले 1,000 दिनों तक मां और बच्चे की देखभाल करता है और अगर आवश्यक हो तो बच्चे की पांच साल की उम्र तक निगरानी की जाती है. इसका नतीजा है कि ज्यादातर मजदूरों और दूसरे श्रमिकों के निवास के इन 52 क्षेत्रों में आपको एसएएम (गंभीर तीव्र कुपोषण) या एमएएम (मध्यम तीव्र कुपोषण) से पीड़ित किसी भी बच्चे के बारे में सुनने को नहीं मिलेगा.

जीवन और आहार में प्रसन्नता के गुर

सुवीर सरन

शेफ, लेखक, उद्यमी और कंसल्टेंट

चॉकलेट केकलेट, भिगोई हुई बेरी, कॉन्ट्रो क्रीम, फ्रैशे क्रीम, और एरलूम फ्लो ब्लू चाइना.

यह कला का खाने योग्य रूप होने के साथ साथ अतीत की यादों, वर्तमान का उत्सव और भविष्य के लिए सृजित एक स्मृति है

जीवन हमारी अपनी यात्रा की छोटी-बड़ी स्मृतियों का घालमेल है जिसमें हमारे सामने आने वाले दूसरों की यात्राओं के टुकड़े भी शामिल होते हैं. इसी में अलग-अलग टुकड़े उन लोगों से भी जुड़े होते हैं जो हमारे साथ मिलकर रहते हैं. इसी में हमारे बाद आने वालों को जोड़ने वाले संयोजी ऊतक भी होते हैं.

व्यक्ति के रूप में और परंपरा के रूप में टुकड़ों में सुंदरता को समग्र रूप से देख पाने का मतलब है जीना, प्यार करना और मुक्त हो पाना.

मैं कभी सिर्फ अपने लिए खाना नहीं बनाता. एक व्यक्ति के लिए खाना बनाना, दो लोगों के लिए खाना बनाना या 20 लोगों के लिए खाना बनाने में लगभग बराबर ही समय लगता है, तो क्यों न मैं अपने श्रम का फल दूसरों के साथ बांटूं, जिसका मूड, जीवन और आत्म-सम्मान सिर्फ यह जानकर बढ़ जाएगा कि कोई दूसरा सिर्फ उनकी खुशी के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है.

अच्छी सामग्री से बना सादा भोजन बना कर मैं चीजों को अपने लिए बहुत सहज रखता हूं. मैं इन चीजों को बिल्कुल पारंपरिक तरीके से रखता हूं जब तक कि कोई ऐसा बढ़िया विकल्प न हो जो सामग्री लेने के मेरे सार्वजनिक रूप से ज्ञात मानकों—स्थानीय और मौसमी चीजों का प्रयोग करना—पर खरे उतरते हों.

मैं दूसरे के लिए खाना बनाना, उन्हें अपने घर पर आमंत्रित करना और उनके साथ बैठने को जीवन की ओर से मुझे घर की साफ-सफाई करने के लिए, चीजों को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर के आसपास कुछ भावनात्मक समय बिताने के लिए मिले अवसर के रूप में देखता हूं और इस दौरान वैसी ही आलोचनात्मक नजर रखता हूं जैसी कि अपने क्लाइंट्स के लिए रखता हूं.

मेरी सजावट हमेशा अधूरी रह जाती है. मैं कभी टेबल सेट नहीं करता, लेकिन मुझे पता होता है कि मैं किन बर्तनों का उपयोग करूंगा. खाना परोसने की तैयारी करते हुए जब मैं जब अपने मेहमानों को नैपकिन ले लेने या टेबल सेट कर लेने के लिए कहता हूं तो उन्हें महसूस करवाता हूं कि वे मेरे लिए परिवार जैसे हैं. ऐसा करने से भोजन तैयार करने और ग्रहण करने में सभी का साझा स्वामित्व पैदा होता है और वे इसकी परिणति से गहराई से जुड़ जाते हैं.

दूसरों के लिए खाना बनाना मेरे लिए बिना स्वार्थी लगे अपने मन के प्रयोग करने का मौका होता है. यह मुझे उन लोगों के साथ समय बिताने का मौका देता है जिन्हें मैं सामान्यतः नहीं देख पाता. यह मुझे अपनी भावनाओं को बाहर लाने और उन पर मनन करने का मौका देता है. यह सब मुझे थका देने के साथ ही मेरी आत्मा को जगा देता है.

यहां तक कि सिर्फ एक ब्राउनी केकलेट परोसने के पीछे भी कोई कहानी और एक उद्देश्य होता है. साधारण से साधारण होते हुए भी इसे पूरे विचार के साथ, घटकों की शुद्धता, समृद्ध ऐतिहासिकता और प्राचीनता के महत्व के साथ परोसा जाता है.

जरूरतमंद माताओं और बच्चों की तलाश में एसएमडीटी कार्यकर्ता प्रति दिन औसतन 10 परिवारों के पास जाते हैं. एसएमडीटी में फील्ड ऑफिसर शीतल हिवाले बताती हैं, ''हम अपने पोषण कार्यक्रम में आने के लिए हर परिवार में सास को मनाते हैं. माताओं और बच्चों को स्वस्थ बनाने में यह प्रयास काफी सफल रहा है.''

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे की मदद से एसएमडीटी ने माताओं को शिक्षित करने के लिए ग्राफिक और ऑडियो-विजुअल प्रारूपों में 18 चार्ट बनाए हैं. विशेषज्ञों ने चावल को ज्यादा पौष्टिक बनाने के लिए घरेलू सब्जियों का उपयोग करते हुए कई व्यंजन तैयार किए हैं. वे स्तनपान के बारे में गलत धारणाओं को दूर करने पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं. दहानुकर कहती हैं, ''यह कार्यक्रम महिलाओं को अपने दम पर सशक्त बनने और बच्चों को स्वस्थ बनाने के बारे में है.'' वे बताती हैं कि हम माताओं को उनकी ताकत का एहसास कराने के लिए स्तनपान कराने पर जोर देते हैं.

खुशी का मंत्र

''मैं देने के विचार पर विश्वास करती हूं. आप कुछ देंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे. प्रेम में बहुत आनंद है, इसके कई रूप हो सकते हैं—साझा करना उनमें से ही एक है''

कुपोषित बच्चों को खोजने और उनकी माताओं को सलाह देने के लिए एसएमडीटी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपने 'टीच द ट्रेनर' कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित भी करता है. ट्रस्ट ने अब तक महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं. ट्रस्ट ने भारत के सबसे कुपोषित क्षेत्र, महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में स्थित राजुरा को कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य भी रखा है. आइआइटी बॉम्बे की मदद से इसने राजुरा को छह ब्लॉकों में विभाजित करने और बच्चों की निगरानी के लिए प्रत्येक ब्लॉक पर अलग से ध्यान केंद्रित करने की योजना तैयार की है. योजना तैयार है पर अभी शुरू नहीं हुई है.

ढोकचौले जैसे लोग ही दहानुकर को काम में लगे रहने की प्रेरण देते हैं. भले ही ढोकचौले आर्थिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन शिवतेज के इलाज के लिए वे कहीं और नहीं जाती. ढोकचौले के मुताबिक, ''यह विश्वास ही है जो मुझे एसएमडीटी से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है.'' दहानुकर पोषण के बारे में मिथकों को दूर करने में सफल होने का श्रेय मजबूत और समर्पित टीम को देती हैं.

खुशी की खोजः *इंडिया टुडे और आरपीजी समूह का संयुक्त उद्यम है जो खुशियां बांटने की अनुकरणीय पहल का उत्सव मनाता है*

पुस्तक अंश

संशोधन प्रस्ताव वापस

वरिष्ठ पत्रकार **रामबहादुर राय** की यह पुस्तक संविधान बनने से जुड़ी घटनाओं के पीछे की कहानियां दिलचस्प ढंग से कहती है. उक्त शीर्षक वाला एक अध्याय हम यहां छाप रहे हैं

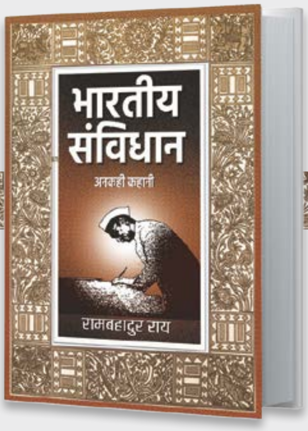

भारतीय संविधानः अनकही कहानी
लेखकः रामबहादुर राय
प्रकाशकः प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली
कीमतः 1,100 रुपए

बहस समापन की ओर बढ़ रही थी. साथ-साथ सहमति के स्वर एक होने लगे थे. संविधान सभा के सदस्य लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव का महत्व समझ रहे थे. सवाल रास्ते का था. इस पर ही हर वक्ता बोले. वे संविधान सभा की प्राथमिकताओं को बताने, गिनाने और रेखांकित करने का प्रयास करते थे. ऐसे ही कुछ भाषण 21 जनवरी, 1947 को हुए. जिसमें एच.जे. खांडेकर का भाषण उस समय भी बहुतचर्चित हुआ और आज भी प्रासंगिक है. वे हिंदी में बोले. उनका आग्रह था कि संविधान हिंदी में बने. उनके शब्द हैं—''हिंदुस्तान का जब संविधान बनने जा रहा है तो हमें उसे अपनी देशी भाषा में ही बनाना चाहिए. अपनी राष्ट्र भाषा में ही बनाना चाहिए.'' इस भूमिका के बाद उनका कहना था कि मैं इसीलिए अपना भाषण हिंदुस्तानी में कर रहा हूं. वे अनुसूचितजाति से थे. उन्होंने दावा किया कि वे पूरी अनुसूचितजाति की ओर से बोल रहे हैं. इस दावे के आधार पर उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर की उस मांग को अनुचित ठहराया, जिसमें वे अनुसूचितजाति के लिए अलग चुनाव क्षेत्र मांग रहे थे. खांडेकर का यह कथन उस समय की वास्तविक चिंता को प्रकट करता है. उन्होंने कहा—''अनुसूचितजाति पर अत्याचार हुए हैं, और हो रहे हैं. फिर भी हमने अपना धैर्य नहीं खोया. हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और इसी रूप में अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे. लेकिन यह नहीं कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं.'' उनके भाषण से यह सूचना मिलती है कि नोआखाली के नरसंहार में 'नब्बे फीसदी अत्याचार अनुसूचितजाति' के लोगों पर हुआ. उन्हें संविधान सभा की संरचना के आधार पर आपत्ति थी, जिसे प्रकट किया. अंग्रेजों ने आबादी के एक हिस्से को अपराधी घोषित कर दिया था. उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू का प्रस्ताव मौन था. इसे ही उन्होंने प्रस्ताव की कमी बताया. उनकी मांग थी कि 'इस कानून को हटाने के लिए प्रस्ताव में प्रावधान होना चाहिए.'

उसी दिन रघुनाथ विनायक धुलेकर ने एक लंबा भाषण किया, जो सबसे अलग था. वे भी हिंदी में बोले. उन्होंने शुरुआत भी अलग तरह से की. संविधान सभा के लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर उनसे पहले जो भी भाषण हुए थे, उनमें ज्यादातर ने गांधीजी का उल्लेख चलते-चलाते कर दिया था. लेकिन धुलेकर ने यह जरूरी समझा कि वे महात्मा गांधी के जीवन-दर्शन का सार पहले बता दें. इसलिए उन्होंने कहा कि 'महात्मा गांधी ने मानवजीवन के तत्त्व को दो शब्दों में रख दिया है, सत्य और अहिंसा. जो न्याय है, जो उचित है, जो धारण करने योग्य है, अर्थात धर्म है, वही सत्य है. जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है, दूसरों की संपत्ति और स्वतंत्रता का अपहरण नहीं करता, जो दूसरों के जीवन की, सामाजिक जीवन की रक्षा करता है, वही सत्य है, वही अहिंसा है.'

उन्होंने प्रस्ताव का न केवल समर्थन किया, बल्कि यह कहा कि, ''कोई भी विचारवान मनुष्य इस प्रस्ताव के किसी भी अंग पर आपत्ति नहीं उठा सकता. इसमें समस्त भारतीयों को रक्षा का वचन दिया गया है. पिछड़ी हुई और पद दलित जातियों पर विदेशियों ने जो अन्याय किया है, उसको पूरी तरह से हटाने और उनकी उन्नति के अवसरों को प्राप्त करा देने का वचन दिया गया है.''

उस समय अनेक वक्ताओं ने यह सवाल

उठाया था कि देशी रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा में नहीं हैं. इसका उन्होंने उचित उत्तर दिया. यह बताया कि कैबिनेट मिशन की घोषणा में जो प्रावधान है, उसके कारण रियासतों के प्रतिनिधियों को आखिर में आना है. उन्होंने भी मुसलिम लीग की अनुपस्थिति को अनुचित ठहराया. लॉर्ड साइमन और चर्चिल के कथन की निंदा की. ब्रिटेन को उन्होंने चेतावनी भी दे दी. प्रस्ताव में अल्पसंख्यक समूहों और पिछड़ी जातियों के लिए जो प्रावधान थे, उनके बारे में धुलेकर का दृष्टिकोण सबसे अलग था. हालांकि वे कांग्रेस के सदस्य थे, स्वाधीनता सेनानी थे, लेकिन उनके भाषण का स्वर कुछ अलग ही था. जैसे वे कहते हैं कि, ''विशेष प्रावधान का प्रश्न तभी उठता है, जब अन्याय का भय हो.''

वे अस्पृश्यता को ऐसा अपराध समझते हैं, जो अक्षम्य है. इसे मिटाने का आश्वासन संविधान के लक्ष्य में वे पाते हैं. यह कहने के बाद जो बात उन्होंने रखी, वह नई है. इस अर्थ में कि उसकी चर्चा संविधान सभा में किसी दूसरे ने नहीं की. उन्होंने कहा कि, ''विदेशियों ने यहां आकर अपनी राजसत्ता को कायम करने के लिए असमानताओं को बढ़ाया. द्वेष और दुर्भावनाओं को उत्पन्न किया. नई-नई गुत्थियां बना दीं...'ब्राह्मण-अब्राह्मण को, छूत-अछूत को, हिंदू-मुसलमान को, हिंदू-सिख को, आदिवासी और गैर-आदिवासी आदि को अंग्रेजों ने अपनी कुटिल चालों से अलग-अलग कर दिया.'' उन्होंने पूछा कि ''क्या उनका भी अपराध हम अपने सिर पर ढोना चाहते हैं?'' उनका कहना था कि जिस सुरक्षा के विशेष अधिकारों की आड़ में अंग्रेज बहेलिया शिकार खेलता था, जिन विशेषाधिकार की सुगंध सुंघाकर अंग्रेज ने हमें महानिद्रा में सुलादिया था, उसी सुगंधि युक्त विष को अब न सूंघिए. यह विधान आप स्वयं बना रहे हैं. अब मतभेद मिटा दिया जाएगा. न कोई बहकाने वाला है और न किसी को बहकाने की आवश्यकता है. विशेषाधिकारों से असमानता नहीं मिट सकती. गड्ढों और टीलों को सुरक्षित रखकर समतल कैसे बनाया जा सकता है; आइए, हम सब मिलकर...असमानता हटा, सबको समानाधिकार प्राप्त कराएं.''

उन्होंने भारतीय इतिहास के हजार साल का जैसा वर्णन किया, वह सबसे अलग था कि भारत बीते हजार साल से स्वाधीन होने के लिए संघर्षरत है. वह घड़ी आ गई है, जब भारत स्वतंत्र हो जाए. जो संघर्ष चला, वह अविराम था. उसमें साधु-संतों ने बड़ी भूमिका निभाई. स्वामी रामदास, गोस्वामी तुलसीदास, गुरु नानक, स्वामीदयानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और रामतीर्थ आदि इस परंपरा के प्रतिनिधि हैं. उन्होंने कहा कि दूसरी ओर शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप, झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, राजाराममोहन राय, लोकमान्य तिलक, पं. मोतीलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आदि उस धारा के राजनीतिक व्यक्तित्व थे. महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान में संत और राजनीतिज्ञ का समन्वय है. उन्होंने कहा कि भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई दो सौ सालों से जारी है. कांग्रेस का इतिहास भी बलिदानों का है. उन्होंने खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद के बलिदान की याद दिलाई. यह कहा कि कांग्रेसजन ने भी अदम्य साहस और धैर्य का परिचय दिया है. इस कारण ही ब्रिटेन को समय-समय पर भारत के लोगों की मांगें मजबूरन माननी पड़ीं. विश्व युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन मजबूर हो गया था. उसे भारत को संविधान सभा देनी पड़ी, जो स्वाधीनता की पहली सीढ़ी है. उन्होंने भरोसा जताया कि संविधान सभा का निर्णय ब्रिटेन की सरकार को मानना ही पड़ेगा. इसलिए उन्हें यह आवश्यक लगा कि ऐसे समय हर भारतीय परिस्थिति को समझे. वह निर्भय रहे. स्वतंत्र भारत सबके साथ न्याय करे. धुलेकर उत्तर प्रदेश के झांसी से थे.

> (एच.जे.) खांडेकर ने अनुसूचित जाति के लिए अलग चुनाव क्षेत्र की डॉ. आंबेडकर की मांग को अनुचित ठहराया...उन्होंने कहा, ''हम हिंदू हैं, हिंदू ही रहेंगे और इसी रूप में अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे लेकिन यह नहीं कहेंगे कि हम हिंदू नहीं हैं''

लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव के इस चरण में प्रो. एन.जी. रंगा, के.के. सेन, जगत नारायणलाल, अलगू राय शास्त्री और विश्वनाथ दास के भी भाषण हुए. हर व्यक्ति के भाषण में स्वाधीनता संग्राम के सिद्धांत की जहां व्याख्या थी, वहीं सुझाव थे कि नई परिस्थिति में भारत की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हर वक्ता ने भाषण में जल्दबाजी नहीं की. लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया, लेकिन उनके भाषण में समुदाय, वर्गविशेष, जाति की जरूरतों को चिन्हित करने के प्रयास हैं. इस कड़ी में एस.एच. प्रेटर का नाम लिया जा सकता है. वे मद्रास से थे, जो आज चेन्नै है. प्रेटर ईसाई समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे. जैसे ही उन्होंने कहा कि, ''मेरे संप्रदाय के एक प्रतिनिधि ने लक्ष्य संबंधी प्रस्ताव पर विचार स्थगित करने का समर्थन किया था, अब ऐसी बात करना अनुचित होगा'', तो सदन में 'वाह-वाह' की आवाज उठी. उन्होंने उसके बाद यह जोड़ा और जोर देकर कहा कि प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए.

संविधान सभा के इतिहास में 21 जनवरी, 1947 का दिन विशेष है. उसी दिन डॉ. मुकुंदराम राव जयकरने अपना संशोधन वापस लिया. उससे पहले वे बोले कि मेरे संशोधन प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि मुसलिम लीग व रियासतों के प्रतिनिधि संविधान सभा की कार्यवाही में सुगमता से शामिल हो सकें, इसलिए संविधान सभा की कार्यवाही को स्थगित रखने का प्रस्ताव मैंने प्रस्तुत किया था. संविधान सभा ने 20 जनवरी तक अपनी कार्यवाही स्थगित की. फिर भी मुसलिम लीग नहीं आई. इसलिए उन्होंने अपना यह इरादा जताया कि वे अपना संशोधन वापस लेना चाहते हैं. उनके शब्द थे—''मैं अपने संशोधन को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता.'' यह कहने के बाद वे कुछ और बोलना चाहते थे. तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने उनसे पूछा कि क्या वे कोई नया प्रस्ताव ला रहे हैं? इसका वे उत्तर देते, इससे पहले ही पं. गोविंद बल्लभ पंत सहित अनेक सदस्यों ने उनके बोलने पर आपत्ति की. जो लोग आपत्ति कर रहे थे, उनका तर्क था कि जयकर ने अपना संशोधन वापस ले लिया है, इसलिए वे कोई नया प्रस्ताव नहीं ला सकते. अध्यक्ष ने भी उन्हें अनुमति नहीं दी. इस तरह डॉ. जयकर का संशोधन सदन की अनुमति से वापस हो गया. ■

सवाल + जवाब

“करुणा बड़ी कारसाज है”

लेखिका और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (जेएलएफ) की को-डायरेक्टर **नमिता गोखले** अपने भीतर की उत्तेजना को आशावाद से संतुलित करती हैं. ऐसे में स्वाभाविक तौर पर उनके नए उपन्यास और जेएलएफ पर उनके विचारों में एक सजग किस्म की उम्मीद दिखती है

● ***ब्लाइंड मेट्रियार्क*** **महामारी के शुरुआती दिनों की भावभूमि पर है. कोविड अभी जाता हुआ दिखता नहीं. इसमें बदलाव का असाधारण समय दर्ज हुआ है.**
इसका बहुत कुछ किताब में गद्य के वास्तु पर और संपादक के रवैए पर निर्भर है. मेरे पिछले नॉवेल *जयपुर जर्नल्स* में बहुत-से स्वर, लोग और उतनी ही कहानियां गुंथी थीं. उससे उसकी वास्तुरचना और संपादन के लिए खास किस्म के शिल्प, दक्षता और एकाग्रता की जरूरत थी. लेकिन नए उपन्यास की कहानी लीनियर होने की वजह से इसका फ्रेमवर्क उतना जटिल नहीं था.

● **आपके उपन्यास में परिवार और राष्ट्र एक-दूसरे की जगह लेते दिखते हैं. क्या चीज है जो दोनों को जोड़ सकती है?**
नहीं, एक-दूसरे की जगह नहीं ले सकते, हां, परिवार और राष्ट्र का अक्स एक-दूसरे में दिखता है. नायिका मातंगी कहीं पर मेरे लिए, हमारे आसपास घूम रही करोड़ों भारत माताओं में से ही एक भारत माता है. मुझे लगता है, करुणा जोड़ती है, जैसा कि प्रगतिशील सोच और पूर्वाभास के जरिए मातंगी परिवार को जोड़े रखती है.

● **उपन्यास में आशा का एक भाव आपका हाथ थामे दिखता है. एक व्यक्ति के तौर पर आप कितनी आशावादी हैं?**
में मूर्खता की हद तक आशावादी हूं और बेहद बेचैन भी. हमेशा बुरे से बुरे हालात का ख्याल कर परेशान हो उठती हूं. अपने परिचितों में मैं सबसे बेचैन आत्माओं में से हूं. हमेशा बदतर के बारे में सोचती रहती हूं. पर हैरत की बात है कि मुझे भीतर कहीं न कहीं लगता रहता है कि इससे निबट लेंगे या फिर यह कि अच्छा ही होगा.

● **जेएलएफ की संस्थापक और को-डायरेक्टर के नाते क्या आपको इस बात की निराशा है कि डिग्गी पैलेस के उस भव्य परिवेश की बजाए सब कुछ कंप्यूटर स्क्रीन पर घट रहा है?**
वैसे, इस बार मौके पर ही आयोजन हो रहा है, हालांकि सुरक्षा वजहों से मुख्य फेस्टिवल हम डिग्गी पैलेस में नहीं करवा सकेंगे. पर पैलेस से मेरा रिश्ता पहले जैसा ही रहने वाला है. हां, जहां तक स्क्रीन वाली बात है तो एकरसता वाला फॉर्मेट होने से जूम थोड़ा उबाऊ हो सकता है. पर मुझे लगता है, आगामी वर्षों में टेक्नोलॉजी हमारे सामने आश्चर्यजनक अवसर मुहैया कर सकती है.

—श्रीवत्स नेवटिया

चंदीप सिंह

देश का नं. 1
हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

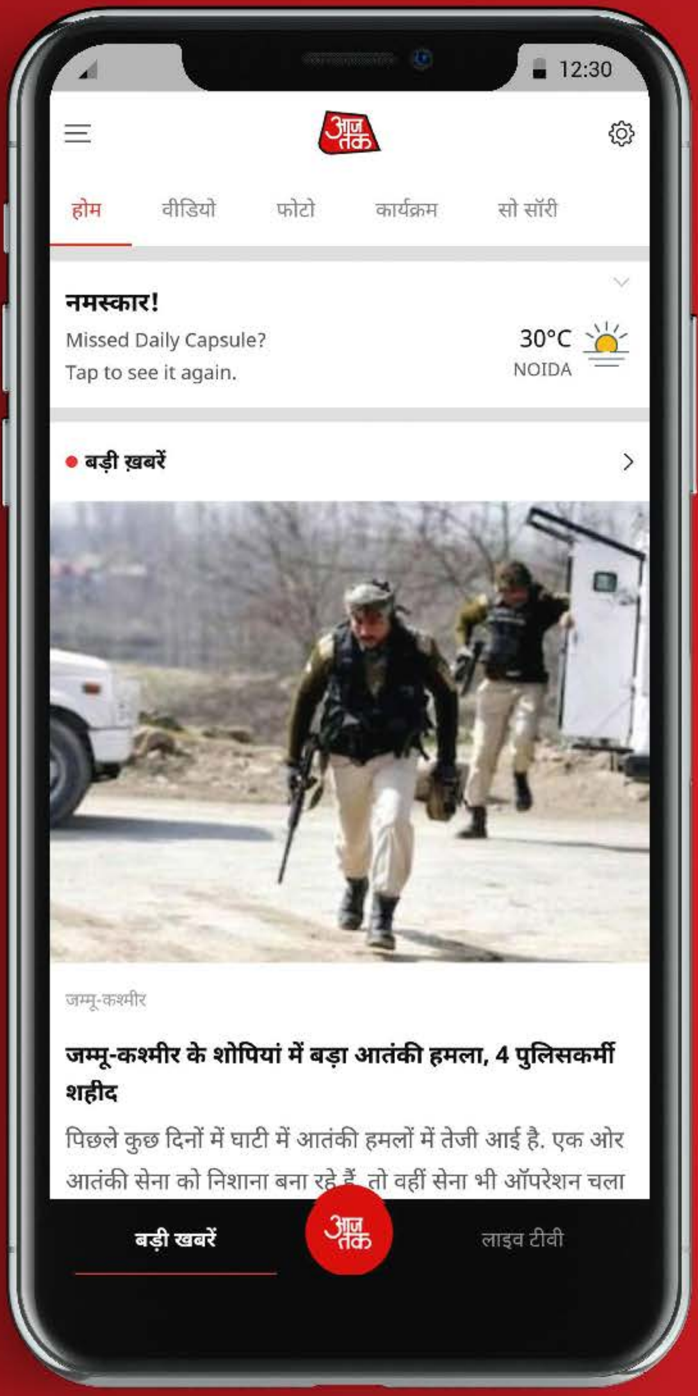
12:30
होम
वीडियो
फोटो
कार्यक्रम
सो सॉरी
बड़ी ख़बरें
बड़ी खबरें
लाइव टीवी

नमस्कार!
Missed Daily Capsule?
Tap to see it again.
30°C
NOIDA

जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में बड़ा आतंकी हमला, 4 पुलिसकर्मी शहीद

पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी हमलों में तेजी आई है. एक ओर आतंकी सेना को निशाना बना रहे हैं, तो वहीं सेना भी ऑपरेशन चला

IndiaContent

SEARCH FOR
EDITORIAL IMAGES
ENDS HERE